वैश्विक संवाद GLOBAL DIALOGUE

4.2

14 भाषाओं में एक वर्ष में 4 अंक

सूचना पत्र

International Sociological Association

समाजशास्त्र एक पेशे के रुप में

डोरोथी स्मिथ
हरबर्ट जान्स

समाजशास्त्र एवं राजनीति के मध्य

निकोलास लिंच
के साथ एक साक्षात्कार

यूक्रेन में विद्रोह

व्लोदिमिर पनिओट्टो
व्लोदिमिर इशचेंको

जलवायु परिवर्तन

युआन त्शै ली एवं
एंड्रयू वी–ची यांग,
हर्बर्ट डोसैना

चीन की वास्तविक क्रांति

फीझाहू झाऊ
योंगहोंग झांग
यिंग जिंग

> शक्ति की औपनिवेशिकता

> चियापास से : असमानता से सामना

> सीरिया की जेलों के अन्दर

> ईरानी महिलाओं का भविष्य

> यान जेपांस्की : पुलों का निर्माण

> पोलिश उच्च शिक्षा का नव्य–उदारवाद

> पोलिश विद्यार्थियों का खुला पत्र

> वैश्विक संवाद का टर्किश दल

अंक 4 / क्रमांक 2 / जून 2014
http://isa-global-dialogue.net

GD

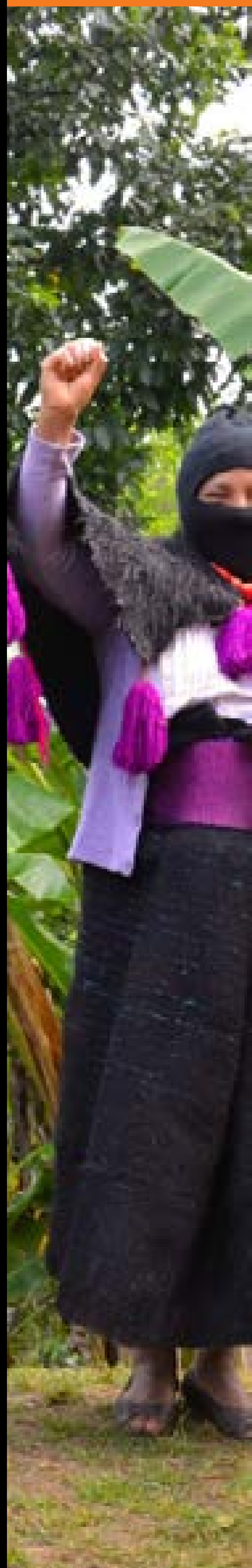

> सम्पादकीय

एक असमान विश्व से सामना

यह जुलाई में योकोहामा में होनें वाली समाजशास्त्र की आईएसए विश्व कांग्रेस, जिसमें कि 5,500 भागीदारों की कीर्तिमान उपस्थिति की सम्भावना है, से पहले का वैश्विक संवाद का अन्तिम अंक है। कांग्रेस का मुख्य विषय – एक असमान विश्व से सामना – इस शताब्दि का एक तेजी से बढता हुआ बडा मुद्धा बन रहा है। यहां तक कि अर्थशास्त्री भी इस क्षेत्र में – जिस पर कि कभी समाजशास्त्र को एकाधिकार था – झुण्डों के रुप में आ रहे हैं जैसा कि थामस पिकैटि की पुस्तक ''21वी शताब्दि में पूंजी (Capital in 21st Century) द्वारा पैदा की गई सनसनी के सार तत्व से स्पष्ट है।

वैश्विक संवाद के इस अंक का सामना भी एक असमान विश्व से हो रहा है। युआन ली एवं एंड्रयू यांग दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार वैश्विक उष्णता को उलटने का हमारा सामान्य हित हमें विभाजित करता है, एक बिन्दु जिसे हर्बर्ट डोसैना ने भी रेखंकित किया है। जलवायु परिवर्तन पर सम्पन्न यूएन कान्फ्रेन्स की रिपोर्ट के आधार पर वो हमें बतला रहे हैं कि किस प्रकार शक्तिशाली – अमेरिका के नेतृत्व में – अपने ''समाधान'' बाकी सब पर थोप रहे हैं और यह कह कर कि वो बाकी सभी के हित में भी हैं। बाकी सब इसे अस्वीकार करते हैं लेकिन अब तक वो कमजोर रहे हैं तथा विभाजित भी। इसे हम औपनिवेशिकता की शक्ति के संदर्भ में विचारणीय विषय के रुप में देख सकते हैं, जिसे कि सीजर जर्माना ने अनेक वैश्विक असमानताओं की जड के रुप में समझाया है। इसे हम यूक्रेन में कार्यरत देख सकते हैं – जैसा कि व्लोदि्मिर इशचेंको एवं व्लोदि्मिर पनिओट्टो के आलेखों से जाहिर होता है, जहां पर कि शीतयुद्ध के पुर्नजीवन ने अल्प–जनाधिपत्य शासन के विरुद्ध बागी आन्दोलन को विभाजित कर दिया एवं कुचल दिया।

राष्ट्रों के मध्य जितनी तेजी से असमानता में वृद्धि हुई है उसके मुकाबले में वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों मे असमानता के नहीं बढने के पीछे अर्द्ध–परिधीय देशों का विकास जैसे भारत एवं चीन है। लेकिन ऐसा किस कीमत पर? चीनी समाजशास्त्री फीझाहू झाऊ, यिंग जिंग तथा योंगहोंग झांग शंघाई एवं बीजिंग के चमकते किलों के परे जा कर ग्रामीण परिक्षेत्र जो कि नये शहरी परिदृष्यों में रुपान्तरित हो रहे हैं, जिन्हें कि कृषकों एव श्रमिकों की पीठों पर बनाया जा रहा है तथा कि जिन्हें अपनी भूमि से निष्काषित कर दिया गया है, नव कुलीनों की अकल्पनीय सम्पत्ति को पोषित किया है। जैसा कि हमें ज्ञात हो रहा है, कृषक इसे बिना किसी विरोध के स्वीकार नहीं कर रहें हैं, यद्यपि उनके प्रतिरोधों के विरुद्ध कठिनाईयां वाकई में काफी गहरी हैं।

''रोटी, आजादी, सामाजिक न्याय'' के नारों ने तीन वर्ष पूर्व मिश्र वासियों ने मुबारक की तानाशाही को उखाड़ फैंका था। प्रजातन्त्र से प्रयोग करने के बाद वो एक बार पुनः सेना के दमनकारी शासन का सामना कर रहे हैं। अरब बसन्त के वादे अन्य स्थानों पर भी चूर–चूर हो गये हैं। जैसा कि सीरिया में हो रहे गृहयुद्ध के कारण जोर्डन, लेबनान और टर्की में शरणार्थियों का तांता लगा हुआ है। जिन चीजों के बारे में कम ज्ञान है उनमें सीरिया की जेलों में होने वाले उत्पीड़न की विभीषिका सम्मिलित है, जिसे कि इस अंक में अब्दुलैह सईद ने वर्णित किया है। लेकिन इस क्षेत्र में सब कुछ उदासीपूर्ण ही नहीं है। ईरानी समाजशास्त्री शिरीन अहमद–निया ने 1979 की क्रान्ति के पश्चात महिलाओं के कल्याण में होने बाले नाटकीय सुधारों का वर्णन किया है। हम वहां तरक्की पाते हैं जहां इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी दौरान, पूर्वी यूरोप नवउदारवाद की जकडन में पडा हुआ है, जो कि अब उच्च शिक्षा में पहुचं रहा है जिसके कि पूर्वानुमानित परिणामों का वर्णन वारसॅा की लोक समाजशास्त्र की प्रयोगशाला द्वारा किया गया है। हमें एक बिल्कुल ही भिन्न युग की याद दिलाते हुऐ उन्होनें आईएसए के 1966 से 1970 तक रहे अध्यक्ष यान जेपांस्की का, जो कि ''एक मानवीय चेहरे के साथ समाजवाद'' के सच्चे उपासक हैं तथा उसके योद्धा हैं, एक गतिमान शब्दचित्र भी लिखा है।

डोरोथी स्मिथ, *प्रख्यात नारीवादी चिन्तक बतला रही हैं कि किस प्रकार उनका झुकाव नारीवाद की तरफ हुआ तथा किस प्रकार उन्होने समाजशास्त्र के प्रति अपना विशिष्ठ परिप्रेक्ष्य – संस्थागत नृवंशीयता, का विकास किया*

हरबर्ट जान्स, *अमेरिका के प्रतिष्ठित समाजशास्त्री सार्वजनिक समाजशास्त्र पर अपने विचारों को आगे बढाते हुए बतला रहे हैं कि हमे अपने भविष्य के प्रति खास तौर से चिन्तित रहना चाहिये।*

निकोलास लिंच, *पेरु के समाजशास्त्री एवं राजनीतिज्ञ, बतला रहे हैं कि किस प्रकार उन्होने एक अनिश्चित वामपंथी राजनीति एवं एक विद्वान के रुप में अपनी बहुसर्जक जीविका के मध्य जीवनपर्यन्त प्रक्षेप–पथ के साथ समझौता किया।*

> वैश्विक संवाद को आईएसए वैबसाइट पर 14 भाषाओं में देखा जा सकता है।
> प्रस्तुतियां (Submissions) burawoy@berkeley.edu पर प्रेषित की जा सकती हैं।

> Editorial Board

Editor: Michael Burawoy.

Managing Editors: Lola Busuttil, August Bagà.

Associate Editors:
Margaret Abraham, Tina Uys, Raquel Sosa, Jennifer Platt, Robert Van Krieken.

Consulting Editors:
Izabela Barlinska, Louis Chauvel, Dilek Cindoğlu, Tom Dwyer, Jan Fritz, Sari Hanafi, Jaime Jiménez, Habibul Khondker, Simon Mapadimeng, Ishwar Modi, Nikita Pokrovsky, Emma Porio, Yoshimichi Sato, Vineeta Sinha, Benjamín Tejerina, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Regional Editors

Arab World:
Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Brazil:
Gustavo Taniguti, Juliana Tonche, Andreza Galli, Renata Barreto Preturlan, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Rafael de Souza.

Colombia:
María José Álvarez Rivadulla, Sebastián Villamizar Santamaría, Andrés Castro Araújo, Katherine Gaitán Santamaría.

India:
Ishwar Modi, Rajiv Gupta, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Ritu Saraswat, Nidhi Bansal, Uday Singh.

Iran:
Reyhaneh Javadi, Najmeh Taheri, Hamidreza Rafatnejad, Faezeh Esmaeili, Saghar Bozorgi, Faezeh Khajezadeh.

Japan:
Kazuhisa Nishihara, Mari Shiba, Kousuke Himeno, Tomohiro Takami, Yutaka Iwadate, Kazuhiro Ikeda, Yu Fukuda, Michiko Sambe, Yuko Hotta, Yusuke Kosaka, Shuhei Naka, Kiwako Kase, Misa Omori, Kazuhiro Kezuka.

Poland:
Krzysztof Gubański, Emilia Hudzińska, Kinga Jakieła, Kamil Lipiński, Karolina Mikołajewska, Mikołaj Mierzejewski, Adam Müller, Przemysław Marcowski, Patrycja Pendrakowska, Zofia Penza, Konrad Siemaszko.

Romania:
Cosima Rughiniș, Ileana-Cinziana Surdu, Adriana Bondor, Ramona Cantaragiu, Ioana Cărtărescu, Miriam Cihodariu, Daniela Gaba, Mihai Bogdan Marian, Mădălin Răpan, Alina Stan, Elena Tudor.

Russia:
Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Elena Nikiforova, Asja Voronkova.

Taiwan:
Jing-Mao Ho.

Turkey:
Yonca Odabaş, Günnur Ertong, İlker Urlu and Zeynep Tekin.

Media Consultants: Gustavo Taniguti, José Reguera.

Editorial Consultant: Abigail Andrews.

> इस अंक में In This Issue

सम्पादकीयः एक असमान विश्व से सामना — 2

समाजशास्त्र एक पेशे के रूप में – संस्थागत नृवंशीयता की वंशीयता
डोरोथी ई स्मिथ, कनाडा — 4

समाजशास्त्र एक पेशे के रूप में – भविष्य की ओर एक दृष्टि
हरबर्ट, जे. जान्स, यू.एस.ए. — 6

> लैटिन अमेरिका से

समाजशास्त्र एवं राजनीति के मध्य
निकोलास लिंच के साथ एक साक्षात्कार — 8

शक्ति की औपनिवेशिकता : पेरू से एक परिप्रेक्ष्य
सीजर जर्माना, पेरू — 11

चियापास से : एक असमान विश्व से सामना
मार्कस एस. शुल्ज, यू.एस.ए. — 14

> मध्य–पूर्व से

सीरियाई जेल में
अब्दुलेह सईद, सीरिया — 17

ईरान में महिलाओं की संदिग्ध प्रगति
शिरीन अहमद–निया, ईरान — 19

> यूक्रेन में विद्रोह

यूरोमैदान : विद्रोह का पार्श्वचित्र
व्लोदि्मिर पनिओट्टो, यूक्रेन — 21

क्रांति जो अभी शुरू भी नहीं हुई है
व्लोदि्मिर इशचेंको, यूक्रेन — 24

> जलवायु परिवर्तन

मानवीय विकास रूपान्तरण
युआन त्सै ली एवं एंड्रयू वी–ची यांग, ताईवान — 26

बाजार पर निर्भर हमारा भाग्य
हर्बर्ट डोसैना, यू.एस.ए. — 28

> चीन में परिवर्तन एवं प्रतिरोध

चीनी नगरीकरण में नाटक एवं तबाही
फीझाहू झाऊ, चीन — 32

भूमि हथियाना और भ्रष्टाचार
योंगहोंग झांग, चीन — 34

विस्थापित आबादी के विरोध का आयोजन
यिंग जिंग, चीन — 36

> पौलैण्ड से

यान जेपांस्की – एक अनिश्चित पुल का निर्माण
एडम मुलर, कामिल लिपंस्की, मिकोलाज मिरजेवस्की, क्रिस्टोफ गुबान्स्की, कैरोलिना मिकोलायेवस्का, पौलैण्ड — 38

पोलिश उच्च शिक्षा पर नव्य–उदारवाद का कब्जा
डारियस जेमिलनियाक एवं कैरोलिना मिकोलायेवस्का, पौलैण्ड — 40

उच्च शिक्षा में सुधार के संदर्भ में एक खुला पत्र
सार्वजनिक समाजशास्त्र प्रयोगशाला, वारसॉ विश्वविद्यालय तथा क्राकोव के यागीलोनियन विश्वविद्यालय के आलोचनात्मक अनुभाग द्वारा — 42

वैश्विक संवाद का टर्किश दल — 44

> संस्थागत नृवंशीयता की वंशीयता

डोरोथी ई स्मिथ, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, कनाडा

डोरोथी स्मिथ

डोरोथी स्मिथ नारीवादी समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तित्व है। एक दृष्टि जिसे 'संस्थागत नृवंशीयता' कहा जाता है, दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यापक संदर्भों के साथ विशेषतः 'शासन के सम्बन्धों' में विद्यमान है। अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की वे लेखक हैं। यह लेखन उनके आधारभूतीय लेख 'सोशियोलोजी फार वीमेन' (महिलाओं के लिए समाजशास्त्र) से प्रारम्भ होता है। 'द एव्रीडे वर्ल्ड एज प्रोब्लेमेटिक : ए फैमिनिस्ट सोश्यालजी (1987)' उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 'द कन्सेप्चुअल प्रैक्टिसिज ऑफ पावर : ए फैमिनिस्ट सोशियोलोजी ऑफ नालेज (1990) एवं इन्स्टीट्यूशनल एथनोग्राफी : ए सोशियोलोजी फॉर पीपुल (2005) उनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अमेरिकन सोशियोलोजीकल एसोसियेशन एवं केनेडियन सोशियोलोजी एण्ड एन्थ्रोपोलोजी एसोसियेशन ने उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया है। उनकी प्रेरण ाा के कारण आइ एस ए में 'संस्थागत नृवंशीयता' पर एक वैचारिक समूह (टी जी 06) को निर्मित किया गया है।

एक पेशे के रूप में समाजशास्त्र विषय पर लिखना मेरे लिये कठिन कार्य है, मैं इस विषय के अन्तर्गत स्वयं के बौद्धिक जीवन और इस के साथ जुड़े अकादमिक क्रियाकलापों को सम्मिलित करने की कोशिश करूंगी। मैं एक पेशेवर समाजशास्त्री घटनावश या अनेक घटनाओं के क्रम के फलस्वरूप बनी। मेरे निजी इतिहास से जुड़ी घटनाओं एवं उसके बाद में दो सामाजिक आन्दोलनों की ऐतिहासिक घटनायें, जिनमें मैं सम्मिलित हुई और जिनके कारण मेरा सम्बन्ध संस्थागत समाजशास्त्र मे रूपान्तरित हो गया, इस संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

घटनाएं : मैं सन् 1952 में लन्दन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स (एल एस ई) में गयी क्योंकि मैं सचिवालयी कार्यों से उकता गयी थी। मेरा विचार था कि यदि मेरे पास विश्वविद्यालयी उपाधि हो तो मुझे कुछ अधिक रूचिकर कार्य करने की कुशलता मिल सकेगी। वहां मैंने समाज विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। बिल स्मिथ से मिली एवं उनसे विवाह किया। तत्पश्चात् मैं बिल स्मिथ के साथ चली गयी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में समाजशास्त्र में शोध डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश लिया हालांकि एल.एस.ई. में मेरी विशेषज्ञता सामाजिक मानव शास्त्र में थी।

बर्कले मेरे लिये एक (आमूल चूल परिवर्तनकारी) रूपान्तरणकारी अनुभव था। एल.एस.ई. में समाजशास्त्र को सीखने की उपलब्धता नहीं थी। दुरखाइम, मार्क्स, वेबर एवं अन्य सामाजिक विचारकों को पढ़ा एवं उन पर चर्चा हुई थी। हमने जनांकिकी, प्रजाति के जैनेटिक सिद्धान्तों की कल्पना सामाजिक दर्शन के व्यवहार मूलक पक्षों एवं आचार शास्त्रों पर चर्चा की एवं उन पर बहस की। बर्कले में मुझे यह जान कर धक्का लगा कि जिस कार्यक्रम की मैं विद्यार्थी थी वहां अच्छी ग्रेड (डिग्री) प्राप्त करने के लिए शिक्षक/अनुदेशकर्ता के विचारों को स्वीकारना होता था। मुझे यह भी जान कर धक्का लगा कि विश्वविद्यालय परिसर में से राजनीतिक बहसों को बाहर रखा गया था—वहां अब भी मैकआर्थी का दौर विद्यमान था।

यदि मैं पीछे/अतीत को देखूं, जब मैं सन् 1955 से सन् 1963 तक अपने स्नातक कार्यक्रम की विद्यार्थी थी, तो कह सकती हूं कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट पेशेवर विषय के रूप में विकसित तो

>>

किया जा रहा था परन्तु वह उस दौर के अस्पष्ट राजनीतिक अतीत से जुड़ा हुआ नहीं था। शिकागो वैचारिकी/सम्प्रदाय की विरासत से इसकी सम्बद्धता को हाशिये पर ला दिया गया था तथा परिवर्तित हो चुके एवं परिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्था जो कि मैकार्थी युग से उभार ले रही थी, बर्कले एवं अन्य स्थानों के समाजशास्त्री उन दिशाओं में व्यस्त होने लगे थे जो समाजवादी राजनीति (जो कि सी राइट मिल्स के कार्यों में विद्यमान थी) से सम्भावित सम्बन्धों को दबा सकें। टालकट पार्सन्स की पुस्तक 'द स्ट्रक्चर ऑफ सोश्यल एक्शन' अत्यन्त शक्तिशाली तरीके से एक ऐसे समाज विज्ञान की प्रभावी रचना कर रही थी जिसमें मार्क्स एवं मार्क्सवाद का कोई स्थान नहीं था। इस अवधि में समाज विज्ञान की पुनर्रचना में अनेक अवधारणाओं को पुनः निर्मित किया जा रहा था उदाहरण के लिए सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा में वर्ग की अवधारणा को बहुत पीछे छोड़ा जा चुका था अथवा व्यावसायिक कारपोरेशन्स के सामाजिक प्रभुत्व में हो रही वृद्धि के संदर्भ में उन्होंने संगठनात्मक सिद्धान्त की खाली तार्किकता (रैडीमेड, हालांकि बाद में इसे प्रबन्धन के द्वारा ग्रहण कर लिया गया) के विचार को विकसित किया।

घटनायें : सन् 1963 में एक सुबह मेरे पति हम लोगों को छोड़कर चले गये। हम लोगों की दो सन्तानें थी उनमें से एक सिर्फ नौ माह की थी। मेरे ऊपर अब दायित्व था कि मैं न केवल अपनी सन्तानों की देखभाल करूं अपितु अब मैं आय अर्जन का मुख्य स्त्रोत भी हो गयी थी। अतः मुझे लगा कि मुझे अब प्रकाशन क्षेत्र में आना चाहिए। मुझे अनुसंधान कार्य एवं लेखन से बहुत लगाव था परन्तु मैंने उसके प्रकाशन के विषय में नहीं सोचा और ना ही मुझे यह महत्वपूर्ण लगता था। पर अब मुझे इस विचार को परिवर्तित करना था। अब मुझे पेशेवर बनना था और वह मैंने किया।

सन् 1968 में कनाडा में स्थित ब्रिटिश कोलम्बिया विश्वविद्यालय में मुझे रोजगार मिला। मेरा सबसे बड़ा पुत्र जो उस समय 8 वर्ष का था के कारण मैंने कुछ सम्भावनाओं के बीच इस रोजगार को चुना (उन दिनों विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो रही थी) क्योंकि जब हमने वैन्कूवर का मानचित्र देखा तो हमने पाया कि पैनिनसुला (प्रायद्वीप) के उत्तर क्षेत्र में, जहां यह विश्वविद्यालय स्थित था, सड़कें नहीं थीं।

घटनायें : परन्तु दो वर्ष के अनुभव में मैंने पाया कि कानाडीकरण के आन्दोलन ने मुझ पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कानाडीकरण साहित्य एवं इतिहास में बहुत आगे था परन्तु कनाडा में समाजशास्त्री धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे थे। हमने यह भी खोजा कि हम वह समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं जो अमेरिका आधारित है, हां, उसमें कुछ ब्रितानी प्रभाव है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कनाडा में भी विशिष्ट एवं मौलिक समाज वैज्ञानिक थे पर हम जिस समाजशास्त्र को पढ़ा रहे थे उसमें वे सम्मिलित नहीं थे। मैंने इस तथ्य को मान्यता के रूप में स्वीकारा कि समाजशास्त्र जिसे मैं पढ़ा रही थी, का सम्बन्ध उस समाज से नहीं था जिसमें मैं वास्तव में रह रही थी। मेरे बर्कले प्रशिक्षण ने मुझे तैयार किया कि मैं रोमन शासन के प्रतिनिधि की तरह क्रियाशील होकर एक प्रान्तीय क्षेत्र में रोम के शासन को पुनः प्रस्तुत करूं।

इस समय तक एक कनाडियन नागरिक के रूप में, जो मैं हाल में बनी थी, मैं समाजशास्त्र के शिक्षक के रूप में कनाडियन समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र को प्रयुक्त कर रही थी। एलएसई में पढ़ते हुए मार्क्स एवं एंजिल्स का अध्ययन करते हुए मुझे यह याद रहा कि समाज विज्ञान की प्रतिबद्धता वास्तविक व्यक्तियों के साथ है इन व्यक्तियों के श्रम एवं इनके जीवन की स्थितियों से समाज विज्ञान की प्रतिबद्धता तो सुनिश्चित होती हैं। मैंने मार्क्स को दुबारा पढ़ा। मैंने यह खोजा कि सामाजिक प्रक्रियाओं की समझ की पद्धति के रूप में विचारधारा की आलोचना के पक्ष क्या हैं। एक समाजशास्त्री के रूप में अपनी सजग सम्बद्धता के कारण मैंने देखा एवं जाना कि जिस समाज में हम रहते हैं वह उस साम्राज्यवादी विवेचन से बिल्कुल भिन्न है जो समाजशास्त्र के स्थापित सिद्धान्तों, अवधारणाओं, विषय वस्तु विभाजनों एवं पद्धतिशास्त्रों से निर्मित हुआ है।

लेकिन फिर महिला आन्दोलन की स्थितियों ने मुझ में बदलाव किये। दो तीन वर्षों में मेरी सहभागिता ने मुझमें जो बदलाव किये वे मेरी समझ से विशिष्ट थे। ये मेरी समझ बर्कले में समाजशास्त्र के अध्ययन से विकसित हुई समझ से आमूलचूल रूप से भिन्न थी। ऐसे समाजशास्त्र का विकास जिसमें महिला विषय बन कर उभरे, एक लम्बे दौर में मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष बन गया। यह पूर्व में नहीं था पर ऐसा आवश्यक रूप से बनाना था ये पक्ष हमारे विचार विमर्श के केन्द्र बन गये। उनसे विमर्श होने लगा जिन्हें मैं पढ़ाती थी उन्होंने भी मेरे मत को स्वीकारा और उसे आगे बढ़ाया। हमें ये पता नहीं था कि हमारी ये खोज हमें किसी दिशा में ले जायेगी पर हम इस विमर्श के विस्तार के प्रति प्रतिबद्ध थे। जिसको हम अब 'संस्थागत नृवंशीयता' कहते हैं, वह इसी विमर्श से उभरी है साथ ही यह हमारे अनुसंधान, हमारी बातचीत एवं लेखन से सम्बद्ध खोज एवं अन्वेषण पर आधारित निरन्तर विचार विमर्श का भी उभार है। क्या यह समाजशास्त्र का एक प्रकार है? समाजशास्त्रीय पारम्परिक विद्या में अधीनस्थता के शब्द को समाजशास्त्रीय सिद्धान्त एवं पद्धति में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यह स्नातक डिग्री हेतु आवश्यक है। क्या यह एक पद्धतिशास्त्र है? नहीं यह पद्धति शास्त्र नहीं है। इसे अन्य समाजशास्त्र या एक वैकल्पिक समाजशास्त्र के रूप में देखा जा सकता है जो वास्तविक लोगों के अनुभवों के आधारभूत अवयवों के प्रति प्रतिबद्ध है, इसमें इन लोगों की क्रियाएं एवं ये क्रियाएं कैसी है, क्या ये क्रियाएं समन्वयमूलक हैं और ये कैसे व्यक्ति की स्थिति से परे सम्बन्धों के क्षेत्र में कितना विस्तार लेते हैं, के समस्त पक्ष सम्मिलित है। ये वे स्थितियां है जहां मैं कार्य करती हूं, अनुसंधान सम्बन्धी विचार विमर्श में सक्रिय रहती हूं जिसमें अन्य संस्थागत नृवंशीय शास्त्री सहभागिता करते हैं। इस प्रकार की खोज करना एक पेशा नहीं है अपितु यह निरन्तर चलने वाली आकर्षक क्रिया एवं प्रतिबद्धता मूलक सम्बद्धता है।

इसके बावजूद समाजशास्त्र निर्वचनात्मक एवं संस्थागत स्पेस प्रदान करती है जहां संस्थागत नृवंशीयता एक प्रमुख क्षेत्र है (यह क्षेत्र अन्य असम्बद्ध विषयों जैसे नर्सिंग में भी प्रवेश कर चुका है)। आज का समाजशास्त्र बाध्यतामूलक संगतता से जुड़ा हुआ नहीं है जिसे मैं भी अपने बर्कले प्रशिक्षण के दौरान हस्तान्तरित करने हेतु सीख रही थी। वे लोग जो समाज को ज्यादा सुसंगत तरीके से समझना चाहते हैं उन्हें विभिन्न दिशाओं को जानना जरूरी है। मैं यहां अनुसंधान एवं ऐसे दृष्टिकोण को केन्द्रित करने की इच्छुक हूं जो संस्थागत नृवंशीयता को ज्ञान के विकास के उद्देश्य से जोड़ते हैं और जो लोगों की समस्याओं एवं मुद्दों को जन मुद्दों में रूपान्तरित करते हैं जैसा कि सी. राइट मिल्स का विचार था। ■

> भविष्य की ओर एक दृष्टि

हरबर्ट जे. जान्स, कोलम्बिया विश्वविद्यालय, यू.एस.ए.

हरबर्ट जान्स

लगभग 50 वर्षों से **हरबर्ट जान्स** अमेरिका के अत्यन्त प्रभावी एवं सक्रिय समाजशास्त्री हैं। इस अवधि में उन्होंने नगरीय निर्धनता एवं निर्धनता विरोधी नियोजन, समानता एवं स्तरीकरण, नृवंशीयता एवं प्रजाति, नवीन मीडिया एवं लोकप्रिय/जन संस्कृति सम्बन्धी क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका का निर्वाह किया है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिसमें 'द अरबन विलेजर्स' (1962) 'द लेवी टावर्स' (1967), 'पाप्यूलर कल्चर एण्ड हाइ कल्चर' (1974), 'डिसाइडिंग व्हाट इज न्यू' (1979), 'द वार अंगेस्ट द पूअर : द अण्डरक्लास एण्ड एण्टी पावर्टी पालिसी' (1995) एवं हाल में प्रकाशित 'इमेजनिंग अमेरिका इन 2033' (2008) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह पुस्तक भविष्य के प्रति आशावादी विचार को स्थापित करती है। एक जन समाजशास्त्री के रूप में उन्होंने समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखा है। एक सामाजिक नियोजक के रूप में उन्होंने सार्वजनिक नीति विश्लेषण में सक्रिय सहभागिता की है। उन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अमेरिकन सोशियोलोजिकल एसोसियेशन के वे अध्यक्ष भी रहे हैं।

अन्य आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं की भांति अमेरिका एक नवीन एवं सम्भवतया दीर्घकाल तक चलने वाली आर्थिक असमानता के उभार का अनुभव कर रहा है जिसका परिणाम आगे चलकर राजनीतिक एवं वर्गीय असमानता में हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप समाजशास्त्रियों को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए कि वे एवं उनका विषय इन असमानताओं को समझने, विशेषतः सामाजिकीय परिवर्तन एवं उसकी सामाजिक कीमतें जो ये परिवर्तन लाने के इच्छुक है, में क्या भूमिका निभा सकता है।

पर इसके साथ ही सम्पूर्ण विषय को भी देश के लिए और अधिक समीचीन बनाने की आवश्यकता है और यदि ऐसा होता है तो विषय स्वयं में अधिक दृष्य एवं मूल्यवान हो जाता है। यद्यपि असमानताओं की वर्तमान वृद्धि वैश्विक है, पर राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थवादों में विभेद एवं राष्ट्रीय समाजशास्त्रों में विभेद इस तथ्य की तरफ संकेत देता है कि प्रत्येक देश को अपने उत्तर स्वयं खोजने होंगे जब तक कि वैश्विक प्रभाव/निहितार्थ एवं परिणामों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ है कि एक अमेरिकन समाजशास्त्री की कोशिश संकेत करे कि एक विस्तृत परिदृश्य क्या है, अथवा आपकी दूर दृष्टि क्या होगी यदि आपको अवसर मिले कि अमेरिकन समाजशास्त्र को किस दिशा में नेतृत्व लेना चाहिए।

असमानताओं के मापन से सम्बद्ध अच्छे अध्ययन हर क्षेत्र में हो ही रहे हैं पर समाजशास्त्र के लिए आवश्यक है कि वह अमेरिका की संस्थाओं एवं लोगों पर असमानताओं के प्रभावों में सक्रिय रूचि ले। असमानताओं के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों के सूक्ष्म समानशास्त्रीय पक्षों को उभारने के लिए हमें तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमने अब तक उतना नहीं दिया है। जहां तक सम्भव हो समाजशास्त्रीय अनु–संधान नीति–अभिमुखित होने चाहिए। यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वास्तविक नीति निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ जावे क्योंकि यह पक्ष अनेक समाजशास्त्रियों की विशेषज्ञता के परे है। तथापि वे ऐसे अनुसंधानों को आयोजित कर सकते हैं जो नीतियों की वकालत करने वालों, नीति निर्माताओं, विश्लेषकों एवं असमानता से सम्बद्ध सार्वजनिक नीतियों के आलोचकों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का उत्तर देने में सहायता कर सकें।

>>

चूंकि अर्थशास्त्री एवं राजनीतिशास्त्री अब भी देश के अभिजनों से जुड़े मुद्दों का परीक्षण करने में व्यस्त हैं, समाजशास्त्र को गैर–अभिजन पर अपने ध्यान को गहन करने की आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसे अनुसंधान कार्य करने अपेक्षित हैं जो कमजोर श्रेणी के अमेरिकन्स के विषय में हैं विशेषतः वे अमेरिकन जो माध्यका आय की जनसंख्या है। यह जनसंख्या अन्यों की तुलना में बढ़ रही असमानता से अधिक परेशान है। इनमें वे जनसंख्या श्रेणियाँ सम्मिलित हैं जो राजनीति में और राजनीति के द्वारा कम से कम प्रतिनिधित्व को व्यक्त करती हैं और सार्वजनिक विमर्श में स्थान नहीं पाती हैं। ऐसी श्रेणियों पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

समाजशास्त्र इन जनसंख्याओं के विषय में कुछ बोल तो नहीं सकता परन्तु अधिक अनुसंधानों को संचालित कर इनकी समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कर सकता है। ये अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण असमानताओं की सामाजिक, भावनात्मक एवं अन्य कीमतों पर अधिक केन्द्रित करने चाहिऐं। उदाहरणार्थ पिछले अनेक दशकों विशेषतः पिछले कुछ वर्षों में अधोगामी गतिशीलता में आश्चर्य जनक रूप से तीव्र वृद्धि हुई है, उर्धगामी गतिशीलता के ह्रास ने कुंठाओं एवं अपेक्षाओं के क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि एवं तीव्र कमी की है। समाजशास्त्रियों को बहुत पहले से ही अधोगामी गतिशीलता की प्रक्रियाओं एवं उसके प्रभावों को अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र बनाना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रियों को अत्यधिक निर्धनता के दीर्घकालिक प्रभावों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यह परिकल्पना जो सुझाव देती है कि एक प्रभाव इस अत्यधिक निर्धनता के पीड़ादायक अनुभवों से उत्पन्न वह असंतुलन है जो अनेक पीढ़ियों तक निरन्तर जारी रहता है। इसके साथ ही अनुसंधानकर्ता को यह समझना चाहिए कि निर्धनता के विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न अधोगामी गतिशीलता का प्रतिरोध एवं इसके विरूद्ध संघर्ष लोग किस प्रकार करते हैं और इन सबका समाधान कैसे करते हैं। यदि पर्याप्त एवं उपयुक्त प्रारूप से इन अध्ययनों को किया गया है तो नीतियों के संदर्भ में अनेक संकेत दिये जा सकते हैं और इस आधार पर राजनीति सहायता हेतु कदम उठा सकती है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि माध्यका आय की जनसंख्या से नीचे की जनसंख्या को उन शक्तियों, संस्थाओं एवं अभिकरणों से परिचित कराया जावे, जो उन्हें इस स्थिति पर लाने और उन्हें और गरीबी की तरफ ले जाने हेतु जिम्मेदार हैं। समाजशास्त्र के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। असमानता वृद्धि को उत्पन्न करने वाली शक्तियों का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इस असमानता वृद्धि के शिकार लोगों का अध्ययन है।

इसके साथ ही समाजशास्त्रियों को अपने विषय की सामाजिक उपयोगिता को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में विद्यमान महत्वपूर्ण मुद्दों, प्रघटनाओं एवं विवादों के विषय में उपयुक्त विचार एवं अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों की प्रस्तुति के आधार पर यह किया जा सकता है। हालांकि यह करने से कहना सरल है कि समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्रीय 'साहित्य' में योगदान एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध चिन्ताओं पर कम ध्यान देना चाहिए। ऐसे कुछ अध्ययन जो अनावश्यक रूप से पहले से ज्ञात ज्ञान का विस्तार करते है, एक स्तर तक सहायता भी करते हैं।

समाजशास्त्रियों को उन समस्याओं के अन्वेषणों को जारी रखना चाहिए जिन्हें अन्य समाज विज्ञान या तो उपेक्षित करते हैं अथवा उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देते। समाज शास्त्रियों को ऐसे अनुसंधान अधिक करने चाहिए जो समाज के हाशिये पर आ चुके पक्षों के विषय में हैं और अन्य अनुसंधानकर्ताओं के लिए या तो वे अरूचिकर हैं अथवा उनसे ये पक्ष छिपे हुए हैं।

जब भी सम्भव हो, समाजशास्त्रियों को आनुभाविक अध्ययनों, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक अनुसंधानों को वरीयता देनी चाहिए। व्यापक स्तरीय प्रदत्तों की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद समाजशास्त्र विषय को लघु स्तरीय प्रदत्तों के संकलन एवं विश्लेषण पर अपने बल को जारी रखना चाहिए। यह संकलन व विश्लेषण विशेष रूप से नृवंशीय क्षेत्र–अध्ययनों द्वारा किया जा सकता है। लोगों के साथ द्वारा, समूहों एवं संगठनों के माध्यम से समाज को समझने हेतु समाजशास्त्रीय अध्ययन हमारे वे विशिष्ट योगदान हैं जो अमेरिका से सम्बद्ध अमेरिकन ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

समाज शास्त्र विषय को नवाचारी एवं साहसिक सिद्धान्त रचना को भी अपना उद्देश्य बनाना चाहिए तथा ऐसे प्रारूप एवं परिप्रेक्ष्यों को सामने लाना चाहिए जो परिपाटीय ज्ञान को सवालों के घेरे में लें उदाहरण के लिये अतीत में आरोपीकरण का सिद्धान्त एवं हाल ही में सम्बन्धमूलक एवं रचनावादी सिद्धान्त। हाल में असमानताओं की वृद्धि से उत्पन्न परिवर्तन हमें प्रेरित कर सकते हैं कि अमेरिकन समान को विभिन्न अछूते एवं अच्छे तरीकों से समझा जावे।

इन सबसे ऊपर समाजशास्त्र को गहन प्रयास करने चाहिए कि वह सामान्य जनता तक पहुंच सके इस हेतु नवीन समाजशास्त्रीय विचार एवं निष्कर्षों को गैर–प्रविधिक अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करना आवश्यक है जो जनता के लिए रूचिकर हों। स्नातक स्तर एवं हाई स्कूल विद्यार्थियों को पढ़ाना हमारा मुख्य दायित्व है जिसे आज सार्वजनिक/जन समाजशास्त्र कहा जाता है परन्तु साथ ही समीचीन अनुसंधान सामान्य जनता हेतु उपलब्ध होने चाहिए। अनुसंधान कर्ता को केवल यह नहीं आना चाहिए कि लेखन कैसे करें अपितु उन्हें सार्वजनिक/जनसमाजशास्त्र की भाषा के लिए प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए चाहे भले ही वे आधारभूतीय एवं पेशेवर समाजशास्त्र के लिये प्रशिक्षित हो चुके हों। इसके साथ ही उन समाजशास्त्रियों को, जो जन/सार्वजनिक समाजशास्त्र को विस्तार देते हों, समान पद, प्रस्थिति एवं पुरस्कारों हेतु योग्य माना जाना चाहिए जो मूल अनुसंधानकर्ताओं को उनके योगदान के कारण प्राप्त होते हैं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त विचार भविष्य की प्रस्तुति/रूपरेखा के विषय में एक व्यक्ति के विचार हैं परन्तु यह इस आशा के साथ लिखे गये हैं कि अन्य इन विचारों में कुछ और वैचारिक वृद्धि सम्बन्धी सुझाव देंगे। समाजशास्त्र विषय के लिए यह आवश्यक है कि इसके भविष्य के बारे में अब और अधिक सोचा जावे ताकि भविष्य की घटनाओं के विषय में, जो कभी वर्तमान बनेंगी, एक दृष्टिकोण अधिक कुशलता के साथ सामने आ सके। ■

> समाजशास्त्र एवं राजनीति के मध्य

निकोलास लिंच के साथ एक साक्षात्कार

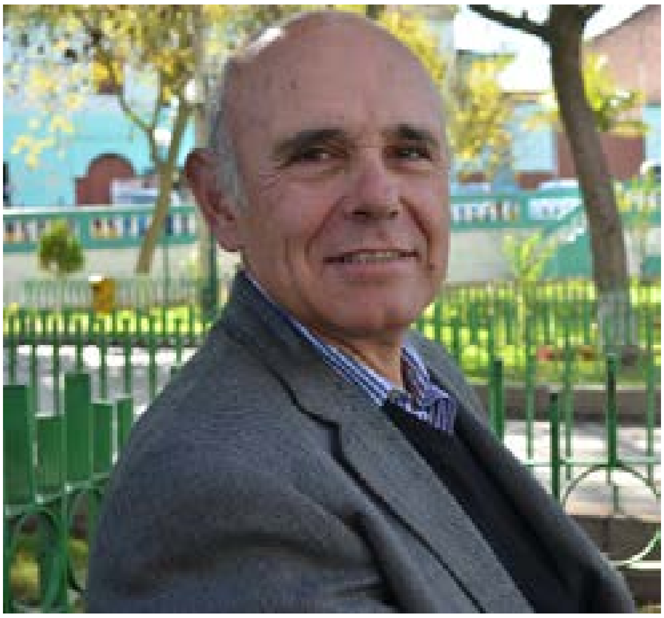

निकोलास लिंच

निकोलास लिंच लीमा, पेरू में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेन मार्कोस में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वे पेरूवियन कॉलेज ऑफ सोशियोलोजिस्ट्स (1998–2000) के अध्यक्ष तथा पेरू के शिक्षा मन्त्री (2001–2002), पेरू गणतन्त्र के राष्ट्रपति के सलाहकार (2002) व अर्जेन्टीना में पेरू के राजदूत (2011–2012) रहे हैं। न्यू स्कूल फॉर सोश्यल रिसर्च न्यूयार्क से पी. एच. डी. एवं लेटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ सोश्यल साइंसेज, मैक्सिकों से एम.एम. की उपाधि प्राप्त निकोलास लिंच अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अनेक अकादमिक लेखों एवं अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है जिनमें लास जाविनिस रोजोज ड सेन मार्कोज (द रैड यूथ ऑफ सेनमार्कोज) ला ट्रांसिसिआन कर्न्जवाडोरा (द कन्जर्वेटिव ट्रांजिसन), उना ट्रेजिडिया सिन हीरोज (ए ट्रेजेडी विदाउट हीरोज), एल पेन्सामिनाटो आर्काइको इन ला एड्यूकासिउन पेरूअना (आर्काइक थिंकिंग इन पेरूवियन एज्यूकेशन), लास आल्टिमोज ड ल क्लोस (द वर्स्ट आफ एज्यूकेशन), क्यू एस सर ड इज्क्यूश्डा (व्हाट इज इट मीन टु बी ए लैफ्टिस्ट) एवं एल आग्यूमेण्टो, डिमोक्रेटि को सोबर अमेरिका लेटिना (द डेमोक्रेटिक आरग्यूमेण्ट एबाउट लेटिन अमेरिका) मुख्य है, लीमा समाचार पत्र ला रिपब्लिका में वे चौदह वर्षों तक राजनीतिक स्तम्भकार रहे हैं तथा राजनीतिक विश्लेषण के ब्लाग के वे सम्पादक हैं जिसका नाम ओट्रा मिरान्डा (एनादर व्यू) है।

एम. बी. : एक समाजशास्त्री के लिए आपका करियर बहुत असाधारण है आप राजनीति के अन्दर एवं बाहर रहे हैं। वास्तव में सम्भवतया हमें साक्षात्कार इस प्रश्न से प्रारम्भ करना चाहिए कि क्या आप एक राजनीतिज्ञ हैं अथवा एक समाजशास्त्री?

एन. एल.: मैं एक समाजशास्त्री हूं इसलिए नहीं कि मैंने इसमें प्रशिक्षण लिया है अपितु इस लिये भी कि मैं समाजशास्त्र से प्यार करता हूं। मैं एक ऐसा समाजशास्त्री हूं जिसे राजनीति अच्छी लगती है। लेकिन तथ्य यह है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ जहां सामाजिक परिवर्तन जीवन एवं मृत्यु से जुड़ा हुआ था अतः मैंने किशोरावस्था से ही राजनीति में प्रवेश कर लिया।

एम. बी. : यह एक रूचिकर उत्तर है। मैक्स वेबर एक आकांक्षी राजनीतिज्ञ थे लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देखा और इसे राजनीति से पृथक किया। पर, जैसा मैं पा रहा हूं, आपके विषय में ऐसा नहीं है। क्या मैं सही हूं?

एन. एल.: मेरे लिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है पर यह एक समाज विज्ञान है। हम सामाजिककर्ता हैं जो विश्व का भाग भी हैं और हम इन सब का अध्ययन करते हैं। एलेन ट्यूरिन, जैसे समाजशास्त्री जो लेटिन अमेरिका में काफी प्रभावी हैं, इस पक्ष को रेखांकित करते हुए ''कर्ता का समाजशास्त्र'' की चर्चा करते हैं। मेरे मतानुसार ट्यूरिन का यह विचार सही था। प्रारम्भ से ही मेरे समाजशास्त्री अनुसंधान मेरे राजनीतिक जीवन से सम्बन्धित रहे हैं। मेरी अधिकांश पुस्तकें यही दर्शाती हैं।

एम. बी. : अब हम राजनीति में आपकी हाल ही में हुई सहभागिता की चर्चा करें। आप अर्जेन्टीना में पेरू के राजदूत बने। ये कैसे हुआ?

एन. एल.: सन् 2009 के अन्त में मैं राष्ट्रपति हुमाला की चुनावी टीम का भाग बना। मुझे इस टीम में मेरे कुछ उन मित्रों ने आमन्त्रित किया जो सन् 2006 के चुनाव में उनके साथ सहभागिता कर चुके थे। सन् 2006 के चुनाव में प्रभावी प्रचार के पश्चात् हुमाला दूसरे स्थान पर आये। किसी के साथ सम्बद्ध होने की व्यग्रता को मैं रोक रहा था क्योंकि हुमाला स्वयं को वामपन्थी राष्ट्रवादी के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे पर साथ ही वे एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी थे जिन्होंने सैन्ड्रियो ल्यूमिनो सो (चमकदार रास्ता) के विरूद्ध ''डर्टी वार'' में भाग लिया था। परन्तु सन् 2006 के उस चुनाव में समाजवादी वामपन्थियों के खराब परिणामें ने मुझे एवं मेरे मित्रों को प्रेरित किया कि मैं हुमाला का साथ दूं। आज जब मैं इन सब घटनाओं को देखता हूं तो सोचता हूं कि मेरी मूल प्रवृत्ति सही थी लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि प्रारम्भ से ही हमें धोखा दिया जा रहा था। सभी, हुमाला एवं उनकी पत्नी अपने लाभ के लिए शक्ति पाने के इच्छुक थे।

एम. बी. : अतः आपके द्वारा दिये समर्थन के प्रत्युत्तर में, जो हुमाला को चुनाव प्रचार के दौरान मिला, राष्ट्रपति हुमाला ने अर्जेन्टीना में राजदूत पद

>>

का आपको प्रस्ताव दिया। ब्यूनस आयर्स में वे आपसे क्या करवाना चाहते थे?

एन. एल.: राष्ट्रपति हुमाला ने अनेक राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मुझे अर्जेन्टीना भेजा। पेरू के अर्जेन्टीना से सम्बन्ध अच्छे नहीं थे क्योंकि हमाला के पूर्व की सरकार (अलान गार्सिया के नेतृत्व में अपरा पार्टी) अर्जेन्टीना सरकार को पसन्द नहीं करती थी क्योंकि इनकी नीतियां प्रगतिशील राजनीतिक दृष्टिकोण की थीं। राष्ट्रपति ने सम्बन्धों को सुधारने का लक्ष्य मुझे दिया जो कि मैंने किया। यह 'साउथ अमेरिकन इन्टीग्रेशन' एवं यू.एन.ए.एस.यू.आर. (दक्षिण अमेरिकी एकीकरण तथा दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रों के संघ (द यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन्स)) की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हुमाला ने मुझे कहा कि पेरू को एकता के मानचित्र पर लाया जाय और मेरी भूमिका का भी यही लक्ष्य था।

एम. बी. : इस पद के सम्मुख चुनौतियां एवं आपको मिले सन्तुष्टि के स्तर क्या थे?

एन. एल.: पहला, ब्यूनस आयर्स में जीवन, विशेषतः सांस्कृतिक एवं बौद्धिक जीवन, लेटिन अमेरिका में सम्भवतया सर्वाधिक समृद्ध है। इसके साथ ही अर्जेन्टीना सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन की महत्व पूर्ण प्रक्रियाओं से गुजर रहा था जो कि उसकी मजबूत राजनीतिक परम्पराओं के संदर्भ में विशेष रूप से रूचि का विषय थी। सम्पत्ति के पुनर्वितरण, मानवाधिकार एवं विश्व की ताकतों से स्वतन्त्रता के संदर्भों में अर्जेन्टीना ने बहुत सराहनीय विकास किया है। अन्य लातिन अमेरिकन देशों की तुलना में अर्जेन्टीना में औपचारिक नौकरियों के क्षेत्र में रोजगार का स्तर सबसे ऊंचा है, साथ ही श्रमिकों को श्रम अधिकारों की प्राप्ति है। लातिन अमेरिका में यह असामान्य है, पर यह सच है कि अर्जेन्टीना सरकार ने 1970 के दशक में दमन के दोषी सैन्य कर्मियों, जिनकी संख्या लगभग 200 है, को कारागार में डाल रखा है। इन सब परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, अर्जेन्टीनी नागरिकों ने नागरिकता की एक मजबूत भावना विकसित की है जो कि क्षेत्र के अन्य भागों में सम्भवतया अनुपस्थित है।

एम. बी. : परन्तु यह सब अचानक समाप्त हो गया, मैं सही कह रहा हूं, आपका पद अचानक आपसे ले लिया गया?

एन. एल.: ठीक कह रहे हैं आप। हुमाला सरकार जो वामपन्थी दृष्टि के अभियान से चुनी गयी थी और जिसमें मैंने योगदान किया था, दक्षिणपन्थ की तरफ अग्रसर हो गयी। हालांकि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह एक लम्बी प्रक्रिया थी। पहले हुमाला ने अपने मन्त्रि–मण्डल से प्रगतिशील लोगों को निकाल बाहर किया। तत्पश्चात् वामपन्थी प्रतिनिधियों (कांग्रेस मैन) से सम्बन्ध विच्छेदित किये एवं अन्त में जो भी प्रगतिशील पृष्ठभूमि के लोग थे, के साथ सम्बन्ध विच्छेदित कर लिये। पेरू की दक्षिण पन्थी ताकतों एवं अमेरिकन सरकार के दवाबों के प्रतिरोध के स्थान पर हुमाला सरकार ने रूपान्तरण के अपने लक्ष्य का त्याग कर दिया एवं पूर्व के बीस वर्षों से चले आ रहे नव्य उदारवादी प्रारूप को जारी रखा। जैसे ही हुमाला सरकार दक्षिण पन्थ की तरफ मुड़ी, राष्ट्रपति के नवीन सहयोगी मुझसे मुक्ति पाना चाहते थे और उन्होंने मुझे हटाने की रूपरेखा बनायी। यह मेरी गलती हो सकती है कि मुझे पहेल त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। पर इस तरह की जटिल राजनीतिक स्थितियों में उपयुक्त निर्णय को क्रियान्वित करना बहुत कठिन हो जाता है।

एम. बी. : उन्होंने आपको हटाने हेतु क्या रूपरेखा बनायी थी?

एन. एल.: जनवरी, 2012 के अन्त में ब्यूनस आयर्स में स्थित पेरू के दूतावास में पेरू नागरिकों के एक समूह से मुझे पत्र प्राप्त हुआ। यह समूह आतंकवादियों के संगठन के एक राजनीतिक समूह मोवाडेफ को वैधानिकता प्रदान करने के लिए प्रचार कर रहा था। 'द शायनिंग पाथ' अपने उन नेताओं के लिए सामूहिक क्षमा दान की मांग कर रहा था जो अपने अपराधों के कारण कारावास की सजा भुगत रहे थे। इस पत्र के आधार पर दस महीने बाद, नवम्बर के प्रारम्भ में एक दक्षिण पन्थी समाचार पत्र ने मुझे मोवाडेफ का समर्थक बता कर मेरी भर्त्सना की तथा मांग की कि मुझे मेरे इस पद से हटाया जाय। सरकार ने न तो मेरा बचाव किया और न ही किसी जांच के आदेश दिये। दक्षिण पन्थियों की आक्रामक शैली से इतने भयभीत थे कि उन्होंने मेरे त्याग पत्र की मांग की। हालांकि मेरा 'मोवाडेफ' अथवा 'द शायनिंग पाथ' से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा। वास्तव में सन् 1982 में 'द शायनिंग पाथ' ने मुझे एक पत्र लिख कर मेरी हत्या की धमकी दी थी और उस समय इस संगठन ने मेरे अनेक मित्रों की हत्या भी की थी। यह एक आतंकवादी समूह है जो अपनी क्रियाओं की स्व–आलोचनाओं को कभी भी नहीं स्वीकारता है। इस भ्रामक एवं असत्य आरोप के बावजूद सरकार में अन्दर एवं बाहर सक्रिय दक्षिण पन्थी समूह इतने शक्तिशाली थे कि वे सरकार से मुझे बाहर करने के निर्णय को सुनिश्चित करालें।

एम. बी. : अच्छा, मैं अब समझ सकता हूं कि पेरू में राजनीति कितनी असुरक्षित एवं खतरनाक हो सकती है। पर यह पहली बार नहीं था कि आप सरकार का हिस्सा थे। सन् 2001 में टोलेडो सरकार में आप शिक्षा मन्त्री थे। इस सरकार ने पेरु में लोकतन्त्र की पुनः स्थापना का प्रयास किया था। मुझे इस बारे में कुछ और भी बताइये।

एन. एल.: यह फ्यूजीमोर की तानाशाही के विरूद्ध संघर्ष का परिणाम था। मैं 'फोरो डैमोक्रेटिको' जो कि एक नागरिकीय संगठन था और जिसने इस सत्ता को उखाड़ने के लिए बने एक व्यापक गठबन्धन के हिस्से के रूप में सक्रियता निभायी थी। टोलेडो जो कि उदारवादी पृष्ठभूमि के मध्यमार्गी थे, ने उस समय पेरू राज्य के लोकतान्त्रिक दौर की नवीन शुरूआत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों को साथ लेकर अपने पहले मन्त्रिमंडल का गठन किया।

मेरा उद्देश्य उस समय शैक्षणिक सुधारों को प्रारम्भ करना था जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था, जो उस समय इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा दयनीय अवस्था में थी, में उन्नयन हो सके। यह व्यवस्था बहुत कम बजट प्रावधानों से संचालित होती थी एवं इसके परिणाम बहुत निम्न प्रकृति की गुणवत्ता वाले थे। मुझे इस क्षेत्र में दो शत्रुओं का सामना करना पड़ा, पहला विश्व बैंक एवं दूसरा शिक्षकों की माओवादी ट्रेड यूनियन (शिक्षक संघ)। पहला शत्रु सब कुछ का निजीकरण करना चाहता था और दूसरा शत्रु किसी भी कीमत पर सेवा सुरक्षा चाहता था और अपने सदस्यों के कार्यों के मूल्यांकन को अवरूद्ध करता था। हम राजनीतिक क्षेत्र में तो सुधार लाने में सफल रहे अतः उन्होंने मुझे एवं मेरे समूह के सदस्यों को हटा दिया।

एम. बी. : मेरी दृष्टि में इस प्रकार की राजनीति एक विश्वासघाती व्यवसाय है विशेषतः इसलिये कि आपने कभी वामपंथी दृष्टिकोण को नहीं नकारा। इस संदर्भ में क्या समाजशास्त्र ने आपको ऐसा कोई सहारा नहीं दिया कि आप विचलित नहीं हुए? क्या इस प्रकार की अनिश्चितता के दौर में समाजशास्त्र ने आपको कोई सान्त्वना प्रदान की? क्या यह आपकी राजनीति में भी कुछ योगदान करती है? क्या समाजशास्त्र अन्य साधनों के आधार पर स्वयं में एक राजनीति है?

एन. एल.: यह केवल एक सांत्वना मात्र नहीं है। समाजशास्त्र ने पेरु के समाज को समझने में मेरी सहायता की एवं पेरू को उस क्षेत्र एवं विश्व में स्थापित किया। उदाहरणार्थ जहां तक शिक्षा का सवाल है, समाजशास्त्र ने पेरू की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं को समझने में सहायता की। यह जाना कि ये समस्याएं विचारधारायी एवं राजनीतिक

>>

हैं। ये तकनीकी नहीं है जैसा कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण हमें विश्वास दिलवाना चाहते हैं। समाजशास्त्र ने मुझे वे उपकरण दिये जिनसे मैं यह समझ सका कि शिक्षा की गुणवत्ता केवल अच्छी ग्रेड से सम्बन्धित मुद्दा नहीं है अपितु विश्व में आपके स्थान के विषय में सामूहिक स्व–बोध का आव्हान करता है तथा जुड़ाव की भावना को महत्व देता है। मैंने कभी भी शैक्षणिक दायित्व नहीं छोड़े। मैं पेरू के सबसे पुराने एवं सबसे प्रसिद्ध सैन मार्कोज विश्वविद्यालय में 34 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। इन वर्षों में मैंने नौ बड़ी शोध परियोजनाओं में सहभागिता की है। इन परियोजनाओं के परिणामों को केन्द्र बना कर मैंने कुछ पुसतकों का लेखन किया है। हां कुछ पुस्तकें अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है कुछ तुलनात्मक रूप से अधिक राजनीतिक हैं एवं कुछ तुलनात्मक रूप से अधिक समाजशास्त्रीय हैं।

एम. बी. : आपकी कुछ ही पुस्तकों का अनुवाद हुआ है अतः यदि आप इन शोध परियोजनाओं के विषय में कुछ बता सकें या कम से कम ऐसी एक या दो परियोजनाओं के विषय में बता सकें जो आपकी दृष्टि में अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं और राजनीतिक से जुड़ी हुई हैं।

एन. एल.: ठीक है। मेरी पुस्तकों की अंग्रेजी भाषा में अनुपस्थिति का कारण अमेरिकन अकादमी से मेरे जटिल सम्बन्धों का होना है। उदाहरण के लिए लोकप्रियता वाद से सम्बन्धित मेरे अध्ययन को ले लें। 1990 के दशक के अन्त में लातिन अमेरिका में लोकप्रियतावाद के विषय में लिखते हुए मैंने इस विवेचना का प्रयास किया कि क्यों लोकप्रिय नव्य उदारवाद टिक नहीं पाया क्योंकि इस अवधारणा में ही अन्तः विरोध थे। मैंने लिखा कि ऐतिहासिक दृष्टि से लोकप्रियता वाद क्षेत्र के लिए व लोकतन्त्र के लिए अच्छा था। स्पेनिश भाषा में प्रकाशन के बाद मैंने इसे अमेरिका की एक महत्वपूर्ण ''तुलनात्मक'' शोध पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजा। महीनों के उपरान्त मुझे इस विषय में एक लम्बी टिप्पणी प्राप्त हुई जिसमें मुझे यह बताया गया कि मैं नहीं जानता कि लोकप्रियतावाद क्या होता है। ठीक है मेरी दृष्टि उनकी दृष्टि की तुलना में भिन्न है। लेकिन समस्या यह थी उस शोध पत्रिका ने एक आलेख को प्रकाशित किया जिसमें मेरे स्पैनिश भाषा के लेख को उद्धरित करते हुए मेरी आलोचना की गयी थी। अर्थात् मेरा लेख प्रकाशन की दृष्टि से तो उपयुक्त नहीं था परन्तु आलोचना की दृष्टि से उपयुक्त था। अनेक बार मुझे समान प्रकार की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। यदि आप असहमत हैं तो आप को पता नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं।

मेरी हाल में प्रकाशित पुस्तक में लातिन अमेरिकन लोकतन्त्र में सिद्धान्त एवं व्यवहार के पक्षों को केन्द्र में रख कर विभिन्न उपागमों का उल्लेख किया गया हैं। मैंने इस लेखन में विवेचना का प्रयास किया है कि क्षेत्र में विभिन्न सरकारें–हयूगो शावेज, लूला, कोरिया, इवो मोरालेस एवं किर्चनर्स–किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के लोकतन्त्र को विकसित करने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने किस प्रकार पुनर्वितरण, सामाजिक न्याय एवं सहभागिता को आगे बढ़ाया। इस पुस्तक का उद्देश्य लोकतान्त्रिक सत्ता से लेकर प्रभुत्वशाली सत्ता के विषय में विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करना है। विभिन्न प्रकार की ये सत्ता प्रणालियां संक्रमण एवं समेकन के विमर्श के फलस्वरूप उभरीं।

एम. बी. : अब क्या वे माध्यम उपस्थित हैं जिनसे आपका समाजशास्त्र राजनीतिक विवाद में प्रवेश करता है?

एन. एल.: हां, ऐसे माध्यम विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ पिछले कुछ महीनों से पेरू में मध्य वर्ग के विषय में एक बहस चल रही है। नव्य उदारवादी एवं जनमत का निर्माण करने वाले व्यवसाइयों का मत है कि पेरू की 70 प्रतिशत जनसंख्या मध्यवर्गीय है। यह तर्क एक विचित्र किस्म की आय वितरण सारणी पर आधारित है। अतः हम कुछ मित्र मिल कर एक बार फिर अनेक वर्षों बाद सामाजिक संरचना, सामाजिक वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के विषय में लिख रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि कैसे ये पण्डित (विशेषज्ञ) सिद्धान्त एवं व्यवहार के क्षेत्र में गलत दिशा को प्रस्तुत कर रहे हैं एवं किस प्रकार समाजशास्त्र इन मुद्दों को पूर्ण दक्षता एवं व्यवस्थित रूप में समझा पाने में समर्थ है।

एम. बी. : समाजशास्त्र में पी.एच.डी. की उपाधि आपने अमेरिका से प्राप्त की। आप वहां समय समय पर जाते भी रहते हैं। वस्तुतः हमारी पहली मुलाकात अमेरिका में विस्कान्सिन विश्वविद्यालय में हुई थी। पेरू के वामपन्थी अमेरिका में क्या कर रहे हैं?

एन. एल.: मैंने एम. ए. की उपाधि मैक्सिको से प्राप्त की। मैं विभिन्न अकादमिक क्रिया कलापों के संदर्भ में समूचे लेटिन अमेरिका एवं यूरोप में गया हूं। अन्य देशों की भांति अमेरिका में ऐसे अनेक सम्भावित स्थान हैं जहां अध्ययन किये जा सकते हैं। 1980 के दशक में एक बहुत अच्छे एवं प्रगतिशील अमेरिकन विश्वविद्यालय, न्यू स्कूल फार सोश्यल रिसर्च से मैंने पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। मैडीसन, विस्कानसिन इत्यादि अनेक स्थानों पर मैं विजिटिंग स्कालर भी रहा। मेरा मत है कि अमेरिका के विभिन्न भागों में हमें सम्पर्क स्थापित करने व विचार विमर्श करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि हमारे विचारों में विमति है पर हमें एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए।

एम. बी. : मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके जीवन वृत्त में ऐसा कुछ है, शायद आपकी प्रारम्भिक शिक्षा में या आपके परिवार की पृष्ठभूमि में जिसके कारण आप एक साथ दो दिशाओं–राजनीति एवं समाजशास्त्र की तरफ अग्रसर हुए?

एन. एल.: ठीक है, अनेक लोगों के मतानुसार पेरू की राजनीति के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मेरा जन्म एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। मेरी कोई देशज वंशावली नहीं है। मेरे पास, जैसा मैं सोचता हूं, अच्छी शिक्षा है। यह हो सकता है कि पेरू में विद्यमान गहन एवं भयानक यथार्थ के रूप में सामाजिक असमानता ने मुझे अन्तः सम्बन्धित धागों वाले दोहरे जीवन के प्रति समर्पित किया। पर मैं समाजशास्त्र एवं राजनीति दोनों क्षेत्रों में क्रिया करते हुए प्रसन्न हूं। जैसा मैंने कहा है ये दोनों विषय एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं। मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है।

एम. बी. : अब चूंकि आप सरकार से बाहर है, आप अपने आप को कैसे व्यस्त रख रहे हैं? क्या आप अब भी राजनीति से सम्बद्ध है? क्या आप और लिख रहे हैं?

एन. एल.: हां, मैं राजनीति में हूं। मैं वामपन्थी गठबन्धन का सदस्य हूं। पेरू के प्रत्येक क्षेत्र में इसका आधार एवं प्रभाव है। सन् 2014 के क्षेत्रीय चुनावों में हमारी सम्भावनायें अच्छी हैं। मेरी स्वयं की एक वेबसाइट है जिसे मैं अपने मित्र समूह के साथ संचालित करता हूं। यह एक ऐसा प्लेटफार्म (स्थल) है जिस पर इन्टरनेट के द्वारा हम राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। हम समाचार विश्लेषण का एक पृष्ठ लगभग 16,000 ई–मेल पतों पर भेजते हैं। हमारे पास रेडियो कार्यक्रम हैं और हम सार्वजनिक नीतियों का विश्लेषण करते हुए आलेख भी लिखते हैं। सेने मार्कोस विश्वविद्यालय में, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, विद्यार्थियों को कक्षाओं में पढ़ाता हूं। साथ ही मेरी एक पुस्तक का लेखन समाप्ति की ओर है जो कि पेरू गणतन्त्र के आधारभूत ढांचे एवं गणतन्त्र के भविष्य के विषय में एक लम्बा राजनीतिक लेख/निबन्ध है।

एम. बी. : मैं सोचता हूं मैक्स वेबर आपसे बहुत ईर्ष्या करते होंगे। यह ईर्ष्या समाजशास्त्र एवं राजनीति दोनों ही क्षेत्रों में उनको आपसे होती होगी। आपने इन दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया पर एक दूसरे के लिए है कि त्रुटि कभी नहीं की। एक शानदार साक्षात्कार हेतु आपको धन्यवाद।

>शक्ति की औपनिवेशिकता
पेरू से एक परिप्रेक्ष्य

सीजर जर्माना, यूनिवर्सिडाड नेशियोनाल मेयर ड सान मार्कोस, लीमा, पेरू

औपनिवेशिकता के मसीहा, पेरु के समाजशास्त्री एनीबाल क्विजानो।

ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जो बताते हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें पिछले 500 वर्षों से इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित कर चुका आधुनिक–औपनिवेशिक शक्ति का सम्पूर्ण/समग्र प्रारूप संरचनात्मक संकट का शिकार है। समूची शक्ति संरचना के मूलभूत आधारों में यह संकट उभरा है। इसके सभी अवयवों एवं स्तरों–जैसे लैंगिक सम्बन्ध, श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध, अन्तः वैषयिक सम्बन्ध एवं प्रकृति के साथ सम्बन्ध, जिनमें विभिन्न प्रकृति की कठिनाइयां उभरी हैं का समाधान वर्तमान ऐतिहासिक व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता अतः सामाजिक सहअस्तित्व के नवीन स्वरूप की स्थापना का आव्हान किया जाना समीचीन हो गया है।

अन्तः वैषयिक संरचनाओं का संकट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है–एवं उन ज्ञान प्रणालियों के तरीकों को विशेषतः समझना है जो समाज विज्ञानों पर लागू होते हैं। 1970 के दशक से समाज विज्ञानों में हमने रूपान्तरण की जटिलताओं को देखा है ये रूपान्तरण संकेत देते हैं कि तरीके कौन से हैं उन्हें आवश्यक रूप से पुनः संगठित करना है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से सामाजिक विचारों के क्षेत्र में हो रहे महत्व पूर्ण बदलावों का सम्भवतया सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण 'गुल बैंकियन कमीशन प्रतिवेदन' में मिलता है (वार्लेस्टीन 1997)। यह प्रतिवेदन दर्शाता है कि ज्ञान की यूरो–केन्द्रित संरचना किस प्रकार बिखर रही है। ऐसा केन्द्रीय एवं परिधिमूलक दोनों ही प्रकार के देशों में हो रहा है। साथ ही किस प्रकार विचारों के सम्प्रदाय उभर कर आये हैं और सामाजिक एवं ऐतिहासिक यथार्थ को समझने हेतु वैकल्पिक स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं अथवा वैकल्पिक स्वरूपों की प्रस्तुति उनका उद्देश्य बन गयी है।

मेरा मत है कि यूरोकेन्द्रियता ज्ञान की वह संरचना है जो शक्ति के औपनिवेशिक–आधुनिक स्वरूप को सुनिश्चित एवं सुपोषित करती है। यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विश्व को अनुभव करने एवं समझने तथा उन्हें संगठित करने के विशिष्ट तरीकों की तरफ ले जाती है। यह तीन आधारभूतीय विश्वासों पर आधारित है:

पहला विश्वास सरलीकरण से सम्बद्ध है: डेकार्ट के अनुसार सभी जटिल प्रक्रियाओं

>>

को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उनको जितना भी सम्भव हो अनेक अंगों में विभाजित कर दिया जाए ताकि प्रत्येक अंग की अलग से विवेचना की जा सके ताकि क्या स्पष्ट/साफ है का पक्ष कितना सरलीकृत है। यह परिप्रेक्ष्य इस पृष्ठभूमि के साथ ज्ञान के खण्डीयकरण एवं विशेषज्ञीकरण को उत्पन्न करता है और उसे बढ़ाता है। इस के कारण विभिन्न विषय बौद्धिक श्रेणियों के रूप में व्यक्त होते हैं साथ ही प्रत्येक विषय के अपने उद्देश्य एवं उनकी अध्ययन की पद्धति भी स्पष्ट हो जाती है। विभिन्न विषय संस्थागत श्रेणियों को भी विकसित करते हैं जो कि विभागों के उद्भव के आधार पर बन जाते हैं एवं आधुनिक विश्वविद्यालयों की संगठनात्मक संरचना को रूप प्रदान कर देते हैं।

यूरोकेन्द्रित ज्ञान की दूसरी आधार भूतीय अवधारणा सामाजिक एवं प्राकृतिक व्यवस्थाओं में संतुलन/स्थायित्तवा से सम्बद्ध विश्वास से है। यह अवधारणा यथार्थ को एक व्यवस्थित विश्व के रूप में प्रस्तुत करती है जो कि सरल एवं ज्ञात नियमों द्वारा संचालित होती हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह ज्ञान हमें भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है कि क्या होगा और इस कारण हम न केवल प्राकृतिक विश्व को अपितु सामाजिक विश्व को भी नियन्त्रित कर सकते हैं। यह विश्वास निर्णायकवाद एवं विपरीतता के विचार को आगे बढ़ाता है। दूसरे शब्दों में घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और इस कारण इतिहास का विलुप्तिकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया हो जाती है।

तीसरा आधारभूतीय विश्वास वस्तुपरकता है। इसका अर्थ यह है कि आप यथार्थ को इसके मूल रूप में जान सकते हैं। यह विचार विषय का स्थगन है। इस विश्वास का परिणाम इस विचार की स्वीकृति से है कि ज्ञान मूल्य–तटस्थ है। शक्ति के औपनिवेशिक–आधुनिक प्रारूप में यूरो–केन्द्रियता अपने आप को ज्ञान का अथवा जानने का एक मात्र वैधानिक/विधिक स्वरूप के रूप में लागू करती है और इसके फलस्वरूप उपनिवेश का शिकार रही जनसंख्या के ज्ञान की संरचनाओं को हाशिये पर लाती है, उन्हें निम्नवर्गीय बना देती है अथवा उन्हें खण्डित कर देती है इन लोगों ने अपने जिस ज्ञान को अनेक शताब्दियों से विकसित किया है और जो उनके सामाजिक अस्तित्व के विशिष्ट स्वरूप के रूप में सक्रिय होता है को हिंसक तरीके से कुचला जाता है एवं उसे हाशिये पर ला दिया जाता है ताकि उनके स्वयं के वाहक ज्ञान के इस स्वरूप से मुक्ति पाने की सोचने लगें एवं स्वयं को तथा स्वयं के ज्ञान को तुच्छ समझने लगें।

औपनिवेशिक–आधुनिक स्वरूप की इस शक्ति की परिधि से ऐसे विचारों के स्पष्ट प्रवाह की उत्पत्ति होती है जो ज्ञान की यूरो केन्द्रित संरचनाओं के सम्मुख रेडीकल प्रश्नों को सामने लाती है। इस परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत महत्वपूर्ण योगदान में उत्तर–औपनिवेशिक अध्ययन, निम्नवर्गीय अध्ययन एवं अफ्रीकी बुद्धिजीवियों के विचारों को सम्मिलित किया जाता है। इन वैचारिक प्रवाहों के अन्तर्गत ''औपनिवेशिकता–शक्ति के वि–औपनिवेशीकरण'' से सम्बद्ध विश्लेषणात्मक उपागम अत्यन्त महत्वपूर्ण व आशावादी तरीके से यूरो केन्द्रित ज्ञान के विकल्पों को प्रस्तुत करता है। यह समकालीन विश्व की प्रवृत्तियों तथा भविष्य की सम्भावनाओं के माध्यम से विमर्श को समझने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। अगस्त 2010 में लीमा में एनिबाल क्विजानो द्वारा आयोजित 'द कुअश्चिन्स ऑफ डिस/कोलोनियलटी एण्ड ग्लोबल क्राइसिज' (वि/औपनिवेशिकता एवं विश्व संकट से सम्बद्ध प्रश्न) विषय पर सेमीनार निश्चय ही पूर्व में हुई बहसों की परिणति थी एवं शक्ति की औपनिवेशिकता के विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य से भिन्न दिशा की तरफ अग्रसरता की बिन्दु थी।

औपनिवेशिकता–शक्ति के विउपनिवेशी करण का विश्लेषण ज्ञान से सम्बद्ध एक परिप्रेक्ष्य को उत्पन्न करता हैं। यह एक तरीका है जिससे यथार्थ की समझ, प्रश्नों को उत्पन्न करना तथा मानव जाति के सामाजिक जीवन से सम्बन्धित प्रत्युत्तरों को संगठित किया जा सकता है। इससे हमें दक्षता मिलती है कि हम उन महत्व पूर्ण प्रश्नों को उठायें जिन्हें यूरो केन्द्रित सोच ने बिल्कुल बन्द कर रखा था। यह ज्ञान को सृजित करने के यूरो केन्द्रित स्वरूपों को एक चुनौती है क्योंकि यह आधुनिक–औपनिवेशिक पूंजीवादी व्यवस्था सम्बद्ध ज्ञान की एकाधिकारी संरचनाओं के आधारों के विषय में प्रश्न उत्पन्न करता है। इस लेख का उद्देश्य उन ज्ञान मीमांसाई एवं सैद्धान्तिक अनुमानों एवं सम्भावनाओं का परीक्षण करना है जो ज्ञान के वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य में अन्तः निहित हैं। मैं इस अन्वेषण के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को विश्लेषित कर रहा हूं जो सामाजिक सिद्धान्त की पुनर्रचना/पुनःसंगठन में योगदान करते हैं।

एनिबाल क्विजानो के नवाचारी सिद्धान्तों का अनुकरण करते हुए, मेरा मत है कि सन् 1492 की यूरोपियन विजय जिसे हम बाद में अमेरिका कहते हैं, में शक्ति के प्रारूप का एक स्वाभाविक उदय हुआ जिसकी औपनिवेशिकता एवं आधुनिकता मुख्य विशेषतायें थीं। एक तरफ यह औपनिवेशिकता के द्वारा परिभाषित हुआ। युद्ध एवं विजय के दौरान जो शक्ति सम्बन्ध उभरे उसमें मानव जाति के सामाजिक वर्गीकरण के रूप में ''प्रजाति'' का विचार उभरा। दूसरे शब्दों में विजेताओं ने अपने आपको श्रेष्ठ मनुष्य समझा एवं स्वयं को 'श्वेत' के रूप में प्रस्तुत किया जबकि जिन्हें जीता गया उन्हें निम्न समझा गया तथा उन्हें 'इण्डियन्स' एवं ''अश्वेत'' की संज्ञा दी गयी। सामाजिक सम्बन्धों की स्वाभाविकता में ''प्रजाति'' का विचार प्रभुत्व एवं शोषण, जो कि देशज लोगों एवं अफ्रीकी दासों के विषय में है, को वैधता प्रदान करता है। यह विचार शक्ति के स्वरूप को पोषित करने की एक आवश्यक विशेषता बन गया। यह विचार स्पेन एवं पुर्तगाल के द्वारा जीते गये उपनिवेशों की स्वतन्त्रता के बाद भी जारी रहा। यह विचार स्थापित करता है कि प्रभुत्व स्थापित करने वाली शक्तियां एवं प्रभुत्व सहन करने वाले लोगों ने प्रभुत्व को एक स्वाभाविक अवधारणा के रूप में स्वीकारा। इस बीच में औपनिवेशिकता का दूसरा चेहरा आधुनिकता के रूप में उभर कर आया। सामाजिक जीवन की तार्किकता एवं वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रगति इसके मुख्य संकेतकों के रूप में उभरे।[1]

विउपनिवेशीकरण की ज्ञान मीमांसा उन अनुमानों पर सवाल करती है, जिन पर यूरो केन्द्रित ज्ञान संरचना निर्मित हुई साथ ही यह वैकल्पिक विवेचनाओं को आगे करती है जो सामाजिक विश्व के व्यवस्थित बोध को विकसित करने में ज्यादा उपयोगी हैं और साथ ही समानता मूलक एवं लोकतान्त्रिक भविष्य के वास्तविक विकल्प को प्रस्तावित करते हैं। मैं सामाजिक जीवन के विषय में ज्ञान को सृजित करने के यूरोपियन तरीके के विषय में पांच प्रश्नों को अनुमान के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं तथा औपनिवेशिकता–शक्ति के विउपनिवेशीकरण के विश्लेषण से उत्पन्न पांच वैकल्पिक विवेचनों को प्रस्तावित कर रहा हूं :

(1) सामाजिक जीवन को समझने हेतु राज्य के एक विश्लेषणात्मक स्वरूप पर प्रश्न/राज्य की संरचनाओं को उन भौगोलिक सीमाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत

>>

नहीं किया जा सकता, जिनके अन्तर्गत सामाजिक सम्बन्ध परिभाषित होते हैं। अतः हमारे विश्लेषण की इकाई, वैश्विक, आधुनिक–औपनिवेशिक प्रारूप जो कि शक्ति कि विषय में है, जो सोलहवीं सदी में यूरोपियन विजय के रूप में उभरा जिसे अमेरिका कहा गया, को आवश्यक माना जाना चाहिए।

(2) औपनिवेशिक शासक एवं उपनिवेशों में निवास कर रहे शासित के मध्य प्रभुत्व एवं अधीनस्थता के सम्बन्धों को समझने हेतु औपनिवेशिक शक्ति की अवधारणा पर प्रश्न। अतः हम न केवल आर्थिक, विधिक एवं राजनीतिक शोषण एवं प्रभुत्व का परीक्षण कर रहे हैं अपितु आधुनिक–औपनिवेशिक व्यवस्था के अन्दर ये शक्ति सम्बन्ध उन विचारों के प्रतीकात्मक एवं वैधानिक समुच्चयों से कैसे सम्बन्धित हैं जो ''प्रजाति'' की अवधारणा को निर्मित व विकसित करते हैं। अतः शक्ति सम्बन्धों का प्रजातीयकरण शक्ति के वैश्विक, पूंजीवादी एवं यूरो केन्द्रित प्रारूप को निर्मित करता है।

(3) सरलीकरण के ज्ञान मीमांसा पर प्रश्न। विशेषतः यह विश्वास कि जटिल प्रक्रियाओं को समझने के लिए उन्हें जितना सम्भव हो अनेक भागों में बांट दिया जाए ताकि इन भागों को स्वतन्त्र रूप में अध्ययन का विषय बना जा सके। शक्ति की औपनिवेशिकता के विश्लेषण हेतु शक्ति के वैश्विक, आधुनिक–औपनिवेशिक प्रारूप को एक ऐतिहासिक समग्री के रूप में समझने के महत्व पर बल दिया जाय। इस तरह शक्ति को यह विषमरूपीय अवयवों की जटिल व्यवस्था के रूप में समझता है ये अवयव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़े हैं। ये अवयव सोलहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए एवं उन्नीसवीं शताब्दी में इनका विस्तार वैश्विक नियन्त्रण हेतु हुआ यह व्यवस्था वर्तमान में विभाजन के दौर अथवा संरचनात्मक संकट के दौर में प्रवेश कर गयी है। इस दृष्टि से राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनमाना विभाजन/पृथक्करण उपयोगी नहीं है। हमें तो इन क्षणों को एक पूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। इसके अलावा इस वैकल्पिक परिकल्पना के अनुसार विषयों के रूप में सामाजिक ज्ञान का विशेषज्ञीकरण जो कि उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप में सामाजिक विज्ञानों की ऐतिहासिक रचना से उत्पन्न हुआ, का कोई ज्ञान मीमांसाई औचित्य नहीं है। हमारी दृष्टि में उपयोगी विशेषज्ञीकरण विशिष्ट समस्याओं अथवा अध्ययन क्षेत्र के आस पास ही संकेन्द्रित होता है।

(4) ज्ञान के विषय एवं वस्तु के मध्य पृथक्करण पर प्रश्न। यहां वस्तुपरकतावाद (जो विषय को बन्धनों में बांधता है) एवं विषयपरकतावाद (जो वस्तु को बन्धनों में बांधता है) दोनों के सम्मुख चुनौती है। चूंकि दोनों ही परिप्रेक्ष्य यथार्थ की सम्पूर्ण समझ को बाधित करते हैं विशेषतः सामाजिक यथार्थ की सम्पूर्ण समझ को बाधित करते हैं। दूसरे शब्दों में इस पक्ष को मान्यता देने की आवश्यकता है कि विश्व का अस्तित्व विषय के बाहर है–लेकिन विषय ज्ञान के सृजन में हस्तक्षेप करता है ताकि मापक के विभिन्न तत्व उदाहरण के लिए जो कुछ मापित किया गया है, में संशोधन या बदलाव कर सकें। अतः ज्ञान एक अन्तः वैषयिक उत्पाद है। इसे अन्तः वैषयिक संरचनाओं के संदर्भ में एवं ज्ञान मीमांसायी नियमों–सामाजिक नियमों के साथ समझा जा सकता है। ये सभी पक्ष सत्य की रचना करते हैं।

(5) वैज्ञानिक एवं मानविकीय ज्ञान के मध्य पृथक्करण से सम्बद्ध प्रश्न। यदि वैज्ञानिक ज्ञान मुख्य रूप से आनुभविक पद्धतियों/प्रणालियों के आधार पर सत्य की खोज करता है एवं मानविकीय ज्ञान आचार संहिता एवं सौन्दर्यात्मकता के मूल्यों की विवेचना करता है। शक्ति की औपनिवेशिकता के विश्लेषण का परिप्रेक्ष्य उस ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है जो कि अपने सृजन की प्रक्रिया में तत्काल सत्य, अच्छा एवं सुन्दर होता है। अतः हमें विश्व में दुबारा उस मोह एवं आकर्षण को उत्पन्न करना है जो विश्व के विषय में बताता है औपनिवेशिकता एवं आधुनिकता तार्किकवादी हो गये हैं और अब मोहभंग हो गया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हमारे पास अब ज्ञान के विषय में एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जिसमें आशावादी विशेषतायें हैं जिन्हें विभिन्न दिशाओं में विस्तारित किया जा सकता है ताकि सामान्य एवं साथ ही विशिष्ट सिद्धान्तों की ज्यादा विवेचना हो सके शक्ति के वैश्विक प्रारूप की वृहद सीमाओं के सामान्य सिद्धान्तों, शक्ति के इस वैश्विक प्रारूप के संकटों एवं ऐतिहासिक विकल्पों जो इन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं को समझा जा सकता है। साथ ही शक्ति के ऐतिहासिक प्रारूप के अत्यन्त विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध विशिष्ट सिद्धान्तों को भी इस आधार पर समझा जा सकता है। ■

[1] एनिबाल क्विजानो ने 1991 में 'कोलेनियेलटी ऑफ पावर' की अवधारणा को प्रस्तुत किया। बाद में इस विचार को उन्होंने अनेक लेखन कार्यों में विकसित किया जिसमें क्विजानो एवं वार्लेस्टीन (1992) एवं क्यूजानो (1993, 2000ए 2000इए 2000ब, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 एवं 2010) सम्मिलित है। इस अवधारणा से सम्बन्धित बहस हेतु देखें: मिग्नोलो (2003), एस्कोबार (2003) एवं पाचोन सोटो (2007)

संदर्भ सूची :

[1] Aníbal Quijano introduced the concept of the *coloniality of power* in 1991. He later developed the idea in various other texts, including Quijano and Wallerstein (1992) and Quijano (1993, 2000a, 2000b, 2000c, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 and 2010). For a debate about this concept, see the following texts: Mignolo (2003), Escobar (2003) and Pachón Soto (2007).

References

Escobar, A. (2003) "Mundos y conocimientos de otro modo: El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano." *Tabula Rasa* 1: 51-86.

Mignolo, W. (2003) *Historias locales/diseños globales: Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal.

Pachón Soto, D. (2007) "Nueva perspectiva filosófica en América Latina: el grupo Modernidad/Colonialidad." *Peripecias* 63.

Quijano, A. and Wallerstein I. (1992) "Americanity as a Concept or the Americas in the Modern World-System." *International Journal of Social Sciences* 134, UNESCO: 617-627.

Quijano, A. (1991) "Colonialidad y modernidad/racionalidad." *Revista del Instituto Indigenista Peruano* 13.29: 11-20.

Quijano, A. (1993) "Raza, etnia y nación en Mariátegui: cuestiones abiertas." In: Aníbal Quijano *et al.* (eds.) *José Carlos Mariátegui y Europa: El otro aspecto del descubrimiento*. Lima: Amauta: 167-188.

Quijano, A. (2000a) "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina." In: Edgardo Lander (ed.), *Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO/UNESCO: 201-246.

Quijano, A. (2000b) "Colonialidad del poder, globalización y democracia." In: *Tendencias básicas de nuestra época*. Caracas: Instituto de Altos Estudios Internacionales Pedro Gual: 21-65.

Quijano, A. (2000c) "Coloniality of power and social classification." In: *Journal of World-Systems Research* 6.2: 342-386.

Quijano, A. (2001) "Colonialidad, poder, cultura y conocimiento en América Latina." In: Walter Mignolo (ed.), *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. Buenos Aires: Signo: 117-131.

Quijano, A. (2004) "O 'movimento indígena' e as questões pendentes na America Latina." In: *Política externa* 12.4: 77-97.

Quijano, A. (2007) "Don Quijote y los molinos de viento en América Latina." In: *Investigaciones Sociales* 10.16: 347-368.

Quijano, A. (2009) "Des/colonialidad del poder: El horizonte alternativo." In: *Pasado y Presente* 21.

Quijano, A. (2010) "'Bien vivir' para redistribuir el poder: Los pueblos indígenas y su propuesta alternativa en tiempos de dominación global." In: Oxfam Annual Report 2009-2010: *Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú*.

Wallerstein, I. (1997) *Abrir las ciencias sociales*. México: Siglo XXI.

>चियापास से एक असमान विश्व से सामना

मार्क्स एस. शुल्ज, अरबाना–चैम्पेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोयस, यू.एस.ए., 2014 आई.एस.ए. वर्ल्ड कांग्रेस की कार्यक्रम समिति के सदस्य तथा फ्यूचर्स रिसर्च पर आई.एस.ए. की शोध समिति के अध्यक्ष (आर.सी. 07)

आत्मसम्मान के लिए संघर्षरत देशज माया महिलाएें। चित्र मार्क्स शुल्ज द्वारा।

सन् 2014, नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेण्ट (नाफ्टा), जो कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका के मध्य हुआ, की 20वीं वर्षगांठ है। नाफ्टा विकास के विभिन्न स्तरों पर स्थित देशों के मध्य हुआ पहला समझौता था जो बाद में हुई सन्धियों एवं वर्तमान समझौतों जो बीस पैसिफिक रिम देशों के बीच ट्रांस–पैसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) तथा यूरोपीय संघ एवं अमेरिका के मध्य हुए ट्रांसएटलांटिक ट्रेड एण्ड डवलपमैण्ट पार्टनरशिप (टी टीआइपी) के लिए संदर्भ बिन्दु बन गया। पहले बुश प्रशासन के दौरान इस समझौते की नींव पड़ी और क्लिंटन के शासन काल में यह क्रियान्वित हुआ। यह समझौता वह प्रारूप है जो निर्यातोन्मुखी कारपोरेशन्स पर शुल्कों में कमी कर लाभ पहुंचाता है वहीं दूसरी ओर श्रमिक हितों एवं पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों की उपेक्षा करता है।

सन् 2014 चीयापास में स्थानीय मूल निवासियों (देशज) के उभरे आन्दोलन की भी 20वीं वर्षगांठ है। जब नाफ्टा प्रभावी हुआ तो जापाटिस्ट संगठित होकर विरोध में खड़े हुए। उन्होंने भूमि, नागरिकीय अधिकार व एक शिष्ट जीवन यापन के लिए हो रहे स्थानीय संघर्षों को वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र तथा सामाजिक न्याय के लिए हो रहे व्यापक संघर्ष से जोड़ा। अनेक वर्षों के इस प्रयास के फलस्वरूप जापाटिस्ट ने आलोचनात्मक विमर्श को प्रोत्साहित किया तथा विभिन्न देशों से जुड़े सक्रिय कार्यकर्त्ताओं के साथ सम्पर्क–ढाँचा

>>

सामुदायिक कार्य – चियापास के पर्वतीय क्षेत्र में आर्गेनिक मूलियों के लिए खेत को तैयार करते हुए। चित्र मार्कस शुल्ज द्वारा।

(नेटवर्क) विकसित किया। इसके कारण सियाटिल, प्राग, जेनेवा में हुए सम्मेलनों, जहां वैश्विक अभिजनों ने विश्व अर्थव्यवस्था में नव्य उदारवाद को पुनः संरचित किया, के सम्मुख बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए।

हालांकि जनसंचार माध्यमों ने चीयापास से अपना ध्यान हटा लिया है पर यह सोचना गलत होगा कि जापाटिस्ट आन्दोलन समाप्त हो गया है। विद्रोह जारी है हालांकि तरीके बदल गये हैं। विद्रोही मायान समुदायों ने अपने स्वायत्तशासी म्युनिसपल निकाय स्थापित किये हैं, जहां वे स्व–प्रशासन के जमीनी स्वरूपों के परीक्षण करते हैं। स्थानीय एवं क्षेत्रीय बोर्ड्स (मंडलों) में सम्मिलित परिभ्रमण प्रकृति के सदस्यों को ''मान्डर–ओबिडिसियान्डो'' ("mandar-obedeciendo") अर्थात् आज्ञा द्वारा शासन को मानना बाध्यता मूलक है। दिसम्बर 2012 में जापाटिस्ट ने हाइलैण्ड्स में केन्द्रित मुख्य नगर सान क्रिस्टोबल ड लास कासास में लाखों लोगों ने मौन जुलूस निकाल कर अपनी शक्ति का परिचय दिया।

पिछली गर्मियों में जापाटिस्ट ने अपने नवीनतम प्रयास को प्रारम्भ किया उन्होंने अपने समुदायों में अतिथियों को आमन्त्रित किया कि वे जानें कि इन समुदायों की दृष्टि में स्वतन्त्रता का क्या अर्थ है। उनके ''लिटिल स्कूल्स'' (छोटे विद्यालयों अथवा (escuelitas) ने सभी संदर्भों को पलट कर रख दिया। विश्व के लोगों को आमन्त्रित किया गया कि वे देशज लोगों को विकास के बारे में न पढ़ायें अपितु उनसे विकास के विषय में समझें, उन्हें देखें, उन्हें सुनें और उनके अनुभवों से सीखें कि वे किस प्रकार सामाजिक विकल्प का आकार बनाते हैं तथा स्वायत्तशासी स्वशासन में सहभागिता संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। एस्क्यूलिटास किसी उच्च आसन से बड़े भाषणों के लिए नहीं थे अपितु उन देशज लोगों के दैनिक प्रतिरोधों में सम्मिलित जीवन्त क्रियाओं व व्यवहारों पर आधारित प्राथमिक/मौलिक शिक्षण के लिए थे।

बारह सौ से अधिक लोग जो विभिन्न आयु समूहों के थे मैक्सिकों के विभिन्न भागों तथा विश्व के अनेक देशों से यात्रा कर वहां पहुंचे। इनमें कलाकार, बुद्धिजीवी, कृषि श्रमिक, संगीतज्ञ, कवि, सड़कों पर काम करने वाले लोग, विद्यार्थी तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जनसंख्या से सहानुभूति रखने वाले लोग सम्मिलित थे। वहां पर कोई शिक्षा शुल्क नहीं था। रहने, खाने एवं यातायात की सुविधायें भी निशुल्क थी। सहभागियों को सौ पैसोस (लगभग दस डॉलर) देने को कहा गया ताकि मुद्रित सामग्री दी जा सके। साथ ही एक सीलबन्द जार दिया गया जो कि लोगों को गुप्त दान करने का अवसर देता था। जापाटिस्ट का मत था कि इससे बड़ी राशि दान करने वाला अपने को बहुत सामर्थ्यवान तथा जो बिना पैसे वाले हैं को संकोच का अनुभव न होने दें।

जाप्टिस्टास के दृष्टिकोण अथवा उनकी दूरदृष्टि एवं उनके निर्देशात्मक/सलाहमूलक सिद्धान्तों के विषय में प्रश्नों एवं उत्तरों के अवसर सामान्य बैठकों में प्राप्त हुए पर शिक्षण का मुख्य भाग समुदायों में उभर कर आया। इन समुदायों ने अनेक महीनों से इस भ्रमण की तैयार की थी। प्रत्येक विद्यार्थी को 'वोटान' अर्थात् अभिभावक एवं शिक्षक उपलब्ध कराया गया जो कि समुदाय का भाग था। जाप्टिस्टास के प्रवक्ता सब कमान्डेंट मारकोज ने विवेचना करते हुए कहा ''यहां कोई एक शिक्षक नहीं है'', ''यहां तो सामूहिकता शिक्षण देती है, यही दिखाती है, यही स्वरूप की रचना करती है, यह स्वयं में है और इस के द्वारा व्यक्ति न केवल सीखता है अपितु शिक्षण भी देता है।''

एक युवा जोटजल (Tzotzil), जो कि एक अभिभावक है, की कहानी स्पष्ट करती है कि उसकी पीढ़ी के अनेक लोगों के अनुभव क्या हैं। दो वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर वह स्वयं समुदाय के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहा है। कानकुन में जोटजल को एक भिन्न जीवन पद्धति का अनुभव हुआ। भविष्य में धन कमाने का स्वप्न लेकर, वे एक बड़े नगर में गये एवं निर्माण उद्योग, रैस्टोरेन्ट एवं होटल्स में कार्य किया। जोटजल उस नगर की चमकती हुई सफेद इमारतों एवं रिसार्ट क्षेत्रों (मनोरंजन/पर्यटन केन्द्रों) के बारे में बड़े प्रभावी ढंग से बताते हैं लेकिन यह भी बताते हैं कि समुद्री क्षेत्र एवं धनाढ्य पड़ौस से कुछ खण्डों की दूरी पर बहुसंख्यक जनसंख्या की निर्मम प्रकृति की निर्धनता के भी वे गवाह हैं। एक साल से अधिक की अवधि में उन्होंने नकद अर्थव्यवस्था से संचालित जीवन पद्धति का अनुभव किया, अपने चारों तरफ प्रभावी लोगों के निर्देश देखे, टिप्स में लोगों को धोखा देते हुए देखा, कभी कभी तो पारिश्रमिक में भी धोखा दिया गया। अन्त में इन स्थितियों को भोगने की चरम स्थिति के उपरान्त वे अपने समुदाय में वापस आ गये। अनुशासन के स्थान पर शिष्टता एवं स्व सम्मान तथा प्रतियोगिता के स्थान पर उन्होंने समुदाय को प्राथमिकता प्रदान की। बीस साल के जन उभार के उपरान्त, अब उस स्थान पर एक स्वायत्तशासी विद्यालय व्यवस्था है जिसमें

>>

जाप्टिस्टा समुदाय अपनी आवश्यकताओं, मूल्यों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी पाठ्यचर्या निर्धारित करते है। अपने क्षेत्रीय केन्द्रों में से एक पर उन्होंने एक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना प्रारम्भ की है जहां विद्यार्थी दो सप्ताह के कालांशों हेतु विशेष रूप से रूकेंगे क्योंकि उन्हें अन्यथा दूर दराज से वहां आना पड़ता है। प्रारम्भिक विद्यालयों को स्थानीय सामुदायिक स्तर पर स्थापित किया गया है। यहां वे शिक्षक पढ़ाते हैं जिन्हें विद्यालय स्तर का कुछ ज्ञान है। जाप्टिस्टास इस व्यवस्था को सरकार द्वारा संचालित सरकारी विद्यालयों से कहीं अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक स्थानीय भाषा नहीं बोलते हैं और परिवार एवं नगरीय सुविधाओं से दूर उनको उपेक्षित दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया है। जाप्टिस्टास शिक्षक स्वयं को शिक्षा के प्रोत्साहक कहलाना पसन्द करते हैं क्योंकि वे शिक्षण कार्य की परिपाटीय शीर्ष–निम्न प्रणाली के स्थान पर मिलजुल कर शिक्षण के सहयोगात्मक तरीकों को अपनाने के पक्षधर हैं। जाप्टिस्टास शिक्षक अध्यापन का वेतन नहीं लेते। समुदाय उन्हें आवास, भोजन, सामुदायिक कार्यों से समय मुक्ति एवं कपड़ों के लिए छोटा–मोटा भत्ता प्रदान करता है।

समुदाय में सहभागिता मूलक जीवन में खेत में श्रम, सब्जियों की खेती, फलों को चुनना, तैरना एवं कपड़े धोना, खाना बनाना, साथ साथ खाना, गाने गाना एवं कहानियाँ सुनाना जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं। यदि भौतिक मापकों के आधार पर वर्गीकरण किया जावे तो उस समुदाय का जीवन स्तर जहां मैं गर्मियों में रूका, अत्यन्त गरीबी वाला था। कच्ची ईंटों की झौपड़ियां अत्यन्त सरल थी एवं उनके फर्श सूखे हुए थे। उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे तथा बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दूसरी तरफ, वहां अनेक लाभ व सुविधा जनक पक्षा थे। वह स्थल शान्तमय था तथा शोर शराबे वाली चौड़ी सड़कों एवं प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से काफी दूर था। पास में बह रहे एक झरने से ताजा पानी अनवर मिलता था। भोजन में मुख्यतः मक्का भुना हुआ, चावल, फली, सब्जियां तथा कभी कभी अण्डा उपलब्ध कराया जाता था लेकिन सामान्यतः ना तो गोश्त और ना ही व्यावसायिक सोडा उपलब्ध था। भोजन की सामग्री ताजी, जैविक एवं सुगन्ध वाली होती थी। सम्भवतया सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि समुदाय में अपने सम्मान एवं शिष्टता की जबरदस्त भावना थी और वे अपनी स्वायत्तता के प्रति गर्व का अनुभव करते थे।

मायान की निर्वाह मूलक कृषि गतिविधि में मक्का मुख्य है। नाफ्टा ने मैक्सिको के किसानों को अमेरिका से प्रतियोगिता की तरफ धकेला। अमेरिका में मक्का का उत्पादन औद्योगिक स्तर पर बड़े मोनोकल्चर्स (बड़े एकल खेती वाले खेत) में होता है तथा सरकार बड़े पैमाने पर रियायतें देती है। इसके कारण किसानों पर दवाब पड़ा कि वे खेती छोड़ें और नगरों में या विदेशों में नौकरी की तलाश करें। जाप्टिस्टास ने अपने उपभोग हेतु परम्परागत रूप से अपने 'मिलपस', गहरी ढलान वाले छोटे खेतों में मक्का का उत्पादन जारी रखा साथ ही अन्य पौधों जैसे खाद्यान्न सम्बन्धी खर पतवार, शरबत एवं विशेषतः फलियों जो कि मक्का की खेती के बाद मक्का की डन्डी का प्रयोग होता है, के उत्पादन पक्षों को भी ध्यान में रखा। जाप्टिस्टास ने बहुराष्ट्रीय निगमों जैसे मोन्सान्टो के द्वारा प्रचारित जी एम ओ बीजों का विरोध किया। जाप्टिस्टास ने 9000 वर्षों से जारी मध्य रूप अमेरिकन खेती में विद्यमान जैव विविधता को अमेरिकन एग्रीबिजनिस में रासायनिकों अर्थात् पेस्टीसाइड्स पर आधारित संकरी प्रणाली, जो कि कुछ इन–ब्रेड क्रियाओं में विद्यमान है, के विपरीत में प्रस्तुत किया।

एक महत्वपूर्ण रूपान्तरण लैंगिक सम्बन्धों के क्षेत्र में हुआ है। क्रान्तिकारी महिला कानूनों ने लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया है। इसने गहराई तक समायी पुरूष सत्तात्मकता को तोड़ा, कुछ समुदायों ने इन कानूनों को अन्यों की तुलना में तीव्रता से अपनाया। उदाहरणार्थ, यातायात एवं भोजन पर अत्यधिक व्यय के कारण वे परिवार जो माध्यमिक विद्यालयों से दूर निवास करते थे, अध्ययन हेतु अपनी पुत्रियों को न भेज कर पुत्रों को भेजते थे जिससे असंतुलन का पुनरोत्पादन होता था। हालांकि ऐसे अनेक संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि युवा पीढ़ी अब लैंगिक समानता को अपनाने हेतु ज्यादा तैयार है। उदाहरणार्थ कपड़ों को धोना अब महिलाओं का कार्य है, का विचार युवा पुरूषों में नहीं है। इन युवा पुरूषों को स्वयं कपड़े धोते हुए देखा जा सकता है। ठीक इसी तरफ शिक्षा के प्रोत्साहक, स्वास्थ्य प्रोत्साहक एवं स्वशासन निकायों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। समय के साथ जाप्टिस्टास के प्रति मैक्सिकों सरकार का रणनीतिक प्रत्युत्तर बदला है। शुरू में इसने मैक्सिकों एवं विदेशों में विशाल विरोध प्रदर्शनों के उपरान्त उनके सैन्य प्रचार को रोका था। अभी हाल में जाप्टिस्टास के प्रभाव क्षेत्र के ठीक पास में सरकार ने एक ग्रामीण सम्पोषित नगर एवं सभा स्थल के निर्माण को प्रारम्भ किया है। लेकिन रोजगार का वादा जो भूमि के चले जाने के बाद किसानों को आकर्षित कर सकता था, विलुप्त हो गया क्योंकि सरकारी रियायतें समाप्त हो गयी। चमकीले पेण्ट वाले बिल्कुल नये मकान अधिकांशतः खाली हैं क्योंकि निर्माण कार्य के दौरान उसमें अनेक कमियाँ पायी गयीं। हालांकि इन समुदायों में अभी सैन्य बल की घुसपैठ नहीं है फिर भी निचली ऊचाइयों पर उड़ान भरते सैन्य विमान चिन्ता व भय उत्पन्न करते हैं। जाप्टिस्टास का मत है कि चुनाव व्यवस्था में धांधली एवं बड़े पैमाने पर मीडिया के पूर्वाग्रहों के कारण वर्तमान राष्ट्रपति सत्ता में आये हैं। जाप्टिस्टास की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था इतनी भ्रष्ट है कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से सहयोग करने से इन्कार कर दिया।

जाप्टिस्टास का यह प्रतिरोध साथ ही राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। यह स्व शासन एवं निर्वाह मूलक श्रम हेतु है। वे ऐसा सामाजिक प्रारूप निर्मित करना चाहते हैं जिसमें आन्तरिक अपील विद्यमान है। सामाजिक न्याय का उनका प्रश्न स्वतंत्रता से प्रारम्भ होता है। वे इजाजत हेतु नहीं पूछते वे तो कार्य करते हैं। संरचनात्मक समायोजन नीतियों ने समूचे विश्व में गन्दी बस्तियों को उत्पन्न किया है। यह वह समय है जब विकास के नवाचारी पक्षों को धरातल से शुरू करना चाहिए। वैश्विक आकांक्षाओं एवं असमानता की समस्याओं पर बल देने वाला समाजशास्त्र तभी लाभकारी हो सकता है जबकि वैश्विक दक्षिण के परिधिमूलक देशों में जमीनी स्तर पर हो रहे संघर्षों एवं प्रतिरोधों पर अधिक ध्यान दिया जावे। ■

> सीरियाई जेल में असम्बद्ध और अवस्तुकृत (Desubjectified)

अब्दुलैह सईद, पूर्व में डमस्कस विश्वविद्यालय, सीरिया में कार्यरत

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अभियोत्ताओं के एक स्वतन्त्र दल द्वारा तैयार की गई कतारी–वित्तपोषित रिपोर्ट ने सीरियाई हिरासत केन्द्रों में भूखे और उत्पीड़ित कैदियों की लाशों की छुपा कर लाई गई हजारों तस्वीरों का विश्लेषण कर, पूर्व में भी संदिग्ध, कैदियों की ''औद्योगिक पैमाने'' स्तर पर हत्या के और सबूत प्रदान किये। यह रिपोर्ट सीरियाई मानवाधिकार के जमीनी संगठनों द्वारा वर्तमान सीरियाई शासन की जेलों में हिरासत की पाश्विक स्थितियों के समान विवरण के पश्चात आई है। यह निबन्ध तस्वीरों के बजाय गवाही पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। वस्तुतः अब सीरियाई जेलों से बचकर निकलने वाले कैदियों की गवाही के प्रचुर प्रलेखन उपलब्ध हैं। मैं इस में यह देखना चाहता हूं कि कैसे ये बंदी कारावास के स्थान में बचे, कैसे इनके शरीर ने निचान की तरफ धीमी उतार को जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा तक जिया और कैसे उन्होंने गायब होने के पूर्व अन्य बंदियों को ''असम्बद्ध'' होते देखा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या और किसी हद तक Musselmanner के विध्वंसकारी अनुभव जिसने ऑशरित्ज (Aushuritz) को प्रिमो लेवी और कई अन्य उत्तरजीवी की स्मृति में अंकित किया और जिसे हाल ही में जियोर्जियो आगमबेन ने एक प्रतिमान (पैराडाइम) में बदल दिया, हमें सीरियाई जेलों में ''असम्बद्ध'' कैदियों की वर्तमान त्रासदी और सीरियाई राजनैतिक जगत में होने वाली आपदा, दोनों को समझने में मदद कर सकता है।

कई उत्तरजीवियों की गवाही के अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन या राहत कार्य में सम्मिलित होने के कारण गिरफ्तार कैदी जो शायद हिरासत में मर गये और उनके शवों को गुप्त सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया, की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उत्तरजीवियों की गवाही अक्सर कारावास में दमित करने वाले सीमित स्थान और अधिक आबादी का कैसे ये कैदी सामना करते हैं, पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। उत्पीड़न की चरम स्थितियां अब सामान्य हो गयी हैं। हिंसा और अमानवीय दुर्दशा पूछताछ सत्र तक सीमित नहीं है अपितु वे सीरियाई हिरासत केन्द्र में एक कैदी के जीवन का अभिन्न अंग प्रतीत होती हैं।

प्रसिद्ध और अब अपहृत वकील रजन जेटओनेह द्वारा सह–स्थापित सीरियाई जमीनी गैरी सरकारी संगठन, उल्लंघन प्रलेखन समिति (Violation Documentation Centre) द्वारा एकत्रित गवाहियां इस बात का संकेत देती है कि जेलर अक्सर टूट जाने के कगार पर लाने के लिए बंदियों को भूखा रखते थे। भुखमरी दोनों, यातना की एक तकनीक और उत्तरजीवियों की स्मृति में भूख को अंकित करने एक साधन के रूप में हिरासत को सामान्य विशेषता के रूप में उपस्थित होती है। हिरासत की कठोर परिस्थितियां अक्सर ''असम्बद्धता'' को पैदा करती हैं। यहां एक उत्तरजीवी द्वारा काबोन, डमस्कस में स्थित सैन्य खुफिया हिरासत केन्द्र जहां कई कैदी उसकी कोठरी की स्थिति के कारण ''असम्बद्ध'' हो गये, का वर्णन प्रस्तुत है:

> मुझे लगभग 180 कैदियों के साथ दो गुणा पांच मीटर की एक कोठरी में रखा गया। वहां बहुत सारे ''असम्बद्ध'' कैदी थे। यह वह शब्द है जिसे हम उन कैदियों के लिए प्रयोग में लाते थे जो तीव्र यातना और कोठरी में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण स्थिति भ्रान्तिक रूप में बोलना और काम करना शुरू कर देते हैं......। हम एक या दो कैदियों को रोजाना मनोवैज्ञानिक दबाव, नमी और गर्म मौसम के कारण असम्बद्ध होते देखते थे..। कैदी विचित्र और अर्थहीन बातें कहना और करना शुरू कर देते थे......।

जब एक असम्बद्ध कैदी लुप्त हो जाता है, कोठरी और फिर हिरासत केन्द्र में से लाश को निकालने की एक व्यवस्था है। कुछ हिरासत केन्द्रों में, निकास अनुभवी कैदियों, जिन्हें मृत लाशों को इकट्ठा करके बाहर ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है, को सौंपा जाता है। अन्य हिरासत केन्द्रों में असम्बद्ध और मृत कैदियों के लिए, अधिकतर शौचालय के पास, तथा–कथित ''सांत्वना'' कमरे बनाये जाते हैं। उत्तरजीवियों की स्मृतियां कोठरी के बाहर के गलियारे पर गड़ जाती है जहां शौचालय के पास असम्बद्ध कैदियों के एकत्रित शरीर अपनी धीमी

सीरियन मूर्तिकार फादी यजीगी द्वारा बनाया हुआ तांबे का ''वृक्ष''। शिल्पकार की अनुमति से।

>>

मौत का इंतजार करते हैं। एक उत्तरजीवी द्वारा असम्बद्ध कैदियों की आंखों में देखते हुए अपने अनुभव का वर्णन यहां प्रस्तुत है :

प्रत्येक दिन करीबर बीस कैदी गलियारे में अपने ''भाग्य'' और धीमी मौत से मिलने के लिए फेंक दिये जाते हैं.....। ये मामले गंभीर यातना, असम्बद्धता या उच्च तापमान के कारण शीघ्र ही मरने वाले और वे जो बिगड़े हुए फोड़ों के कारण कंकाल की तरह दिखते थे, के मध्य पड़ते थे। वे एक ही स्थान, जो मवाद और खून से भरा था, में पेशाब करते थे। वे खत्म होने वाले थे। उनकी आंखे खुली रहती थी और उनमें ऐसी नजर को केन्द्रित करने की क्षमता थी मानों वे उन कैदियों से, जो चल सकते थे, बाह्य दुनिया को उनकी पीड़ा की गवाही देने के लिए कह रही हो।

कैदियों के अनुभव के इस विस्तारित पल जिसमें मस्तिष्क आसानी से असम्बद्ध हो जाता है या फिर कार्य करना बंद कर देता है, से व्यक्ति आक्रांतित होता है। इस क्षण में मस्तिष्क शरीर को खत्म होने के पहले एक प्रकार की निष्क्रिय स्थिति में छोड़ देता है। हाल ही में जियार्जियो अगमबेन द्वारा अपनी 2005 की पुस्तक ऑसवित्ज के अवशेष (Remnauts of Auschwitz) में प्रस्तुत ऑसवित्ज बंदी शिविर पाये गये Muselmann के चरित्र से समानांतर खींचने के लिए लालायित होते हैं। यह ऑसवित्ज का उत्तरजीवी प्रिमो लेवी था, जिसने उनकी 1946 की पुसतक If this is a man में ऑसवित्ज में SS और अन्य कैदियों द्वारा Musselmanner या मुस्लिम कहलाने वाले कैदियों के एक वर्ग के बारे में सर्वप्रथम गवाही दी थी। लेवी का वर्णन सजीव था : Musselmanner ऑसवित्ज में रहने 'डूबे हुए' या ''गैर–पुरूष'' थे। ये वो थे जो ''क्षय'' होते हुए शरीर के साथ सर झुका कर और कंधे मोड़ते हुए चुप्पी में मार्च करते थे और जिनके चेहरे और आंखों में ''विचार का कोई भी अवशेष दिखाई नहीं देता है।'' उत्तरजीवियों की गवाही के अनुसार Muselmann का ''जीवित मृत'', ''चलती फिरती लाश'', ''चलता हुआ कंकाल'', ''ममी–आदमी'' के रूप का पता अन्य यातना केन्द्रों में भी था परन्तु भिन्न नामों के अंतर्गत। Muselmann शब्द के अत्यन्त अपमानजनक रूप में प्रयोग होने व इसकी उत्पत्ति पर कम शोध हुआ हैं

Muselmann के रूप के साथ अगमबेन की दो अन्तर्सम्बन्धित प्रश्नों में दिलचस्पी थी : यातना शिविर की चरम स्थिति, जहां, नाजियों के इरादे सभी कैदियों और उनकी गवाही की किसी भी संभावना को नष्ट करने के थे, को देखना कैसे संभव था; और कैसे नाजी शक्ति ने अंततः मनुष्य को ''अवस्तुकृत'' कर दिया। अगमबेन ने दर्शाया कि कैसे 'दूसरे' को भूखा रख कर, और इस 'दूसरे' को Muselmann की स्थिति तक पहुंचा कर शक्ति अतिरिक्त समय प्राप्त करती है। वह जीवन और मृत्यु के मध्य एक ''तीसरा दायरा'' खड़ा करती है। Muselmann की स्थिति, शक्ति की मनुष्य पर विजय का प्रतीक है। यह विजय उन्हें अवस्तुकृत कर और उन्हें उनके जैविक अस्तित्व तक घटा कर प्राप्त हुई। शक्ति उन्हें अल्प जीवन में जीवित रहने देती है।

यद्यपि ''असम्बद्ध होते'' सीरियाई कैदी जो वास्तव में अपने चेतन जीवन और जैविक जीवन के अलग होने से अवस्तुकृत है, के साथ समानांतर खींचने के लिए मुझे लालच है, यह समान अनुभव यहीं समाप्त हो जाता है। वस्तुतः ऑसवित्ज के Muselmann और असम्बद्ध सीरियाई कैदी में काफी अंतर है। Muselmann की स्थिति ऑसवित्ज के लिए प्रासंगिक थी क्योंकि पूरी कार्यवाही, जिसमें गवाही की संभावना भी सम्मिलित है, विध्वंस के लिए तैयार थी। इसके विपरीत ''असम्बद्ध'' सीरियाई की स्थिति सीरियाई शासन सत्ता की समग्र मशीनरी में एक केन्द्रीय भूमिका निभाती है। 'असम्बद्ध' की छवि उदाहरण स्थापित करने का प्राथमिक कार्य करती है। इसे उत्तरजीवियों की स्मृति में अंकित होना चाहिए। उत्तरजीवियों की गवाही ''असम्बद्धता'' की स्थिति का निर्माण और उसे पूर्ण करती है। उत्तरजीवी के बिना कोई ''असम्बद्ध'' नहीं है और ''असम्बद्ध'' के बिना कोई उत्तरजीवी नहीं है। शासन द्वारा सीरियाईयों के मन में डर को बैठाने के अथक प्रयासों के हिस्से के रूप में ''असम्बद्ध'' के अनुभव को उत्तरजीवियों द्वारा बताया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीरियाई कैदियों का "Muselmannization" इस बात का उदाहरण देता है कि शासन कैसे सीरियाई राजनैतिक जगह का प्रतिनिधित्व करता है और उससे कैसे निपटता है। शासन की सत्ता मशीनरी मुख्य रूप से आबादी के एक वर्ग को नष्ट करने के लिये नहीं अपितु सार्वजनिक स्थान में किसी प्रकार के विपक्षी सामूहिक राजनैतिक दावे को विकसित करने की लोगों की क्षमताओं को खत्म करने की तरफ कार्यरत है। ऐसा वह लोगों को मात्र जैव–राजनैतिक तथ्य तक घटा कर या फिर आबादी को रेजिमेंट कर अपनी इच्छानुसार निपटाने के द्वारा करती है। औद्योगिक पैमाने पर हत्या के द्वारा विनाश और विस्थापन शक्ति का अंत नहीं बल्कि यह शासन द्वारा समाज को पुनः जीतने और वश में करने का एक माध्यम मात्र है। शांतिपूर्ण राजनैतिक लामबंदी के सामने, शासन व्यवस्था प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेती है और उन्हें नारकीय असम्बद्धता के एक स्तर पर ला कर और फिर उनमें से मृत को मात्र जैविक अपशिष्ट के रूप में फेंक कर, राजनैतिक अधिकारों की चेतना से पूर्णतया अलग करने के लिए संगठित होते हैं।

यदि हम सीरियाई हिरासत केन्द्रों के व्यक्तिगत शरीरों पर दी गई यातना और सीरियाई राजनैतिक शरीर पर की गई यातना के बीच समानांतर खींचने में सफल हो : यहां शरीर पर यातना; वहां पूरे शहरों का विनाश; कैदियों को असम्बद्ध करने के लिए जाना, सार्वजनिक चौक जहां नागरिक राजनैतिक आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होते हैं, को मिटा देना; यहां कैदियों की लाशों को फेंकना; वहां नागरिकों को बलपूर्वक हटाना? निश्चित रूप से, यह सैद्धान्तिक रूप से सरल और अरक्षणीय समानांतर है परन्तु यह सीरियाई त्रासदी के जीवित यथार्थ, जो राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए होने वाले किसी भी नागरिक और शांतिपूर्ण आंदोलन को शासन द्वारा व्यवस्थित रूप से कुचले जाने से मौलिक रूप से अंकित होता है, को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करता है। ■

> ईरान में महिलाओं की संदिग्ध प्रगति

शिरीन अहमद–निया, अलामेह–तबातबा'इ विश्वविद्यालय, ईरान

Maternal Mortality Ratio (per 100,000 live births) in Iran, 1974-2007

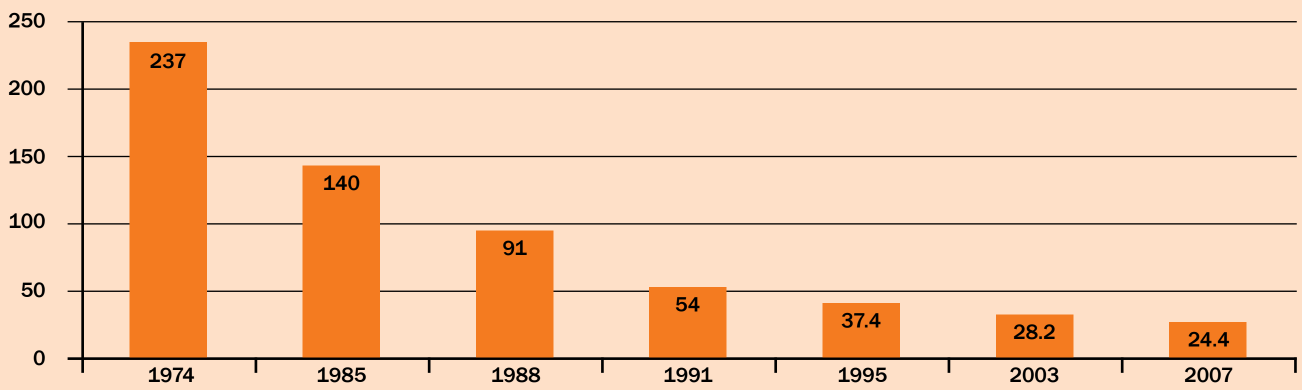

Source: "Heath Profile Indicators in the Islamic Republic of Iran", Center for Health Network Development & Health Promotion, Ministry of Health and Medical Education, 2009

1979 के इस्लामिक आंदोलन के बाद से ईरानी समाज में सामाजिक–राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, ऐसे परिवर्तन जो परिवार, शिक्षा और नगरीय जीवन के नये प्रतिमानों में विशेष रूप से दिखाई देते हैं।

ईरान में आंदोलन के ठीक पहले, आधे से कम (47%) लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे जबकि 2011 की अंतिम राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, यह आंकड़ा 71% तक बढ़ गया है। पिछले 50 से भी अधिक वर्षों में (1956 से 2011), शहरी ईरानियों की कुल साक्षरता दर 39.5% से बढ़ कर 88.9% हो गई है जबकि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लैंगिक अन्तर बहुत तेजी से कम हुआ है।

औपचारिक आंकड़ों के अनुसार, ईरान के 10 परिवारों में से एक परिवार में महिला मुखिया है और अकेली, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि सांस्कृतिक विश्वास औपचारिक क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के विरूद्व कड़ाई से कार्य करते हैं। "पुरुष ही मुखिया या केवल कमाने वाला है" जैसे लैंगिक पृथक्करण के पारंपरिक मूल्य महिलाओं की आधिकारिक श्रम बाजार तक सरल पहुंच को बाधित करते हैं। जिसके फलस्वरूप महिलाओं की आर्थिक गतिविधि दर अभी भी आंदोलन के पहले के समान ही, 12% के थोड़ी ही उपर है। यह आज शैक्षिक क्षेत्र में महिलाओं की फलती–फूलती उपस्थिति के विपरीत है और विशेष रूप से विषयों में बढ़ती महिला विश्वविद्यालय स्नातकों की संख्या जिनके लिए बेरोजगारी की दर पुरूषों से लगभग दुगुनी है।

श्रम बाजार में महिला भागीदारी के विरूद्व भेदभाव के बावजूद, महिलाओं की उच्च शैक्षणिक उपलब्धियां, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक उनकी बढ़ती हुई पहुंच, सांस्कृतिक वैश्वीकरण लाने वाली सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विस्तृत प्रयोग और अतः उनकी नये विचारों और आदर्शों के साथ अंतरंगता, सबने युवा महिलाओं की लैंगिक पहचान में उल्लेखनीय परिवर्तन उत्पन्न किये हैं।

महिलाओं की युवा पीढ़ी ने पत्नी और मां की पारंपरिक भूमिकाओं से परे, सामुदायिक और सांस्कृतिक घटनाओं के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के पक्ष में, लैंगिक पहचान को पुनः

>>

परिभाषित किया है। सांस्कृतिक बाधाओं के बावजूद, 'सार्वजनिक क्षेत्र' में उनके प्रवेश ने महिलाओं को सशक्त किया है और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर किया है। अपनी परिष्कृत सामर्थ्य और क्षमताओं के साथ, ये महिलाएं अपनी नई व्यक्तिगत पसंद के कारण नये परिवार प्रतिमानों और जीवन शैली की ओर अग्रसर हैं।

गहरे रूप से पारंपरिक समाज, जो शाह के युग की आधुनिकीकरण की नीतियों से वास्तव में अछूता था, में जहां कम उम्र में विवाह (यौवन के आस पास) किशोरों की बुनियादी जरूरतों का स्वीकार्य प्रत्युत्तर था। वहां पिछले 50 से अधिक वर्षों (1956 से 2011) में प्रथम विवाह के समय महिलाओं की औसत आयु 18 से 24 वर्ष हो गई है। उसी अवधि के दौरान, परिवार के औसत आकार में एक क्रमिक गिरावट हुई (4.8 से 3.5 व्यक्ति) और औसत प्रजनन दर में भी 6 जन्म प्रति महिला से करीबन 2 जन्म प्रति महिला से भारी कमी आई है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर जो 1955–65 में अपने उच्चतम स्तर पर थी (3.91%), 2011 में 1.29% तक सीधी गिर गई है।

1989 में परिवार नियोजन कार्यक्रम के पुनरूद्धार के बाद से, गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने वाली विवाहित महिलाओं का प्रतिशत 74% के करीब बढ़ गया है। इससे जन्म दर और अवांछित गर्भधारण की संख्या में कमी आई है। इसके परिणामस्वरूप 1973 में 237 (प्रति 100,000 जीवित जन्म) से 2010 में 10 के मातृ मृत्यु अनुपात में उल्लेखनीय कमी आई है। महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य उच्च जीवन प्रत्याशा, जो 2011 में लगभग 75 वर्ष हो गई, में प्रतिबिम्बित होता है।

इन सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनों ने स्वतन्त्र जीवनसाथी चयन, विवाह पूर्व अंतरंग सम्बन्ध और परिवारों के टूटने में योगदान दिया है। जीवनसाथी का चयन, अब विश्वविद्यालयों, कार्यस्थलों, पार्क, शॉपिंग मॉल, इंटरनेट फोरम, चेट रूम, सड़क पर और यहां तक कि धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकाण्डों के दौरान, जहां कहीं भी युवा लोगों को मिलने और दोस्त बनाने का स्थान मिलता है, में होता है। विवाह एक दशक पहले की तुलना में बुजुर्ग और शादी तय करने वाले पारंपरिक लोगों से बहुत कम नियंत्रित होते हैं। तलाक की अभूतपूर्व उच्च दर (तेहरान में 2012 में सभी विवाहों का एक–तिहाई तलाक में अंत) ने विवाह सम्बन्धों के कम प्रचलित प्रकारों जैसे गैर स्थायी इस्लामी (शिया) विवाह (Sighe or Mot'e) की संख्या में वृद्धि की है। यह उच्च जोखिम वाले यौन व्यवहार, विवाह–पूर्व और विवाहेत्तर सम्बन्धों की बढ़ती मात्रा की धार्मिक प्रतिक्रिया है।

किशोरों और युवाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों पर बहुत अल्प राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान है लेकिन स्थान स्तर पर सबूत दर्शाते हैं कि लड़के और लड़कियों की पहले यौन अनुभव की उम्र किशोरावस्था तक गिर गई है। इसके अलावा, गैर पारंपरिक सम्बन्धों ने तथा–कथित ''उच्च जोखिम व्यवहार'', जो युवाओं को यौन संचारित रोग जैसे एच आई वी/एड्स से परिचय कराता है, में वृद्धि की है। यह सब मनोरंजन जीवन शैली और अवकाश गतिविधियों में परिवर्तन जो काले बाजार में सस्ती दरों पर आसानी से उपलब्ध आधुनिक नशीले पदार्थों और शराब की खपत को प्रोत्साहित करती है, से और संयोजित होता है। इन गतिविधियों, जिनमें से किसी को भी धर्म और कानून द्वारा अनुमति नहीं है, का इस देश में प्रकट होने के रूझान ने ही परिवारों और अधिकारियों दोनों को घबरा दिया है। ■

> यूरोमैदान विद्रोह का पार्श्व चित्र

व्लोदिमिर पनिओट्टो, कीव मोहयला अकादमी का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, महानिदेशक, कीव इंटरनेशनल इंस्टीटयूट ऑफ सोशियोलोजी (KIIS) एवं सदस्य, आई.एस.ए. की तर्क एवं पद्धतिशास्त्र की शोध समिति (RC 33)

लोकप्रिय यूक्रेनी रॉक बैण्ड, ओकियन एल्जी (''एल्जाज ओशन'') 14 दिसम्बर 2013 को मैदान में प्रदर्शन करते हुए।

'मैदान' एक अद्वितीय समाजशास्त्रीय प्रघटना है। 'भीड़', 'बैठक' या 'प्रदर्शन' जैसी शब्दावली इसके गतिशील चरित्र को पर्याप्त रूप से दर्शा नहीं पाते हैं। तकनीकी तौर पर 'मैदान' कीव में स्वतन्त्रता चौक को संदर्भित करता है लेकिन अब यह लगातार बदलते हुए शिविर जिसमें एक तम्बू शहर और प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा की गई कई आसन्न इमारतें सम्मिलित है, से अमिट रूप से जुड़ गया है। यूरोमैदान के गतिवाद और घटनाक्रम को चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है।

> पहला चरण : प्रतिरोध शुरू होता है।

28–29 नवम्बर (2013) को यूक्रेन और यूरोपीय संघ ने विलनियस में ''पूर्वी भागीदारी'' शिखर सम्मेलन में एक संघीय करार पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। तथापि, यूक्रेनी आबादी को आश्चर्यचकित करते हुए यूक्रेनी प्राधिकारियों ने इस करार पर हस्ताक्षर करने की तैयारियों को निलंबित कर दिया। प्रथम मैदान बैठक 2004 की आरेंज क्रांति के बाद सबसे बड़ा जमाव, 24 नवम्बर को हुई जिसने 50 से 100 हजार लोगों को एकजुट किया। EU के समर्थक स्वतन्त्रता चौक में तम्बू लगाने लगे और सैकड़ों लोग रातभर वहीं रहे। यूक्रेनी भाषा में चूंकि 'मैदान' का अर्थ चौक होता है,

>>

उत्तरगामी रैलियाँ और स्थायी तम्बू–शहर 'यूरोमैदान' कहलाने लगे।

> दूसरा चरण : प्रदर्शन–कारियों पर हमला और उनकी बदलती प्रोफाइल

30 नवम्बर को सुबह 4 बजे, पुलिस की विशेष शाखा, 'बेरकुट' (गोल्डन इगल) के कई सैंकड़ों सदस्यों ने यूरोपीय एकीकरण के समर्थकों, विशेष रूप से मैदान में एकत्रित युवा लोगों को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। यह महज चौक से निष्कासित होने से कहीं ज्यादा था–प्रदर्शनकारियों को लातें और लाठियां मारी गई और उनका खेरचाटय्क (Khreschatyk) (मुख्य सड़क) और योजक सड़कों पर सेंट माइकल कैथेड्रल तक, जहां भिक्षुओं ने द्वार खोल भागते छात्रों को छुपा लिया, पीछा किया।

इन घटनाओं ने सार्वजनिक हो–हल्ला/चिल्लाहट को पैदा किया। तदनुसार, आगामी रविवार (8 दिसम्बर) को न सिर्फ कीव से बल्कि सभी आसपास के क्षेत्र, मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्रों से प्रदर्शनकारियों की रिकॉर्ड भीड़ 7 लाख और 1 करोड़ के मध्य अनुमानित मैदान और उसके आसपास की सड़कों पर उतर आई। मैदान में कौन आये और उनकी क्या मांगे थीं? डेमोक्रेटिक इनिशियेटिवस फाउण्डेशन ने प्रदर्शनकारियों के सर्वेक्षण को कमीशन दिया जिसे कीव इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलोजी (KIIS) ने 7 और 8 दिसम्बर को सप्ताहांत में संचालित किया। हमने 1037 साक्षात साक्षात्कार किये। अनुवर्ती सर्वेक्षण 20 दिसम्बर को कार्य दिवस पर किया गया और इसमें सिर्फ मैदान शिविर में रहने वालों को सम्मिलित किया गया।

हमारे द्वारा प्रयोग में लाई गई पद्धति के बारे में कुछ शब्द कहना आवश्यक है। हमें यह जल्दी ही पता चल गया कि एग्जिट पोल और सड़क साक्षात्कार का हमारा अनुभव इस लगातार बदलते संदर्भ में, जहां मैदान में स्थायी रूप से रहने वालों की संख्या 5 से 20 हजार के बीच में झूल रही थी, लेकिन रविवार की रैली में 1 लाख तक पहुंच सकती थी, बहुत काम का नहीं था। अतः स्थिर संदर्भ के लिए डिजाइन की गई हमारी प्रचलित पद्धति में संशोधन की आवश्यकता थी। हमारी निर्देशन तकनीक ने मैदान (कब्जा की गई इमारतें भी सम्मिलित) के क्षेत्रों को चिन्हित किया और हमने प्रत्येक में से दैव रूप से साक्षात्कारदाताओं को चुन लिया। प्राप्त परिणामों को प्रत्येक क्षेत्र की अनुमानित संख्या के आधार पर भारित किया। भवनों/इमारतों में रहने वालों के मामले में मानक एग्जिट पोल प्रक्रिया को अपनाया अर्थात् पूर्व निश्चित अंतरालों पर भवन/इमारत से निकलने वाले लोगों का साक्षात्कार किया गया।

मैदान के लिए, हमने चौक में कई साक्षात्कार स्थल सीमांकित किये। साक्षात्कारकर्ता के बगल से एक तीन मीटर की रेखा खींची गई और इस रेखा को पार करने वालो सभी लोगों को साक्षात्कार किया जाना था। तथापि व्यवहारिक तौर पर रेखाएं दिखाऊं नहीं थी अतः साक्षात्कारकर्त्ताओं ने स्वयं को किसी एक प्रमुख वस्तु के मध्य काल्पनिक रेखा खींची। साक्षात्कारों का पर्यवेक्षकों ने अवलोकन किया और प्रत्येक साक्षात्कार स्थान का विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित लोगों की संख्या के अनुमान हेतु उपर से फोटो चित्र खींचा गया ताकि परिणामों को भारित किया जा सके।

लोगों को मैदान में आने के लिए दो प्रमुख प्रेरक तत्व थे : 30 नवम्बर की रात को मैदान में प्रदर्शनकारियों की क्रूर पिटाई (70%) और यूरोपीय संघ के साथ संघीय करार पर हस्ताक्षर करने से यानुकोविच का इंकार (54%)। प्रतिरोध में शामिल होने के अन्य प्रेरकों में यूक्रेन में जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा 50% और देश की शक्ति संरचना में बदलाव लाना 39% सम्मिलित थे। मैदान के प्रतिवादियों ने निम्न मांगे रखी : गिरफ्तार किये गये प्रदर्शनकारियों की रिहाई और दमन को रोकना (82%); सरकार का इस्तीफा (80%); यानुकोविच के इस्तीफे के बाद जल्दी राष्ट्रपति चुनाव (75%); EU के साथ संघीय करार पर हस्ताक्षर करना (71%); मैदान प्रदर्शनकारियों के विरूद्ध हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध आपराधिक जांच और अभियोग शुरू करना (58%)। संक्षिप्त रूप में, हम कह सकते हैं कि मुख्य मांगे सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के मुद्दों पर केन्द्रित थीं। इसी कारण पत्रकारों ने इस प्रतिरोध को ''आदर की क्रांति'' कहा।

स्थायी मैदान शिविर और मैदान रैलियों की तुलना करते हुए यह देखा कि पहले में कीव के बाहर के लोगों का स्पष्ट वर्चस्व था (81%) जबकि परवर्ती में कीव निवासियों का वर्चस्व था (57%)। गैर निवासियों में पश्चिमी यूक्रेन के प्रदर्शनकारियों का दोनों ही मैदानों में वर्चस्व था (रैलियों में 52% और शिविर में 42%) जो शिविर में अन्य क्षेत्रों से थोड़े उच्च अनुपात की ओर इंगित करता है। रैलियों में शिक्षा का स्तर भी काफी उच्च था : कॉलेज शिक्षित 64% थे जबकि अपूर्ण कॉलेज शिक्षा प्राप्त 13% थे। व्यवसाय के संबंध में, तकरीबन 60% पेशेवर, उद्यमी और प्रबंधक थे। अन्य शब्दों में रैलियों में भाग ले रहे अधिकांश प्रतिभागी मध्यम वर्ग से थे। यद्यपि शिविर पर पेशेवरों का अनुपात रैलियों से आधे से भी कम था और कॉलेज डिग्रीधारी रहने वालों के 50% से भी कम थे।

> तीसरा चरण : मैदान का अतिवादीकरण

मैदान सप्ताह दर सप्ताह चलता रहा परन्तु इसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और प्रदर्शनकारी लगातार गिरफ्तार होते रहे। शून्य से 10 डिग्री नीचे तापमान में तम्बुओं में रहने वाले प्रदर्शनकारी और उग्र हो गये। 16 जनवरी को संसद ने सख्त कानून पारित किये जिसमें प्रतिरोध पर दंड में उल्लेखनीय वृद्धि की गई। (पत्रकारों ने इसे ''तानाशाही'' कहा) इन कानूनों से क्रोधित प्रदर्शनकारियों ने मैदान से संसद तक का एक मार्च आयोजित किया जिसे पुलिस ने रोक दिया। ग्रूशेवस्कोवो सड़क पर खड़े किये गये बैरीकेड़ पास हुए झगड़े में कई लोग घायल और कई मारे गये। इसके अलावा, अज्ञात घुसपैठियों ने प्रदर्शनकारियों को अगवा किया और जंगलों में ले जा कर बेरहमी से पीटा। एक कार्यकर्त्ता मृत पाया गया और कई अन्य गुमशुदा थे।

3 फरवरी को KIIS ने डेमोक्रेटिक इनिशियेटिवस के साथ मैदान के सर्वेक्षण को दोहराया (पूर्व वाला 20 दिसम्बर को हुआ था) इन एक–डेढ़ महीनों में मैदान सैन्य छावनी : ''मैदान सिच'' ('सिच' यूक्रेनी स्वतन्त्रता के प्रतीक जेपोरोजियन कोसेक्स के शिविर को इंगित करता है) बन गया। प्रतिरोध के अधिक उग्रवादी रूप को अपनाने को तैयार लोगों में वृद्धि हुई : सरकारी इमारतों पर धरना देने के पक्ष की संख्या 38% से 56% हो गई; इमारतों पर कब्जा करने के पक्ष वाले 19% से 41% हो गये; समनान्तरण शक्ति संरचना और सैन्य टुकड़ियों को खड़े करने के पक्ष वाले 31 से 50% हो गये। राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षण और दैनिक समाचार पूरे देश में नजरियों में कट्टरता की तरफ इशारा कर रहे थे। मैदान के प्रति नजरिया क्षेत्र के अनुसार भिन्न था। यूक्रेन के क्रीमिया सहित सभी क्षेत्रों में 8 फरवरी और 18 फरवीर के मध्य KIIS द्वारा कराये गये सर्वेक्षण (2032 साक्षात

>>

साक्षात्कार) के अनुसार सम्पूर्ण देश की 40% जनसंख्या मैदान का समर्थन करती है लेकिन यह समर्थन पूर्व में 8% से पश्चिम में 80% तक बदलता है।

> चौथा चरण: हिंसक दमन और मैदान के लिए विजय

18 फरवरी को जब मैदान पर हमला करने की तैयारियां चल रही थीं, स्थिति और खराब हो गई। पुलिस ने मैदान को चारों तरफ से घेर लिया था, कब्जा की गई इमारतों में बन्दूकधारी दाखिल हो गये और मुठभेड़ शुरू हो गई जो 19 और 20 फरवरी को छोटे मोटे रूकावट के रात–दिन चलते रहे। दोनों तरफ से हथियारों का प्रयोग हुआ। इन तीन दिनों में बेरकुट के पाँच पुलिसकर्मिया सहित 100 से भी अधिक प्रदर्शनकारी या तो मारे गये या फिर चोटों से मर गये। इसके साथ 1500 से अधिक लोग घायल हुए और करीबन और 300 बिना किसी सुराग के गुम हो गये। यह देश के लिए बहुत बड़ा सदमा था। 21 फरवरी के संसदीय सत्र में, सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्यों ने विपक्ष का समर्थन किया और संसद ने सेना को वापिस बुला बैरकों में उन्हें भेजने के लिए मतदान किया।

> यूक्रेन के वर्तमान संकट में आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं?

समर्थन में प्रतिक्षण	क्षेत्र				
	पूरा यूक्रेन	पश्चिम	मध्य	दक्षिण	पूर्व
सरकार और यानुकोविच	23	3	11	32	52
प्रदर्शनकारी	40	80	51	20	8
किसी के भी तरफ नहीं	32	13	33	42	39
कहना मुश्किल है	5	4	6	7	1

उसी समय, पोलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस और रूस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति यानुकोविच ने संकट को समाप्त करने के लिए विपक्ष के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये। हालांकि उसी दिन शाम को वे अचानक गायब हो गये। उन्हें रोकने व हिरासत में लेने की कोशिशें की गई परन्तु वे रूस भागने में सफल हो गये। अतः संसद ने एक नई सरकार नियुक्त कर राष्ट्रपति के चुनाव घोषित किये और संविधान का अनुसरण करते हुए, अध्यक्ष ने अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया।

इस तरह से यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। ■

> क्रांति अभी शुरू भी नहीं हुई है

व्लोदिमिर इशचेंको, कीव मोह्यला अकादमी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, और उप निदेशक, सेन्टर फॉर सोसाइटी रिसर्च, कीव, यूक्रेन

16 जनवरी 2014 को संसद द्वारा पारित नागरिक स्वतन्त्रता को प्रतिबन्धित करने वाले दमनकारी कानूनों के कारण मैदान जन हिंसा में बदल गया।

यह जानते हुए कि यूक्रेन में घटनाएं पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अलगाववादी रैलियों और क्रीमिया में रूसी सैन्य हस्तक्षेप से जोर पा तेजी से विकसित हो रही हैं, सैद्धान्तिक सामान्यीकरण के प्रयासों को अनिश्चित ही रहना होगा। फिर भी, राष्ट्रपति यानुकोविच का शासन गिरा दिया गया है; नई सरकार यूक्रेनी राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों पर लगभग कुशलता से नियंत्रण कर रही है और उसने पहले राजनैतिक और आर्थिक सुधारों की घोषणा की है।

कई विश्लेषकों एवं सक्रिय कार्यकर्त्ताओं ने इन घटनाओं को ''क्रांतिकारी'', ''राष्ट्रीय'', ''लोकतांत्रिक'', ''औपनिवेशिक–विरोधी'' या ''बुर्जआ'' का नाम दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन में जो कुछ हुआ वह (मुख्य रूप से पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में संकेन्द्रित और पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों से बहुत कम समर्थित) संसदीय दलों के कमजोर निर्देशन एवं झगड़े से पूर्ण नेतृत्व में यूक्रेनी आबादी के एक हिस्से द्वारा विद्रोह था, जिसने पुलिस और सशस्त्र अर्द्ध–सैनिक समूहों के बीच (अंतिम चरणों में) हिंसक टकराव सम्मिलित

>>

था। इसका परिणाम सत्तारूढ़ कुलीन वर्ग में परिवर्तन था। यद्यपि कुछ राजनीतिक वैज्ञानिक दावा करते हैं कि यह इसे एक प्रकार के ''टिली टाइप'' क्रांति कहने के लिए पर्याप्त होगा, लोकप्रिय लामबंदी के कारण कुलीन वर्ग में परिवर्तन क्रांतियों में रूचि पैदा करने के लिए काफी नहीं है। इसके बजाय, हम आम तौर पर किसी सम्भावी उग्र संस्थागत, संरचनात्मक परिवर्तन को ढूंढते हैं और आशा करते हैं। क्या यह क्रांति यूक्रेन के वर्ग या सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव लायेगी? अर्थव्यवस्था की उल्लेखनीय बुलंदियां वही पुराने कुलीन वर्ग–राज्य के करीबी वित्तीय–औद्योगिक समूहों के नियंत्रण में है। इसके अलावा, वे अब केन्द्र और स्थानीय सरकारों दोनों पर अधिक प्रकट रूप से नियंत्रण प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेनी ''चाकलेट किंग'' पेट्रो पोरोशेन्को (जिसने दोनों युशचेन्को और यानुकोविच सरकारों में कार्य किया) आने वाले राष्ट्रपति चुनावों में सबसे अधिक संभावित विजेता के रूप में उभरे हैं। अब जो विपक्षी क्षेत्र हैं, उनमें अपने शासन को वैधता प्रदान करने और रूसी हस्तक्षेप के समक्ष राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के प्रयासों में नई सरकार ने यूक्रेन के सबसे अमीर लोगों से कुछ (इवान कोलोमोइस्की, सरहिये तारूता) को यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों में क्षेत्रीय गर्वनर नियुक्त किया।

राजनैतिक संकट अधिक बहुलवादी होता जा रहा है लेकिन इसका अर्थ अधिक लोकतांत्रिक संस्थाएं शायद ही है। यानुकोविच ''परिवार'' द्वारा सत्त पर एकाधिकार स्थापित करने के प्रयासों को एक अधिक सामूहिक कुलीन तंत्र के पक्ष में प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। यद्यपि 2004 के नये संविधान ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर, संसद को अधिक शक्तियां दीं, लेकिन यह बहुत कम ज्यादा लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। संसद के चुनाव पार्टी सूचीयों के लिए मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर पूरी तरह से आयोजित किया जायेगा। संविधान पार्टी सूची में कौन उम्मीदवार होगा पर लोगों के नियन्त्रण के लिए कोई तरीका प्रस्तावित नहीं करता है (उदाहरण के लिए प्राइमरी के माध्यम से)। पार्टी सूचियों पर पार्टी नेतृत्व के पास लगभग असीमित शक्ति है जिसमें उन्हें यह अधिकार है कि वे असहमत सांसदों को संसदीय समूहों से बाहर कर सकते हैं जो इस मामले में स्वतः ही जनादेश खो देते हैं। यह संभव है कि संसदीय नियंत्रण के नियम 16 जनवरी 2014 के हादसे, जिसमें संसद ने कार्यप्रणालियों को दरकिनार कर और संविधान का उल्लंघन कर भाषण की स्वतन्त्रता और शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले दस कानून पारित किये, की पुनरावृत्ति कर सकते हैं।

मैदान आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों में से एक, एक महत्व पूर्ण समस्या जिसने लोगों को सड़क पर उतार दिया और नई सरकार की कार्य योजना के केन्द्र में मुद्दों में से एक राजनीतिक शासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार से लड़ना है। यह मुद्दा चाहे नव उदारवादियों के लिए लोकप्रिय शब्द हो परन्तु इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। शक्तिशाली अभिजात वर्ग के नजदीकी कुछ लोगों के पक्ष वाली अनौपचारिक प्रक्रियाओं के स्थान पर प्रभावी एवं पारदर्शी संस्थाओं की स्थापना यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण आधुनिक भेदन होगा। यद्यपि यह संदिग्ध है कि इन मुद्दों को यूक्रेनी समाज में असमानता और गरीबी को चुनौती दिये बिना निपटा जा सकता है। अभी तक हमने सिर्फ उल्टा देखा है–सरकार ने अत्यधिक आवश्यक ऋण लेने हेतु IMF की मितव्यत्तता की प्रत्येक कार्यवाही की शर्त के तत्परता से स्वीकारने की घोषणा की है। इससे आर्थिक असमानता और बदतर होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार के उच्च हलकों के संचालन में अधिक पारदर्शिता की तरफ कदम, यूक्रेन के परिधिय पूंजीवाद के संदर्भ में अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाये रखने के लिए सभी प्रकार के अनौपचारिक राज्य लाभ पर निर्भर कुलीन तंत्र द्वारा समर्थित नहीं होगा। यूरोपीय निगमों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र में खुली प्रतिस्पर्धा में चयनात्मक संरक्षण और राज्य के संसाधनों तक पहुंच और भी अधिक महत्वपूर्ण होगी। यूक्रेनी राष्ट्रीय पूंजी के विस्तार को सीमित करने वाला सबसे सशक्त कारक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा है, अतः राज्य संरक्षण, जो स्वयं यूरोपीय संघ और रूस के प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना कर रहा है, का महत्व है। विरोधाभास यह है कि यूक्रेन का औपनिवेश–विरोधी आंदोलन देश की आर्थिक निर्भरता में वृद्धि करता प्रतीत होता है।

अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के संदर्भ में यानुकोविच के उच्च तीव्रता वाले परन्तु असंगत दबाव/बाध्यता से भिड़ने के लिए हिंसा प्रभावी साबित हुई है।[2] तथापि, इसके भी कई हानिकारक परिणाम हैं। उनमें से एक प्रकट नव–नाजी समूह को सम्मिलित करते हुए 'दक्षिणी क्षेत्र' गठ बंधन का आरोही कैरियर था जिनके मैदान प्रतिरोध हाशिये से मध्य में तीव्रता से स्थापित हुए और तीन महीनों के अन्दर यूक्रेनी राजनीति में एक प्रभावशाली कारक बन गये। फिर भी इन प्रतिरोधों को जैसा रूसी मीडिया और कुछ वामपंथी विश्लेषकों द्वारा वर्णित किया गया है–'फासीवादी तख्तापलट' नहीं कहा जा सकता है–क्योंक ऐसा कहने का अर्थ उपर से शक्ति का संगठित सैन्य अधिग्रहण होगा जो कि यूक्रेनी घटनाओं को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। सामान्य तौर पर दक्षिणपंथी क्षेत्र और मैदान आंदोलन सत्ता में आने वाली राजनैतिक दलों के कदाचित ही नियंत्रण में थे। दक्षिणपंथी क्षेत्र के पास हथियार हैं (पुलिस विभाग से छीनी गई बंदूकों के कारण) और इन्हें एक सफल लोक विद्रोह के नायक के रूप में कुछ लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ है।

पूर्व के महान क्रांतियों के मामलों की भांति, विदेशी हस्तक्षेप, यूरो मैदान में पाये गये कमजोर मुक्ति संभाव्यता में भी जहां उभरती राष्ट्रवादी भावनाओं ने सरकार और अन्य सामाजिक एजेण्डा पर नागरिक नियंत्रण को दबाया, में कटौती लाने का महत्व पूर्ण कारक है। अतः यदि एक बार पुनः सामाजिक–आर्थिक अशांति उभरी–इस बार सरकार के मित्तव्यतता के नये उपायों और उसके प्रकट कुलीनतंत्र शासन के खिलाफ–यह संभवतः तुलनात्मक रूप से कमजोर नव–वामपंथ नहीं अपितु लोकप्रिय चरम दक्षिणपंथी के नेतृत्व में होगी। इस तरह यह सांस्कृतिक रूप से विभाजित देश के लिए अतिआवश्यक व्यापक सर्व राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा और ऐसे में संभावना है कि यह सामाजिक रूपांतरण की तरफ अग्रणी हुए बिना ही राज्य विघटन की गतिकी को भड़कायेगा। ■

[1] http://www.psa.ac.uk/insight-plus/blog/ukraine%E2%80%99s-euromaidan-tilly-an-revolution-can-lead-second-crimean-war

[2] http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2014/02/26/why-ukraines-yanukovych-fell-but-so-many-analysts-including-me-predicted-he-would-survive/

> मानवीय विकास रूपान्तरण

युआन त्सै ली, अध्यक्ष, इंटरनेशनल कौंसिल ऑफ साइंस व भूतपूर्व अध्यक्ष एकेडेमिया सिनिका, ताईवान एवं
एंड्र्यू वी–ची यांग, विशेष सहायक, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएसयू

"ना तो क्रमिक विकास और ना ही बढ़ती हुई ठठेरागिरी पर्याप्त होगी"

कुछ वर्ष पहले एक बैठक में हम लोग भयानक जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए विकास पर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता पर विचार कर रहे थे, तभी एक अफ्रीकी साथी ने कहा–"नहीं। हमारे लोग दयनीय स्थिति में हैं। हमें विकास की आवश्यकता है और अगर इसका अर्थ पृथ्वी को नष्ट करने से है तो हम सभी को साथ ही मरना चाहिए।

इन शब्दों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। जितना हम सभी एक साथ मरने के लिए असहमत हैं उतना ही इन शब्दों ने इस सत्य को संप्रेशित किया कि दुनिया के गरीब व भूखे लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है। हर मानवीय आत्मा को इसकी जरूरत है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह अन्यायपूर्ण दुनिया है जहां 1.3 बिलियन व्यक्तियों को बिजली सुलभ नहीं है, 2.5 बिलियन 2 डॉलर प्रतिदिन से कम पर गुजारा करते हैं जबकि अमीर संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हैं।

निःसंदेह वे बहुत अधिक उपभोग करते हैं। आज के समय में मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले संसाधनों का 50% अधिक उपयोग कर रहा है।[1] 2012 में दुनिया के 105 विज्ञान विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए आवाज उठाई थी कि अतिशय उपभोग और अतिशय जनसंख्या पृथ्वी पर भयंकर दबाव डाल रहे हैं।[2] हम जिस गति से बढ़ रहे हैं, विज्ञान की भविष्यवाणी है कि इस शताब्दी में पृथ्वी का तापमान 4°C तक बढ़ जाएगा। मौसम परिवर्तन होगा, कई प्रजातियां सामूहिक रूप से नष्ट हो जाएंगी व लाखों लोगों को विपत्ति के कारण विस्थापित होना होगा।

21वीं सदी में ऐसी मानवीय दशा होगी जिसमें सीमित संसाधन होंगे तथा मानवीय दबाव को सहने की सीमित क्षमता होगी, जबकि 7 बिलियन लोग पहले ही अधिक उपभोग कर उसे प्रभावित कर रहे हैं। अभी 2.5 बिलियन लोग बहुत कुछ पाने के हकदार हैं, 2050 तक ऐसे 2 बिलियन लोग और उनमें जुड़ जाएंगे।

> पृथ्वी को नष्ट किए बिना, मनुष्य अच्छी तरह कैसे रह सकता है?

यह विश्वास करना कि विकास का वर्तमान तरीका ही कारगर है, मूर्खतापूर्ण है। 7 बिलियन लोगों के साथ यह मॉडल जिसमें उपभोग और वृद्धि को प्राथमिकता हो–दुनिया के करोड़ों लोगों को आश्रित बनाने तथा पर्यावरण को छिन्न–भिन्न कर देने वाला है। 9–10 बिलियन लोगों की स्थिति में तो यह संभवतः इस ग्रह को तथा मानव कल्याण के रूपों को नष्ट ही कर देगा।

> हमें दूसरा मार्ग खोजना होगा–

धरती जितना कुछ दे सकती है उस सीमा के अन्तर्गत अगर हम सभी को गरिमामय जीवन देना चाहते हैं तो हमें अपने विकास के मार्ग को पूर्णतः रूपान्तरित करना होगा। ना तो क्रमिक विकास और ना ही बढ़ती हुई

> >

ठठेरागिरी पर्याप्त होगी। पूर्णतः रूपान्तरण की आवश्यकता है। आप पूछ सकते हैं यह रूपान्तरण क्या होगा, टिकाऊ या स्थायी विकास जैसा होगा? बहुत संभावना है यह व्यक्तियों की सृजनात्मकता एवं ज्ञान के साथ बहुआयामी रूपों के उद्भवन के रूप में होगा किंतु उसे निम्न उद्देश्यों को आवश्यक रूप से पूर्व करना होगा :

- स्थायी विकास को पृथ्वी तथा जीवन को सहायता देने की उसकी क्षमता की रक्षा करनी होगी क्योंकि वर्तमान एवं आगामी पीढ़ियों का जीवन इस पर ही निर्भर है।[4]
- स्थायी विकास की वृद्धि पर एक सीमा लगानी होगी–खास तौर पर जनसंख्या एवं उपभोग पर क्योंकि सीमित ग्रह में असीमित वृद्धि असंभव है।
- स्थायी विकास समानतापूर्ण होना चाहिए क्योंकि "समानता के बिना यह मेरा ग्रह है और हम इसके सेवक हैं" की स्वामित्व की भावना का विकास संभव नहीं है।

एक वाक्य में कहें : स्थायी विकास का अर्थ वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूर्ण करना है जो कि समानतापूर्ण तथा पृथ्वी की क्षमता की सीमाओं के मध्य हो।

> समाजशास्त्री (व सभी समाज वैज्ञानिक) क्या योगदान दे सकते हैं?

वास्तव में वास्तविक प्रश्न यह है कि वे क्या नहीं कर सकते? इस समस्या की मूल जड़ भौतिकवादी अवधारणा नहीं बल्कि असंतुलित मानव विकास का कारण इसकी संख्या, व्यवहार एवं मूल्य हैं। अलग शब्दों में यह समाज विज्ञान का ही क्षेत्र है तथा स्थायी विकास का मुख्य युद्ध इसके द्वारा ही लड़ा जाएगा।

आप पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान एवं तकनीक के विषय में क्या है? निश्चय ही वे 'लो कार्बन सोसाइटी' के निकट ले जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं किन्तु वे इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। वास्तविक तथ्य यह है कि विज्ञान व तकनीक अधिकतर संसाधनों के दोहन, उपभोक्तावाद तथा अतिशय विकास के जिम्मेदार रहे हैं क्योंकि राष्ट्रों और लोगों का सपना पर्यावरण संरक्षण नहीं होता है। जब तक राष्ट्र अनंत वृद्धि और उपभोग का सपना देखते रहेंगे 'हरित तकनीक' का उपयोग भी उन्हें पृथ्वी को विकास झेलने लायक नहीं बना पाएगा।

किंतु यदि हम इन सपनों तथा उनसे जुड़े मूल्यों, व्यवहार एवं संस्थानों को रूपान्तरित करने में सफल हो जाएं तो हम तकनीक द्वारा प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को भी परिवर्तित करने में सफल हो जाएंगे और इस रूपान्तरण के लिए समाज विज्ञान प्रासंगिक ही नहीं बल्कि अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं। हस्तक्षेप के संभावित क्षेत्र अनेक हैं। उनमें से तीन हैं :

1. 'विकास' एवं 'आवश्यकता' की हमारी अवधारणा : स्थायी विकास की प्रचलित परिभाषा (ब्रुडलेंड कमीशन 1987) विकास और आवश्यकता के अर्थ को परिभाषित नहीं करती हैं। 'विकास' का हमारा अर्थ क्या है–एक ऐश्वर्यपूर्ण पश्चिमी जीवन शैली या संतुष्टिपूर्ण प्रसन्न जीवनयापन? तथा 'आवश्यकता' का क्या अर्थ है? एक सोता हुआ व्यक्ति 100 वॉट की सप्लाई से आराम से रह सकता है जबकि औसत अमरीकी व्यक्ति 10,000 वॉट का उपभोग करता है जबकि स्विस इनिशिएटिव इसके लिए 2000 वॉट प्रस्तावित करता है। क्या उचित है? इस तरह के प्रश्न स्वीकार्य रूप से उलझे हुए हैं, किंतु उनका उत्तर नहीं देने का अर्थ जबड़ों के भीतर जितना भी आ जाए चाहे वह उपयोगी न भी हो, समाहित कर लेने जैसा है। निश्चित रूप से समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, मनोवैज्ञानिक और अन्य लोग संयुक्त प्रयास से एक विवेकपूर्ण उपाय दे सकते हैं।

2. जनसंख्या : 2050 में 9–10 बिलियन लोगों का होना केवल अनुमान मानकर इसे व्यर्थ नहीं बतला सकते हैं यह होना निश्चित है किंतु जनसंख्या भाग्य नहीं हो सकती। यह सामाजिक मान्यता, अर्थशास्त्र अभिभावकों की सुरक्षा से निर्मित जनसंख्या होगी तथा जिसके लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी और जिसके लिए समाज वैज्ञानिक हस्तक्षेप जरूरी होगा।

3. वैश्विक सहयोग : हमारी राष्ट्र आधारित राज्य व्यवस्था जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना करने में अपर्याप्त सिद्ध हुई है। हमें बड़े वैश्विक संस्थानों की आवश्यकता है। यह समय है कि हमें गंभीरतापूर्वक निवेश करना होगा तथा समाजशास्त्रियों जो कि संस्थागत निर्माण की जानकारी रखते हैं कि बौद्धिक सम्पदा का उपयोग करना होगा।

मानवीय विकास के रूपान्तरण में समाजशास्त्र व समाज विज्ञान की क्षमता वास्तव में अपार है किन्तु जब तक कि हम इस क्षमता को वास्तविक क्रिया में नहीं बदलते इसका कोई लाभ नहीं है। बेहतर होगा कि हम इसकी शुरूआत कर देते। विज्ञान ने दिखला दिया है कि अगर हम अनियंत्रित विकास से इस दशक में अलग नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी। भविष्य में आने वाली पीढ़िया हमारे बारे में क्या सोचेंगी?

हम दो वर्ष पहले हुई बैठक पर वापिस लौटें, उसमें किसी भी प्रकार की असहमति नहीं हुई। हम सभी इस आशा पर एकमत थे कि अलग प्रकार के विकास की जरूरत है – जो कि समानतापूर्ण हो तथा अपने ग्रह की सीमाओं के अन्तर्गत हो। ■

[1] Global Footprint Network: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/

[2] Inter-Academy Panel, *Statement on Population and Consumption*: http://www.interacademies.net/10878/19191.aspx

[3] The World Bank, *Turn Down the Heat*: http://climatechange.worldbank.org/sites/default/files/Turn_Down_the_heat_Why_a_4_degree_centrigrade_warmer_world_must_be_avoided.pdf

[4] Griggs D. *et al.*, "Policy: Sustainable development goals for people and planet", *Nature* 495, pp. 305-307, 21 March 2013: http://www.nature.com/nature/journal/v495/n7441/full/495305a.html

>जलवायु परिवर्तन
बाजार पर निर्भर हमारा भाग्य

हर्बर्ट डोसैना, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले, यू.एस.ए.

संयुक्त राष्ट्र वार्ताक्रम के 20 से अधिक सालों बाद भी जहां ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं विश्व के नेतागण चार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने के विनाशकारी परिणामों से बचाने के लिए ज्यादातर बाजार पर निर्भर हैं। लेकिन सरकारों का गठबंधन और सामाजिक आंदोलनों की लड़ाई मुखर हो चुकी है। वारसॉ में 11–22 नवंबर 2013 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से हर्बर्ट डोसैना की रिपोर्ट।

यूएन की जलवायु परिवर्तन कान्फ्रेंस पर पौलैण्ड में वारसॉ की सड़कों पर सामाजिक आन्दोलनों का अभियान।

संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की पूर्व संध्या पर लगातार दूसरे साल फिलिपींस में सुपर टाइफून ने दस्तक दी। वारसॉ में मौजूद और घर लौट चुके प्रतिनिधियों के समक्ष इस घटना ने इस बात की तस्दीक की है कि जलवायु परिवर्तन न सिर्फ हो रहा है, बल्कि इसमें जिन देशों की सबसे कम भूमिका रही है, वे भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

इतना ही नहीं, 'हैइयन के अलावा अन्य चरम मौसमी घटनाओं ने लोगों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मजबूर किया है और कई ने आवाज वारसॉ में भी बुलंद की थी कि संयुक्त राष्ट्र की बातचीत बुरी तरह बेनतीजा रही, जैसा कि एक प्रतिनिधि ने इस बात की ओर इशारा भी किया। इसकी बजाय यह बातचीत किसी बदलाव का वाहक बनने के, एक खतरनाक रास्ते पर बढ़ रही है। पूर्व की बजाय, इस बार कम विभाजित नजरिये के साथ विकसित देशों की सरकारों का झुकाव इस समस्या के समाधान के लिए बाजार की ओर देखा गया। लेकिन वैश्विक आंदोलना ने सरकारों को असहज स्थिति में ला दिया है और विभिन्न लक्ष्यों के साथ चलाये जा रहे सामाजिक आंदोलनों ने वापसी करते हुए इसे एक अलग दिशा दे दी है।

>जिम्मेदारी का सवाल

वारसॉ सम्मेलन कई बैठकों की एक अद्यतन कड़ी है, जब सन् 1972 में वैश्विक पारिस्थितिक संकट पर बात करने के लिए विश्व की सरकारें स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक साथ इकट्ठा

>>

जलवायु परिवर्तन के वार्ताकारों के मध्य अंतिम समझौते पर एक ''अनौपचारिक जमघट''।

हुई थीं। सन् 1992 में वैश्विक सरकारों ने ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा स्थिर करने और जलवायु प्रणाली के बिगड़ने से मानव पर इससे होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

ऐसे स्पष्ट कार्य हालांकि भयभीत करने वाले ही साबित हुए हैं, फिर भी क्योंकि इनमें कम से कम हमारे जनजीवन के अंदर एक किस्म के अंतर्संबंधी रूपांतरण, जैसे बिजली के बल्ब को बदलने से लेकर राष्ट्रीय ऊर्जा के आधारभूत ढांचे को बदलने की जरूरत पड़ती है, कुछ का जोर देकर कहना है कि इसमें कुल मिलाकर पूंजी को स्थापित करने की जरूरत होती है और सकल बदलावों की तरह इन रूपांतरणों से किसी को परेशानी, तो किसी को लाभ ही होता है।

इसके बावजूद एक मूलभूत एकमत जरूर बना हुआ है कि इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ना है। सन् 1992 के सम्मेलन के तहत विकसित देश अनुगृहीत स्थिति में हैं कि उन्होंने ग्रीनहाउस गैसों के निस्तारण को कम करने में 'अपने कदम पहले बढ़ाये।' लेकिन चूंकि उनका यह प्रयास काफी नहीं है, इसलिए विकासशील देशों पर भी ऐसा करने के लिए जोर डाला जाता रहा और ऐसा करने के लिए उन्हें विकसित देशों से ही संसाधन और तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि वे ज्यादा संवेदनशील होने के बावजूद उनके पास जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कम संसाधन हैं, उन्हें मदद चाहिए, ताकि वे इसके दुष्प्रभावों का सामना कर सकें।

यह एक कठिन स्थिति है, क्योंकि आधारभूत एकमतता के बीच असमान पक्षों के बीच वितरण, खर्च और लाभ को लेकर कई गहरे अंतर्विरोध मौजूद हैं। इसके अलावा लोगों के कार्यों का अर्थ और एक–दूसरे के बीच संबंध से लेकर लोगों के प्रकार और दूसरों से किस तरह के व्यवहार की अपेक्षाएं हैं, इन पर अंतर्विरोध बरकरार हैं।

एक ऐसी समस्या, जिसके वे कारण नहीं हैं और न ही उन्हें कोई लाभ मिला है, इसके बावजूद समस्या के समाधान के बोझ से ग्रस्त विकासशील देशों का इस बात पर जोर है कि धनी देश नैतिक रूप से उन्हें जो करना चाहिए, उसके लिए बाध्य हैं, क्योंकि वे वायुमंडल में ज्यादा गैस उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से जिम्मेदार हैं और ऐसा करके वे लगातार समृद्ध भी होते गये हैं। विकासशील देशों को भी मजबूर करना चाहिए और कुछ प्रतिबंध भी लगाने चाहिए, उन्हें न सिर्फ पारितोष देना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छे कामों के लिए सहभागी भी बनाना चाहिए।

लगभग सभी विकसित देशों के वार्ताकारों, जिनका मैंने साक्षात्कार लिया, उन्होंने गुस्से में इसे खारिज किया, यह कहकर कि ऐसे कामों के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता ही नहीं। अगर वे इससे अधिक कुछ करते भी हैं, तो इसलिए कि उनका नेतृत्व सक्षम है, वे चैरिटी करना चाहते हैं, इसके लिए नहीं कि वे दोषी हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं, जिन्हें दंड दिया जाये, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है।

> विकास का सवाल

इस सबमें बड़ी उलझन यह है कि ये संघर्ष नैतिक स्थितियों और पदानुक्रमों पर हावी होते जा रहे हैं और संघर्ष इस बात को लेकर है कि अस्तित्व कैसे बचायें और विकास को कैसे पुनर्जीवित

>>

करें या फिर यह दीर्घ आर्थिक गिरावटों के संदर्भ में शुरूआत करने का एक लक्ष्य हो सकता है।

पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और सुधारवादी पर्यावरण आंदोलनों के उल्लेखनीय उभार, जिन्होंने सन् 1970 के दौरान हुई समस्याओं के लिए पूंजीवाद को जिम्मेदार ठहराया था, उस पर गौर करते हुए ओईसीडी देशों के अधिकारी और विशेषज्ञों, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, पर्यावरण समूहों और निगमों ने दीर्घावधि विकास की अवधारणा को आगे किया और इसका समर्थन किया, जिससे वैश्विक पारिस्थितिक संकट का समाधान निकल सके, जो सभी को एकजुट होने में रूकावट न बने। और वास्तव में यह निरंतर विकास में अपना योगदान दे सकता है।

यह मुद्दा अकसर कई सरकारों की परियोजनाओं, बहुपक्षीय संगठनों और नागरिक समाज समूहों के लिए एक सर्वसुलभ तर्क का रहा है। आवश्यकता तो इस बात की है कि सभी एक साथ कहें, 'वैश्विक पर्यावरण प्रबंधन' हो और प्रकृति के दोहन कैसे हो, इस पर नियमन तय किया जाये। लेकिन इसकी आवश्यकताओं पर ही वे संघर्ष करते रहे हैं।

एक ध्रुव पर, अमेरिका अधिक नव–उदारवादी नियमनों में महारत दिखाता रहता है, उसका मानना है, उच्च अंतराष्ट्रीय प्राधिकार नहीं, बाजार को हमारी प्रकृति के दोहन के नियमन तय करने देना चाहिए। देशों को कहा जाना चाहिए कि वे स्वैच्छिक रूप से अपने उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को तय करें, कम करने का कोई मानक तय न हो। ऊंचे मुनाफे के वादे को पूंजीवादियों से जोड़ कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कचरे से हरित ऊर्जा की ओर जायें या फिर विश्व में स्वच्छ तकनीकी परियोजनाओं में निवेश करें।

दूसरे ध्रुव पर यूरोपीय संघ है, जो ज्यादा सामाजिक–लोकतांत्रिक नियमनों की तरफ झुकाव रखता है। उसका मानना है कि इस प्रक्रिया में भागीदार देश उत्सर्जन कम करने के प्रयासों में ज्यादा सीधे और सक्रिय भूमिका में आयें, स्वच्छ तकनीक की तरफ पूंजी के प्रवाह को निर्देशित करें।

पूंजीपतियों के बीच मुख्य विवाद, उनके जिनका भविष्य फॉसिल ईंधन यानी भूरा पूंजीवाद और उनके जिनका हरित पूंजीवाद से जुड़ा है, के बीच है, मतलब जो नवीनीकरण योग्य ऊर्जा, कार्बन का व्यापार और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न लाभकारी अवसरों से जुड़े हैं। इनमें पहले वाले पूंजीपतियों को अमेरिकी प्रयासों में ज्यादा सहूलियत दिखती है, जबकि बाद वाले यूरोपियन यूनियन के पीछे हैं। जो दोनों ही पूंजी व्यवस्था में निवेशक हैं, उन्हें दोनों में ही अनुकूलताएं दिखती हैं।

विकासशील देशों का धड़ा, जिनमें लगभग 130 देश शामिल हैं, हमेशा से ही भिन्न मतों के रहे हैं, लेकिन साधारणतः वे पुनर्वितरण के न्याय और समाधान के केंद्र में अपने को साधे रखते हैं, क्योंकि उनके देशों में राज्य द्वारा लागू अधिकांश दंडात्मक नियमन (जैसे लेवी और फाइन) जारी हैं और वे अपने अधीन बाजारों से वैश्विक समाज की ओर ज्यादा तत्परता से उन्मुख हैं। लेकिन बड़े लक्ष्यों को लेकर हमेशा से आंतरिक मतभेद रहे हैं। कई उत्तर के अधिकारी और बौद्धिकों द्वारा प्रतिपादित दीर्घावधि विकास के पक्षधर हैं, जबकि कई ने प्रकृति संरक्षण द्वारा दीर्घ पूंजी विकास को पुनर्परिभाषित करने का पक्ष लिया है।

> वादे जो पूरे नहीं हुए

वार्ता के शुरूआती वर्षों में अमेरिका द्वारा प्रस्तावित नव–उदारवादी रूकावटहीन वादारहित शैली को यूरोपियन यूनियन और विकासशील देशों, दोनों के ही द्वारा खारिज कर दिया गया। जो कुछ जारी रहा, वह यह था कि बाजार के साथ एक लक्ष्य या कैप एंड ट्रेन समझौता, जिसमें विकासशील देशों को सन् 1990 के उत्सर्जन से कम उत्सर्जन भत्ता दिया जायेगा और एक कार्बन बाजार स्थापित किया जायेगा, जहां वे अतिरिक्त भत्ते हासिल कर सकते थे।

सन् 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल में संहिताबद्ध यह व्यवस्था आरंभिक दौर में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की अगुवाई में विकासशील देशों के समूहों को स्वीकार्य थीं, क्योंकि इसने बाजार की यांत्रिकी को (जिसे नव उदारवादी पसंद करते थे) उत्सर्जन की सीमा (जिसे गैर नव–उदारवादी चाहते थे) से जोड़ दिया, लेकिन चूंकि इसमें उन सभी की निर्दोषिता के सामूहिक दावे मुखर थे, विकासशील देशों द्वारा समर्थित दंडात्मक नियमनों के विपरीत बाजार आधारित नियमन उन्हें दंड पाने वाले कानून तोड़कों की तरह विरूपित कतई नहीं करते थे।

हालांकि बड़े पैमाने पर बाजार की यांत्रिकी के विरोध और कम लक्ष्यों से असंतुष्ट विकासशील देशों ने हस्ताक्षर किये, क्योंकि कानूनबद्ध सीमाएं कम से कम तय की गयी थीं और उन्हें इससे छूट दी गयी थी। इसके साथ–साथ बाजार से उन्हें धन और तकनीक हासिल करने का भी वादा किया गया था। लेकिन यह अमेरिका में उनके लिए हद ही साबित हुआ जो सीमाओं से प्रभावित थे और विकासशील देशों को छूट दिये जाने से क्षुब्ध थे। यह छूट न सिर्फ अमेरिकी प्रतिस्पर्द्धा के लिए खतरे के रूप में देखी गयी, बल्कि यह उस अमेरिकी नैतिक दावे को भी झुठलाता था कि वह दूसरों से ज्यादा दोषी नहीं है और उसकी नैतिकता दूसरों से कम भी नहीं है। अमेरिका ने प्रोटोकॉल से किनारा कर लिया, जबकि लगभग सभी देश उसका पालन करते रहे। लगभग 10 वर्ष लागू रहने के बाद भी यह समझौता कम ही कुछ हासिल कर सका। कुछ पक्ष उत्सर्जन कम करने में सफल रहे, वह भी इसलिए क्योंकि मंदी के कारण विकास प्रभावित हो गया था या फिर वे विसंगतियों से ग्रस्त और खत्म होते जा रहे कार्बन बाजार से सस्ती प्रतिपूर्ति खरीदने में सफल रहे। कुल मिलाकर आज उत्सर्जन सन् 1990 में, जब वार्ता शुरू हुई, तब से 60–70 फीसदी ज्यादा है और काफी कम मात्रा में धन या तकनीक विकासशील देशों के हाथ लग पाये हैं।

जबकि पिछले कुछ सालों में वार्ता चलती रही है, वारसॉ में मौजूद काफी लोगों का सोच यह था कि इतिहास में दर्ज यह जबरदस्त टाईफून एक नयी दिशा में वार्ता को आगे बढ़ायेगा। फिलिपींस के प्रतिनिधि वार्ताकार ने घिघियाते हुए कहा, 'हम इस जलवायु पागलपन को रोक सकते हैं।' और सचमुच उद्घाटन सत्र में उसकी आंखों में आंसू थे।

> आपदा की ओर तेज गति

इससे इतर हुआ यह कि वार्ता उसी रास्ते पर आगे बढ़ी, जिसे पहले छोड़ दिया गया था और पूर्व से अलग जब अमेरिका की अगुवाई वाले समूह और यूरोपियन अपनी राह पकड़ रहे थे, इस बार वे एक राह पर दिखे। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के पीछे है या फिर वह किसी समझदारीपूर्ण वैकल्कि ध्रुव प्रदान करने में विफल रहा है, जैसा कि उसने 1990 में किया था।

कार्बन व्यापार का समर्थन करते वक्त सीमाओं को छोड़ कर ज्यादा विकसित देशों की सरकारें एक तरह से सीमा और व्यापार के समझौते से अलग जा रही हैं और वे सीमा–रहित सिर्फ व्यापार समझौते की राह पकड़ रही हैं। पहले से कम विभाजित ये सरकारें अधिक सीधे नियमनों से आगे जा रही हैं और जलवायु संकट का

>>

समाधान निकालने के लिए ज्यादा तौर पर बाजार पर निर्भर हो रही हैं।

वे बारंबार वार्ता के दौरान कहती रहीं कि उत्सर्जन कम करने के लिए सरकारें प्रकृति के लिए कीमत निर्धारित कर निजी क्षेत्रों को हरित ऊर्जा में निवेश के लिए उत्प्रेरित करें, जो राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्बन बाजारों के प्रसार और उनके बीच अंतर्संबंध स्थापित करके हो सकता है। वे उदार निवेश नीतियों और अनुदानों के माध्यम से एक सक्षम वातावरण निर्मित करें और इसके लिए सरकारों को उच्च से निम्न स्तर पर कार्यवाही करनी होगी।

वारसॉ में कनाडाई वार्ताकार ने जो काम सौंपा, वह यह था कि विश्व की सरकारें यह संदेश भेजें कि 'जलवायु परिवर्तन व्यापार के लिए मुफीद है और व्यापार के लोग जो दीर्घावधि विकास के तर्क का पालन करते हैं, ऐसे लोग हैं, जिन्हें पक्ष में रखना या खुश करना जरूरी है, यदि वे हमें जलवायु परिवर्तन के संकट से बचाते हैं, बजाय इसके कि उन्हें मजबूर किया जाये या दंडित किया जाये। अगर बाजार के माध्यम से शासन करना है, तो ऐसे लोगों के हाथ में धरती का भविष्य सौंप देना सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन यह और भी नव–उदारवादी समाधान के रूप में सामने आया और इससे विपक्ष उत्तेजित हो गया है। इसके बावजूद कि अंदर में कई दरारें दिख रही हैं और बाहर से दबाव बढ़ रहा है, ज्यादातर विकासशील देशों की सरकारें इस बात पर एकमत हैं कि बाजार नहीं, देश ही सीधे तौर पर यह सुनिश्चित करें कि उत्सर्जन व्यापक तरीके से कम किया जाये और संसाधन और तकनीक का आदान–प्रदान बढ़े।

इस समझौताहीन स्थिति का कुछ हिस्सा वेनेजुएला, बोलीविया, इक्वाडोर और इस संघ के अंदर के कुछ वाम झुकाव वाले देशों के बढ़ते प्रभाव में भी निहित है। अभी भी लगातार हाशिये पर रहे और चतुराईपूर्वक चुप रहने को मजबूर किये गये इन देशों के वार्ताकारों ने वैश्विक रूप से जुड़े कार्बन बाजार निर्मित करने के लिए विकसित देशों को एकजुट करने में सफल भूमिका निभायी है। ये देश गैर–बाजार यांत्रिकी विकसित करने या फिर उत्सर्जन रोकने के लिए सीमाहीन बाजार के हित में माहौल बनाने में अग्रगामी रहे हैं, जो शायद बाजार समाधानों के सबसे वृहत विकल्प के तौर पर वार्ता की मेज पर शामिल किया गया था। नागरिक समाज भी अब एक बिंदु पर जाता हुआ दिखायी देता है। लगभग 800 एनजीओ, ट्रेड यूनियन और सामाजिक आंदोलनों के प्रतिनिधि, मौलिकतावादी और मध्यमार्गियों ने वार्ता के तरीके के विरोध में बहिष्कार किया। इस सबसे धरती का भविष्य व्यापारिक हाथों में जाता दिखायी पड़ता है। लेकिन जब तक विकासशील देश और विश्व भर में फैले सामाजिक आंदोलन विकसित देशों की सरकारों पर अपना प्रभावी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय उन सभी लोगों पर प्रभावी रूप से जोर नहीं डालेगा, जो यह तय करते हैं कि क्या, कितना और किस स्त्रोत से ऊर्जा पैदा होगी (यहां तक कि विकासशील देशों में भी), विश्व वैश्विक तापमान में चार डिग्री बढ़ोतरी की राह पर है, एक ऐसे विश्व में जहां 'हैइयन' को भी तुलनात्मक रूप से नकार दिया जाता है। सुपर टाईफून की शक्ति से भी बड़ी शक्ति हमें चाहिए, जो हमें उस संभावित दुर्भाग्य की राह से दूर ले जाये। ■

>चीनी नगरीकरण में नाटक एवं तबाही

फीझाहू झाऊ, पिकिंग विश्वविद्यालय, चीन

एक किसान अपने खेत को सिंचित करते हुए जैसा कि उसका भविष्य चीन के नये शहरों की बहुमंजिला इमारतों के परे है।

प्राचीन समय से चेंगदू समभूमि घनी आबादी वाला कृषि क्षेत्र रहा है। 2007 में केन्द्रीय सरकार ने "शहरी एवं ग्रामीण विकास के समन्वयन हेतु पाइलट क्षेत्र" जिसका उद्देश्य नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य सम्बन्धों को बदलना था, के लिए चेंगदू शहर को चुना। चेंगदू के सुधारवादी उपायों का अन्य क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और 2009 से इनका अध्ययन किया गया, सीखा और अनुकरण किया गया। चेंगदू परियोजना का सर्वाधिक जरूरी हिस्सा किसानों को पारंपरिक परन्तु आम तौर पर छितराए ग्रामीण समुदायों से सरकारी कोष से निर्मित अपार्टमेण्ट इमारतों में स्थानांतरित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक अपार्टमेण्ट इमारत में 100 से 500 परिवार जो एक से तीन ग्रामीण समुदायों के आकार के बराबर है, निवास कर सकते हैं। ये आवासीय परियोजनाएं नल का पानी, बिजली, गैस, सड़क तक पहुंच, कूड़ा निपटान और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इन समुदायों में जीवन गुणवत्तता ग्रामीण कस्बों के औसत स्तर के बराबर है। पुनर्वास परियोजना को स्थानीय सरकारें 'नव देहात निर्माण' या "नगरीय और ग्रामीण विकास में संतुलन" के नाम से बुलाती है। यद्यपि कुछ समाचार मीडिया के लिए ये "लुप्त होते हुए गांव" के रूप में जानी जाती हैं।

इस बीच, कृषक कार्य भी संक्रमण में है। 1980 के दशक से गैर–सामूहिकीकरण सुधार में "परिवार को ठेके पर उत्पादन देना" (baochan daochu) को शामिल किया है और भूमि अधिकार, उपयोग और आय दोनों के रूप में, ग्रामीणों के समान रूप से पुनः वितरित किये गये। परिणामस्वरूप, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को खेत के कई टुकड़े मिलें परन्तु हमेशा एक टुकड़ा परिवार के आवास के पास अवश्य था। अपार्टमेण्ट इमारत में जाने से किसानों के रिहायशी स्थान और उनके खेतों के मध्य की दूरी बढ़ गई। कई किसानों को अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए दो घंटे और कभी–कभी इससे भी ज्यादा, पैदल चलना पड़ता था। इन परिस्थितियों के अंतर्गत स्थानीय सरकार ने उच्च योगित मूल्य की नकदी फसलों को उगाने हेतु बड़े खेतों को किराये पर दे कर नगरीय कार्पोरेशनों को देहात में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चेंगदू में भूमि को लीज देने की कीमत लगभग 800–1000 युआन प्रति क्यू है। यह कीमत मोटे तौर पर किसानों की खाद्य फसलों के वार्षिक उत्पादन के बराबर है। अतः जब किसान नई आवासीय परियोजना में चले गये उनकी खेती की जमीन नगरीय कार्पोरेशन द्वारा ले ली गई और पारंपरिक खेती कार्पोरेट खेती में बदल गई।

अपार्टमेण्ट में रिहायश ने किसानों की उत्पादक गतिविधियों और जीवन शैली को आश्चर्यजनक रूप से बदल दिया है। चूंकि किसानों के पास सब्जी और फल उगाने या सुअर और मुर्गियों जैसे पशुपालन हेतु कोई जगह नहीं है अतः एक तरफ तो उनके पास अपने जमीन का किराया ही उन्हें प्राप्त होता है। दूसरी तरफ किसानों को अब मूलभूत आजीविका–खाना, पानी, गैस इत्यादि के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। हमारे द्वारा चेंगदू में करवाये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, अर्पाटमेण्ट

>>

इमारतों में रहने के कारण किसानों की रहने की लागत में औसतन 30% की वृद्धि हुई है। रिहायशी पैटर्न में परिवर्तन और गांवों के विलयन के कारण न सिर्फ उत्पादन सम्बन्ध अपितु ग्रामीण सामाजिक सम्बन्ध और शासन व्यवस्था भी प्रमुख रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हैं। इन सुधारों के दूरगामी परिणाम अभी भी अस्पष्ट है परन्तु इन्हें चीन में अभी हो रहे तीव्र नगरीकरण के संदर्भ में ही समझा जा सकता है।

चीन की भूमि व्यवस्था में दो प्रकार के स्वामित्व एक साथ पाये जाते हैं : ग्रामीण जमीन का सामूहिक स्वामित्व और नगरीय भूमि का राज्य स्वामित्व। यदि शहरों को नगरीय विकास और निर्माण के लिए ग्रामीण भूमि की आवश्यकता है तो उन्हें पहले कानूनी तौर पर ग्रामीण भूमि के सामूहिक स्वामित्व को राज्य स्वामित्व में बदलना होगा। यह प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण कहलाती है। भूमि को अधिग्रहित कर बेचने का अधिकार सिर्फ स्थानीय सरकारों के पास है। स्थानीय सरकारें ग्रामीण भूमि का स्वत्वहरण कर और फिर शहरी विकासकों को बेच कर ''भूमि हस्तांतरण शुल्क'' से विशाल भू–राजस्व कमा सकती है। 2013 में देश भर में भूमि हस्तांतरण शुल्क की कुल राशि 4.12 ट्रिलियन RMB से अधिक थी। यह राशि स्थानीय सरकार के राजकोषीय राजस्व के 59% से अधिक थी। 1994 के कर–बंटवारा सुधार के पश्चात, चूंकि स्थानीय सरकारों को शहरी निर्माण से उत्पन्न अधिकांश कर राजस्व अपने पास रखने की अनुमति है, उनके पास शहरी निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा करने का भारी प्रलोभन भी है। कर राजस्व का यह हिस्सा, भूमि हस्तांतरण शुल्क के साथ, आज जो ''भूमि केन्द्रित स्थानीय राजकोषीय शासन'' (tudi caizheng) कहलाता है, का आधार भी है।

शहरी विकास और निर्माण के लिए गैर–सरकारी पूंजी के उपयोग के अलावा, स्थानीय सरकार को नगर निगम के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भी निवेश करना होता है, जो उसकी वित्तीय क्षमताओं के काफी परे है। कानून के अनुसार स्थानीय सरकारों द्वारा शहरी निर्माण के लिए ऋण लेना गैर कानूनी है। सरकारी एजेन्सियां न तो वित्तीय संस्थानों से प्रत्यक्ष रूप से ऋण ले सकती है और न ही वे ऋण के गारंटर के रूप में कार्य कर सकती हैं। यद्यपि व्यवहार में स्थानीय सरकारें सरकारी राजस्व कोष को राज्य स्वामित्व वाली कम्पनियों जैसे शहरी निवेश विकास कार्पोरेशन, शहरी पारगमन निगम, शहरी वाटर वर्क्स, भूमि आरक्षित केन्द्र इत्यादि को स्थापित करने के लिए पंजीकृत पूंजी के रूप में उपयोग करती हैं। आमतौर पर ये कम्पनियां राज्य संपत्ति की स्थानीय प्रशासन समिति जो स्थानीय शहर या काउण्टी सरकार का एक विभाग होती है, द्वारा प्रबंधित होती हैं। इन कम्पनियों का मुख्य कार्य सरकार द्वारा हस्तांतरित राज्य स्वामित्व वाली जमीन को बैंक के पास गिरवी रख कर शहरी निर्माण के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना होता है। चीन की लगभग सभी काऊण्टी एवं शहरों में अब इस प्रकार की कम्पनियां हैं। ये कम्पनियां ''स्थानीय वित्तपोषण मंच'' (difang vongzi pingtai) कहलाती हैं। ये वित्तीय मंच आमतौर पर गिरवी रखी गई भूमि के आकलित मूल्य के 70% के बराबर ऋण प्राप्त करती हैं, जिनका उपयोग शहरी बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार जून 2013 के अंत तक स्थानीय सरकारों पर 17.9 ट्रिलियन RMB का कुल कर्ज था। अधिकांश कर्ज वित्तपोषण मंचों के कारण था।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, चीन के शहरी विस्तार के पीछे एक शक्तिशाली भूमि, राजकोषीय और वित्तीय तंत्र है। प्रथम, स्थानीय सरकारें नगरीय विकास के लिए भूमि अधिग्रहण द्वारा राज्य–स्वामित्व भूमि और साथ ही भूमि विक्रय से राजस्व प्राप्त कर सकती हैं। द्वितीय, स्थानीय वित्तपोषण मंच की कार्यप्रणाली के अंतर्गत, स्थानीय सरकार शहरी निर्माण के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि को गिरवी रख सकती है। भूमि और वित्त के बीच इस तालमेल ने तेजी से बदलते, समृद्ध शहरों का निर्माण किया है जो उद्योग और जनसांख्यिकी ढ़ेर पर आधारित पारंपरिक नगरीकरण की प्रक्रिया से भिन्न है।

नगरीकरण के नयै पैटर्न की चाबी विकास और गिरवी रखने के लिए पर्याप्त राज्य स्वामित्व भूमि होना है। यद्यपि खेती योग्य भूमि के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार स्थानीय सरकारों द्वारा खेती योग्य भूमि के अधिग्रहण की मात्रा को सख्ती से नियंत्रित रखती है। चेंगदू सुधार विरोधाभासी शक्तियों से उपजा है : एक तरफ भूमि अधिग्रहण पर कठोर नियंत्रण और दूसरी तरफ शहरीकरण को बढ़ावा देने हेतु भूमि की शक्तिशाली मांग।

ग्रामीण चीन में, वासभूमि (zhaijidi), यानि कि वह भूमि जिस पर घरों का निर्माण होता है कृषि योग्य नहीं होती है। पारंपरिक चौक निवास पद्धति के कारण, किसानों के पास आम तौर पर विशाल घर होते हैं। चेंगदू में किसानों को अपार्टमेण्ट इमारतों में स्थानांतरित करने के पीछे मुख्य मंशा नगरीकरण के लिए भूमि का 'उत्पादन' करने की है। किसानों के एक बार अपार्टमेण्ट में प्रवेश करने के बाद उनके खाली किये घर अधिग्रहण के पश्चात कृषि योग्य बन सकते हैं। इस तरह स्थानीय सरकार कृषि योग्य भूमि में वृद्धि का शहर के विस्तार के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त करने के लिए उपयोग में ले सकती है। उदाहरणार्थ, ग्रामवासियों के अपार्टमेण्ट में जाने के पश्चात, एक गांव ने 100 म्यू रिहायशी भूमि को पुनः प्राप्त किया और उसे कृषि योग्य भूमि के परिवर्तित किया। अब जब भी शहरों को शहरी विकास की आवश्यकता हो वे 100 म्यू कृषि योग्य जमीन को अधिग्रहित कर सकते हैं। उसी समय कृषि योग्य भूमि की कुल मात्रा भी नहीं बदलती है।

अतः, सामान्य तौर पर, किसानों के छितराये निवासों से गहन अपार्टमेण्ट ब्लॉक्स में निवास के बदलते पैटर्न, चीन के ग्रामीण नगरीकरण के लिए भूमि और पूंजी का परम स्त्रोत है। यदि किसान अपने घरों को नहीं छोड़ें तो स्थानीय सरकार द्वारा अधिग्रहित करने हेतु कृषि योग्य जमीन और बैंक ऋण के लिए गिरवी रखने के लिए जमीन ही नहीं होगी। नगरीकरण की दर अब से बहुत धीमी होगी। वर्तमान में चेंगदू प्रयोग का चीन के कई हिस्सों में अनुकरण किया जा रहा है, जिसका परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र नगरीय विस्तार है। ■

>भूमि हथियाना और भ्रष्टाचार

योंगहोंग झांग, सन यात–सेन विश्वविद्यालय, गुआंगडोंग, चीन

शेनझेन में ग्रामीण स्थानीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध नारे लटकाते हुए।

चीन में शहरीकरण की अभूतपूर्व प्रक्रिया के दौरान शहरी निर्माण के लिए सामूहिक भूमि का अधिग्रहण हुआ जिसमें ग्रामीण सामूहिक संपत्ति का प्रबंधन और वितरण सामाजिक विरोधाभासों और संघर्षों का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। 1990 के शुरूआत में दक्षिणी–पूर्वी तटीय इलाकों में शहरीकरण चीन के अन्य भागों की तुलना में अधिक तीव्र था। स्थानीय सरकार के दिशा–निर्देशों के तहत शहरों के आस–पास के गावों ने धीरे–धीरे ग्रामीणों की सामूहिक भूसंपत्ति को शेयरों में परिवर्तित कर दिया और उनको ग्रामीण व्यक्तियों में बांट दिया। ग्रामीण भूमि के सामूहिक स्वामित्व की संपूर्ण व्यवस्था को बदले बिना इन गांवों ने 'सामूहिक हिस्सेदारी निकाय' स्थापित कर दिये और ग्रामीण व्यक्ति सामूहिक भूसंपत्ति के हिस्सेदार बन गये तथा इससे मिलने वाले लाभांश प्राप्त करने लगे।

'सामूहिक हिस्सेदारी निकाय' स्थानीय सरकार का एक प्रयास था जिससे ग्रामीण समाज को उनके लोगों की साम्यवाद के काल से चली आने वाली पूर्व शक्ति संरचना में बिना आमूलचूल परिवर्तन के शहरीकरण के लिए तैयार किया जा सके। समिति के सदस्य ग्रामीण हिस्सेदारों द्वारा चुने जाते थे परंतु परिणाम स्थानीय सरकार और ग्रामीण दलों द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होते थे। अधिकतर, ग्राम दल–शाखा सचिव राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक शक्ति पर एकाधिकार रखते हुये 'स्वाभाविक रूप से' समिति का अध्यक्ष बन जाता था। ये सामुदायिक निकाय स्थानीय सरकार और आस–पास के गावों के बीच संपर्क बनाए

>>

रखते थे और फलस्वरूप सरकार के लिए शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने का साधन बन गए। उदाहरण के लिए, सामुदायिक निकाय ना केवल सामूहिक संपत्ति का प्रबंधन करते थे बल्कि ग्राम–विकास, जनसुरक्षा, सामुदायिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य भी देखने लगे जो कि स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी थे।

यद्यपि ग्राम समिति और सामुदायिक निकाय मूल रूप से जनसाधारण के स्वायत्त संगठन थे फिर भी स्थानीय सरकार और ग्रामीण दलों का प्रभाव प्रायः ग्रामीणों के स्वतंत्र प्रजातांत्रिक अधिकारों पर सवार हो जाता था। परिणाम यह हुआ कि समिति का अध्यक्ष (ग्राम दल–शाखा सचिव भी) और स्थानीय सरकार षडयंत्र करके सामूहिक भूमि मुआवजों में हेराफेरी और सामूहिक संपत्ति को नियंत्रित करने लगे।

हाल ही के कुछ वर्षों में भूमि की कीमतों के लगातार बढ़ने के कारण समिति के अध्यक्ष या ग्राम दल–शाखा सचिव ने हथियाई गई भूमि को बेच कर या किराये पर देकर स्वयं को संपन्न कर लिया है। इससे गांव में विरोध बढ़े हैं। 2012 के बसंत से लेकर, वुकान की नाटकीय घटना से प्रेरित हो कर, गुआंगजो के न्यायाधिकार और शेंजेन नगरपालिका सरकारों (गुआंगडोंग प्रांत) – मेरी शोध संस्था द्वारा अध्ययन किये गये – के लगभग सभी गांवों में भूमि को लेकर संघर्षों से उत्पन्न सामूहिक हिंसा देखी जा चुकी है। गुआंगजो नगरपालिका के संदर्भ में, उदाहरण के लिए, विरोध के कई वर्षों बाद 2013 में, ग्रामीण 'मूल हिस्सेदारी निकाय' के नेताओं के खिलाफ याचिका जीत गए और नई निर्वाचित समिति ने एक नई लीज पर हस्ताक्षर किये जिससे उन्हें 100 मिलियन RMB (16 मिलियन डॉलर) अधिक मिले।

मजदूर संघर्षों से भिन्न, भूमि हथियाने और भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्षों ने ग्रामीणों के व्यक्तिगत–आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा को आवश्यक बना दिया और स्थानीय सरकारों की वैद्यता को गंभीर चुनौती दी। उनके परिवार और समुदाय के संबंधों के जटिल पंरपरागत ढांचे और उनके बहुपीढ़ीय निवास को धन्यवाद, जिसके कारण भूमि संघर्ष दीर्घकाल तक चले और शासन की सामाजिक स्थिरता को गंभीर चुनौती दी। इसके अलावा, गांवों में विरोधों को निपटाये बिना, भविष्य में भूमि पुनर्वितरण और शहरी विकास स्थायी रूप से रूक जाता। इसलिये, स्थानीय सरकारों ने भ्रष्टाचार की जांच और सजा के लिए सख्त कदम उठाने शुरू किये। इस प्रकार गुआंगजो नगरपालिका में लगभग एक चौथाई ग्राम–दल संवर्ग को गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा दी गई।

चीन की सत्तावादी व्यवस्था के अंतर्गत, कार्यविधिक खेल (उदाहरण के लिए, ग्राम चुनाव और मुकदमे) विरोध समाप्त करने के प्रभावी माध्यम है। आपको पता है कैसे प्रांतीय सरकार ने वुकान विरोध को संभाला था, जहां ग्राम विरोध अधिक था और भ्रष्टाचार के पर्याप्त प्रमाण थे, स्थानीय सरकारों ने संदिग्ध ग्राम नेता की खोजबीन करके और नए चुनाव करवा कर भूमि हथियाने के खिलाफ हो रहे संघर्षों को निपटाया। उसी समय, अधिकतर गांवों में चुनाव ग्रामीणों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा अभी तक नहीं कर सके थे, बल्कि ये सामूहिक निकायों के नेताओं के लिए व्यक्तिगत लाभ खोजने और सत्ता के दुरूपयोग के माध्यम बन गये। इसलिये ग्रामीणों ने चुनावों के प्रति एक निराशाजनक रूख अपना लिया। वे चुनावों को नागरिकों का अविच्छेद्य अधिकार नहीं समझते है, बल्कि अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का सिर्फ एक उपकरण मानते हैं। जैसा कि उन्होंने हमें क्षेत्र में अध्ययन के दौरान कहा कि जो भी चुनाव जीत जाएगा, वह इसे स्वयं के शक्तिवर्धन और विकास का साधन बना लेगा।

ग्राम शासन की वर्तमान व्यवस्था, जो कि सामूहिक भूमि स्वामित्व पर आधारित है, ने ग्राम स्वायतत्ता को गंभीर रूप से हानि पहुंचाई है। जब शहरीकरण बढ़ता है, सरकार से लोगों की जरूरतों के प्रति जिम्मेदार और ग्रामीणों को शहरी लोगों के समान नागरिक अधिकार देने की अपेक्षा की जाती है। आज, राज्य और ग्रामीणों के बीच संबंध निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, क्योंकि दोनों ही स्थानीय शासन के नए तरीके खोज रहे हैं। फिर भी, सभी प्रयोगों के बावजूद, वर्तमान भूसंपत्ति स्वामित्व व्यवस्था को बिना बदले, शहरीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण निस्संदेह नुकसान में ही रहेंगें। ■

>जलमार्ग विरोध तीन घाटी बांध का मामला

यिंग जिंग, राजनीति विज्ञान एवं विधि का चीनी विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीन

युनयांग काउन्टी का एक प्रदर्शनकारी हे केचांग के नेतृत्व में होने वाले विरोध की कहानी बतलाते हुए। चित्र यिंग जिंग द्वारा।

समकालीन चीनी समाज में, जब अधिकारियों एवं आमजन के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, लोग उससे राहत पाने के लिए चार प्रमुख तरीके अपनाते हैं—वर्ग कार्यवाही, समूह याचिका, मौके पर ही प्रतिरोध करना (या तत्काल विरोध) और सामूहिक दंगा। समूह याचिका और तत्काल विरोध दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग करना इनमें सबसे आम है। मैं प्रथम वर्ग—कार्यवाही मुकदमा, जिसे 'हे केचांग मुकदमा' नाम से जानते हैं, में चीन के तीन घाटी बांध से विस्थापित लोगों द्वारा अपनाये गये कानूनी उपायों का विश्लेषण करूंगा।

846,200 लोगों को तीन घाटी जलाशय क्षेत्र में बसाया गया जिनमें से 361,500 लोग ग्रामीण क्षेत्र से थे। 1997 के बाद से युनयांग काउंटी, चोंगक्वींग नगर पालिका से खेतिहर किसानों ने एक समूह याचिका

>>

दायर की। श्री हे केचांग, प्रतिनिधि दावेदार, की याचिका चार चरणों में प्रस्तुत हुयी।

10,000 लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को चोंगक्वींग व केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों के एक संयुक्त कार्य दल द्वारा युनयांग काउंटी भेजा गया। हालांकि उन्होंने इस बात को नकारते हुए कि 'विस्थापितों के लिए मुआवजा अपर्याप्त था', अपनी जॉच का निष्कर्ष निकाला, कि यह विस्थापित जनसंख्या के प्रतिनिधियों की केवल एक गलतफहमी थी जोकि स्थानीय नेतृत्व के अध्यक्ष को दरकिनार करने की गलती कर रहे थे। हे केचांग और अन्य प्रतिनिधि इस परिणाम से काफी असंतुष्ट थे कि 1998 से 2000 तक उन्होंने बीजिंग कई पत्र भेजे, दो याचिकाओं का भुगतान करने के लिए बीजिंग का दौरा किया और चोंगक्वींग के अनेक दौरे किए परंतु उनमें से किसी का भी जवाब नहीं आया।

समूह याचिका और स्थानीय लामबंदी में वृद्धि मार्च 2000 से मार्च 2001। मई 1999 में, राज्य परिषद ने तीन घाटी पुनर्वास नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया जिसमें खेतिहर किसानों को स्थानीय क्षेत्र से हटाकर दूर जगहों पर बसाया जायेगा, जिसके कारण युनयांग की विस्थापित जनसंख्या में विरोध की एक अन्य लहर उत्पन्न हो गई। हे केचांग के नेतृत्व में विस्थापित जनसंख्या ने अनेक रणनीतियों को संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया। जैसे–आमने–सामने विरोध की नीति और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ टकराव, संगठन में सुधार, स्वयं को नीतियों से परिचित करवाना और पुनर्वास के बारे में सूचनाओं का प्रसार करना, पत्रों के माध्यम से और बीजिंग का दौरा करके याचिकाओं की तीव्रता में वृद्धि करके और विदेशी मीडिया के साथ संचार करके इत्यादि।

कारावास की विपरीत परिस्थितियां : मार्च 2001 से मार्च 2004। मार्च 2001 में, हे केचांग और दो अन्य प्रतिनिधियों ने याचिका के लिए बीजिंग का दौरा किया। चोंगक्वींग की स्थानीय सरकार ने बीजिंग में तीनों प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में युनयांग काउंटी की जन अदालत ने पुनर्वास जांच संगठन की घोषणा की जो सरकारी पुनर्वास योजना को चुनौती दे रहा था और हे केचांग को तीन साल के लिए कारावास में डाल दिया तथा अन्य दो प्रतिनिधियों को शांति भंग करने के लिए एकत्र होने के लिए दो साल की सजा सुनाई। यह पहली बार था कि तीन घाटी के याचिकाकर्त्ताओं को कारावास की सजा सुनायी थी और युनयांग खेतिहर किसानों का भविष्य/भाग्य एक अंतराष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया था।

एक अंतहीन लड़ाई : मार्च 2014 से अब तक। 11 मार्च 2004 को हे केचांग को उनकी सजा पूरा होने के बाद छोड़ दिया गया। यद्यपि उसे कारावास में अत्यधिक यातनाओं का सामना करना पड़ा–उसके पैर तोड़ दिए गए और उसके हाथों को विकृत कर दिया गया तथा अगस्त, 2002 में उसकी सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया, परंतु फिर भी उसमें संघर्ष करने की प्रवृत्ति जिंदा है। अपनी रिहाई के बाद उन्होंने स्थानीय सरकार के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और विस्थापित जनसंख्या के विषय में सूचना एकत्र करने में निरन्तर व्यस्त रहे। वे एक अंतहीन लड़ाई–संघर्ष में प्रवेश कर चुके थे।

हे केचांग के मामले में हम देखते हैं कि विरोध नीति का चुनाव करते समय वह कुछ व्यावहारिकता बरतते थे, न्यायिक उपायों से गैर–न्यायिक उपायों और कई बार उन्हें संयुक्त रूप से भी प्रयुक्त करते थे। विस्थापित जनसंख्या के दृष्टिकोणों से 'विधि के शासन' तथा 'मानव के शासन' के बीच अन्तर का महत्व कम था। एक विशिष्ट विवाद के समाधान को प्राप्त करने में राजनीति की व्यावहारिकता ज्यादा महत्व पूर्ण है। वे न्यायालय में इसलिए अपील नहीं करते, क्योंकि वे वैधानिक न्याय में विश्वास करते हैं और वे इसलिए याचिका दायर नहीं करते क्योंकि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों की ईमानदारी पर विश्वास है। वे आवश्यक उपागमों के रूप में मुकदमा और याचिका दोनों को अपनाते हैं ठीक उसी तरह से जैसे सत्ता में बैठे लोग शासन करने हेतु आवश्यक/समयोचित रणनीति अपनाते हैं। ■

> यान जेपांस्की
एक अनिश्चित पुल का निर्माण

एडम मुलर, कामिल लिपंस्की, मिकोलाज मिरजेवस्की, क्रिस्टोफ गुबान्स्की, कैरोलिना मिकोलायेवस्का,
सार्वजनिक समाजशास्त्र प्रयोगशाला, वारसॉ विश्वविद्यालय, पोलैण्ड

यान जेपांस्की (1913–2004) एक पोलिश समाजशास्त्री थे, जो कि 1966 से 1970 तक इंटरनेशनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन (आई एस ए) के अध्यक्ष रहे। पूर्वी ब्लॉक से इस पद पर आने वाले वह पहले व्यक्ति थे। पोलैण्ड में उनके संस्करणों में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। समाचारपत्रों में भी उनके कॉलम (स्तम्भ) प्रशंसा व चर्चा का विषय रहते थे। वह जन मुद्दों के प्रति उदासीन नहीं थे और उन्होंने पोलैंड के जनवादी गणतंत्रीय संसद का एक सदस्य (1957–61, 1972–85) तथा राज्य परिषद का एक सदस्य (1977–82) होने के नाते राजनीतिक जीवन में सक्रिय सहभागिता की। 1960 के अंत में आई एस ए के अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्हें दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम, पूर्व और पश्चिम के बीच वार्त के साथ–साथ ग्लोबल दक्षिण के साथ वार्ता पूर्वी यूरोप (वर्ना, बुल्गारिया) में आईएसए की कांग्रेस के आयोजन का परिणाम था। दूसरी, उनकी डायरी के अनुसार, एक अध्यक्ष के रूप में जब वह संगठन के सरलतम मामलों को निपटाने की कोशिश करते थे तो उन्हें अनेक बोझिल कागजी कार्यवाही से गुजरना पड़ता था।

यान जेपांस्की मौज मस्ती के मूड में।

साम्यवादी युग में पोलिश राजनीतिक स्थिति की विशिष्टता, जिसकी चर्चा प्रसिद्ध समाजशास्त्री विनिसियस नेरोजेक ने की, को राज्य की सीमित वैधता प्राप्त थी। एक ओर साम्यवादी शासन को अधिकांश जनसंख्या का समर्थन प्राप्त था, विशेष रूप से प्रारम्भिक दौर में, जिसे एक बाहरी शक्ति के रूप में सोवियत संघ द्वारा ऊपर से थोपा गया था, इस प्रकार, यह परम्परागत राष्ट्रीय मूल्यों के विपरीत था। दूसरी तरफ, सत्ता के प्रतिनिधियों को अक्सर आवश्यक बुराई के रूप में देखा जाता था। ऐसा माना जाता है कि वे अपने पूर्वी रक्षकों से स्वयं को पृथक रखने में सक्षम थे। वैधता के अनेक स्तम्भों में से एक सत्ता में स्थित लोगों की

>>

योग्यता व इच्छा शक्ति रूढ़िवादी सोवियत सिद्धांत के क्रियान्वयन में बाधा पहुंचा रही थी। 'जन लोकतंत्र', विशेषतः संकटों के समय में (1956, 1970, 1980) लोगों को नियंत्रित करने व आकर्षित करने में मजबूत भी था और कमजोर भी।

पोलिश बुद्धिजीवियों ने इस स्थिति के प्रति व्यापक रूप से भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों को अपनायाः पूर्णतः विरोध से लेकर व्यवस्था के प्रति समर्पित और उत्साही योगदान तक। अनेक लोगों ने कठिन और नैतिक रूप से असहज मध्य मार्गीय स्थिति को चुना। 1956 के बाद यहां हम यान जेपांस्की की उपस्थिति को देखते हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर एक नई राजनीतिक रेखा को तैयार करने में सहभागिता की जबकि, उसी समय, कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पार्टी द्वारा की गई अनेक गलतियों व विकृतियों को उत्पन्न करने के कारण वह उसके आलोचक भी रहे। ऐसे लोगों के प्रयास धन्य हैं जिन्होंने निरपेक्ष सत्ता और बौद्धिक अभिजनों के बीच एक अस्थायी पुल का निर्माण किया, जिसके माध्यम से ही पोलिश बुद्धिजीवियों के लिए, कुछ हद तक, सापेक्ष स्वायत्तता स्थापित करना संभव हो पाया। 'एकता' आंदोलन के बाद बुद्धिजीवियों ने कार्यवाही करने की एक निश्चित स्वतंत्रता प्राप्त करके विपक्षी संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। सोवियत गुट (ब्लॉक) के अनेक देशों के विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग नहीं था क्योंकि सामाजिक जीवन की व्याख्या करने का एकाधिकार मार्क्सवादी–लेनिनवादी संस्थाओं को प्राप्त था। ऐसे में, स्टालिन की मृत्यु के बाद पोलैंड में समाज विज्ञानों का पुनरूद्धार सोवियत गुट में होना असामान्य था, जिसने ऐसे पोलिश समाजशास्त्रियों को उत्पन्न किया, जो महान सार्वजनिक बुद्धि जीवी के रूप में उभरे जैसे–यान जेपांस्की, मारिया ओसोवस्का, स्टेनिस्लॉ ओसोवस्की, जिग्मंड बाउमन, मारिया हिर्शजोविक एवं स्टेफन नोवाक इत्यादि प्रसिद्ध और परिचित व्यक्तित्व हैं।

इन कठिन परिस्थितयों में यान जेपांस्की एक विशिष्ट पद प्राप्त करने में सक्षम था–एक स्वतंत्र समाजशास्त्री के रूप में एक सत्तावादी सरकार में शिक्षा और सामाजिक नीतियों के विषय में सलाह देने की स्थिति ने उसे इस निराशापूर्ण समय में पब्लिक समाजशास्त्र को व्यवहार में प्रयुक्त करने का अवसर दिया। वह स्वयं को एक असम्बद्ध बुद्धिजीवी के रूप में नहीं देखते थे, अपितु एक अनुसंधानकर्त्ता के रूप में वर्तमान सामाजिक समस्याओं और उनके संभावित समाधान प्रस्तुत करने में वे स्वयं को अत्यधिक जुड़ा हुआ महसूस करते थे। राजनीतिक जीवन में अपने प्रभाव के कारण जेपांस्की ने अनेक महत्वपूर्ण पोलिश वैज्ञानिकों की विदेश यात्राओं को संभव बनाया। वे सार्वजनिक संस्थाओं को प्रिंटिंग पेपर उपलब्ध कराने के लिए भी संघर्षरत थे ताकि अनेक समाजशास्त्री और अन्य बुद्धिजीवी अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर सकें। वह, यहां तक कि, सामाजिक प्रतिरोध में भी संलग्न रहे, जोकि स्टालिन युग में बहुत मुश्किल था, इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए, 1954 में, सेंसरशिप के विरूद्ध विरोध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 34 बुद्धिजीवियों में से वह एक थे, हालांकि प्रथम गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया।

वे एक व्यापक रूप से पढ़े जाने वाले पत्रकार व स्तंभकार थे। राजनीतिक पद पर होने के कारण उन्होंने सत्ता की सीमित आलोचना की। वे अपने प्रसिद्ध लेखनों के माध्यम से जनता तक पहुंचे और ध्रुवों की एक समग्र पीढ़ी के मस्तिष्क और दृष्टि कोणों पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस तरह इन्होंने सार्वजनिक बहस में समाजशास्त्र की कुछ बुनियादी अवधारणाओं की बहस को आरम्भ किया। एक ऐसे समय में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रत अनिश्चित थी सार्वजनिक बहस/चर्चा के आयोजन ने थोड़ा बहुत स्पेस तैयार किया। हालांकि, समाजशास्त्र के इस व्यावहारिक रूप का आज ज्यादा महत्व है–उनकी मृत्यु के 10 साल बाद जेपांस्की को सभी जगह याद किया जाता है परंतु पोलैंड ने उन्हें भुला दिया। वर्तमान समस्याओं पर केन्द्रित अपने सैंकड़ों प्रकाशनों के बावजूद भी वे कोई प्रभावी चिंतन सम्प्रदाय अपने पीछे छोड़कर नहीं गये। उनकी जन्म शताब्दी (100वीं वर्षगांठ) के अवसर पर पोलिश विज्ञान एकेडमी (एकेडमी ऑफ साइंसेज) और पोलिश समाजशास्त्र परिषद के द्वारा घटनाओं और सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया, हालांकि उनके नाम से समाज विज्ञान के समकालीन विद्यार्थी परिचित नहीं है।

उनकी संतुलित गतिविधियों से यह सिद्ध होता है कि एक अत्यधिक अलोकतांत्रिक प्रणाली में भी, सार्वजनिक समाजशास्त्र के लिए स्थान बनाया जा सकता है। हालांकि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी : आन्तरिक राजनीति की एक श्रृंखला में फंस गये और उन्हें अनेक असहज समझौते करने पड़े। ■

> पोलिश उच्च शिक्षा पर नव्य–उदारवाद का कब्जा

डारियस जेमिलनियाक एवं **कैरोलिना मिकोलायेवस्का**, कोजमिंस्की विश्वविद्यालय, वारसॉ, पोलैण्ड

विद्यार्थी और अध्यापक पौलेण्ड में पीएच.डी. विद्यार्थियों द्वारा स्थापित एक गैरसरकारी संगठन न्यू ओपनिंग आफ द यूनिवर्सिटी (NOU) द्वारा पैलिश शैक्षणिक जगत पर शोध करने के लिए सभा करते हुए।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि समकालीन पोलिश शिक्षाविदों की स्थिति की चर्चा ग्लोबल डायलॉग के अंक में की जा रही है। ग्लोबल डायलॉग के 2.4 अंक में पब्लिक (सार्वजनिक) समाजशास्त्र लैब के सदस्यों ने पोलिश विश्वविद्यालयों[1] के उदारवादी सुधार की ओर इशारा किया था। पिछले सात वर्षों में पोलिश उच्च शिक्षा प्रणाली में बहुत से बदलाव हुए इस आधार पर कि पोलिश शिक्षाविदों को विश्वस्तरीय मानकों को पूरा करना चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण नजर आता है और आमतौर पर इसका समर्थन भी किया गया, जबकि वास्तविक परिणामों में अनेक नकारात्मक/प्रतिकूल प्रभावों को भी उत्पन्न किया जिसने स्थिति को बेहतर करने के बजाय, खराब ही किया।

पोलिश शिक्षाविदों की कठोर स्थिति को समझने के लिए यह उचित होगा कि संरचनात्मक रूपांतरण के कुछ प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त चित्रण करें जिन्हें हम विशिष्ट रूप से समस्यामूलक मानते हैं। यह सामान्यतः तब हुआ जब पोलैंड में लीना कोलारस्का–बोबिंस्का ने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में पद संभाला, जो कि समाजशास्त्र की प्रोफेसर और यूरोपियन संसद की एक भूतपूर्व सदस्य थीं। वह इस बात पर जोर देती है कि वे अपने पूर्ववर्ती की नीतियों को ही जारी रखेंगी।

शैक्षणिक क्षेत्र में सकल घरेलु उत्पाद (जी. डी. पी.) का केवल 0.4% अनुदान पोलैंड को यूरोपीय संघ के देशों में अंतिम पादान पर ले आता है। हमें इस पक्ष पर भी बल देना चाहिए भले ही ध्रुवों ने यूरोपीय संघ शोध अनुदान तक अपनी पहुँच बना ली है फिर भी वे बहुत

>>

कम ही इसके लिए आवेदन करते हैं और बहुत कम सफल हुए हैं। हाल के बदलावों का मतलब है कि अधिकांश सार्वजनिक संसाधनों को नये स्थापित अनुदान संस्थानों को सौंप दिया गया जैसे राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र (NCN) बजाय अकादमिक संस्थानों को सीधे भेजने के। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर अनुदान प्रणाली ने अधिकारिक तौर पर योग्यता और व्यवसायिकता को बढ़ावा देकर क्षेत्रों के बीच असमानतों में वृद्धि की है। अनुदान का अधिकांश हिस्सा राजधानी वारसॉ द्वारा नियंत्रित माजोविया प्रांत के शोधकर्ताओं को आवंटित किया जा रहा है।

यह असमानता संगठन द्वारा पीएच. डी. अनुदान के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से प्रबल होती है, शोध प्रस्ताव के समग्र मूल्यांकन का 20% एक शोधार्थी के पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) की उपलब्धियों पर निर्भर करता है, उन शोधार्थियों को भारी लाभ दिया जा रहा है जो सबसे प्रतिष्ठित/असाधारण प्रोफेसरों के साथ शैक्षणिक केन्द्रों में प्रवेश करते हैं। पिछले 20 वर्षों में पीएच.डी. उम्मीदवारों की संख्या में 15 गुना वृद्धि होने से दुर्लभ संसाधनों हेतु आयोजित इस प्रतियोगिता में और भी तीव्र वृद्धि हुयी है। इसी समय परंतु इसके पूरे होने की दर अधिकतम[2] केवल दोगुनी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएच.डी. उम्मीदवारों की केवल थोड़ी सी संख्या ही छात्रवृत्ति प्राप्त करती है जबकि असंख्य विश्वविद्यालयों में अनुसंधान व शिक्षण सहायता राशि को समाप्त कर दिया गया जिसके कारण स्नातक छात्र एक नये अनिश्चित वर्ग 'डिस्पोजेबल शिक्षाविदों'[3] में परिवर्तित हो रहे हैं।

इस प्रक्रिया ने पोलैंड में समग्र जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए बहुत कुछ किया जिसका शैक्षणिक समुदाय की संरचनात्मक स्थितियों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। स्कूल छोड़कर विश्वविद्यालय जाने वालों के अनुपात में 9.8% की वृद्धि हुई जो कि उत्तर–समाजवादी परिवर्तन की सीमा का लगभग 50% है। यह विश्व की उच्चतम दरों में से एक है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों का सार्वजनिक अनुदान छात्रों की संख्या पर निर्भर करता था। जिन्हें अनुसंधान हेतु केवल छोटी–सी राशि दी जाती थी (सीमित समय के लिए अनुदान एवं अधिक स्थायी नौकरी की संभावना का प्रस्ताव नहीं था)। अब पोलैंड असफल होने वाले असंख्य छात्रों के कारण जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है, विश्वविद्यालय वित्तीय संकटों का सामना कर रहे है, इनसे मुख्यतः वे विभाग प्रभावित हुए हैं, जिनमें छात्रों की भर्ती मुश्किल थी/कम हुयी थी। उत्तर पूर्वी पोलैंड में बेलीस्टॉक में दर्शनशास्त्र पाठ्यक्रम को बंद करने और इसके स्थान पर संज्ञानात्मक विज्ञान के एक संकाय को खोलने पर हाल ही में ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसमें अधिकांश छात्रों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं हैं।

समग्र पोलैंड, सार्वजनिक वित्त पोषित दर्शनशास्त्र संस्थान (और साथ ही अन्य मानविकी विभाग) दूसरे प्रमुख (मानविकी विषयों) विषयों के भुगतान के लिए प्रारम्भ से ही विशेष कठिनाईयों का सामना कर रहा है–मानविकी कार्यक्रमों को सामान्यतः दूसरे प्रमुख के रूप में चुना जाता है, समृद्ध छात्र इन विषयों को अब छोड़ चुके हैं।

ऐसे समय में, अनुसंधान की गुणवत्ता के लिए प्रयास के अधिकारित सूत्र पर शायद ही कभी कोई विश्वास करेगा। उदाहरण के लिए, विज्ञान मंत्रालय ने एक शोध मूल्यांकन अभ्यास शुरू किया जो कि निजी कंपनी थामसन रयूटर की 'जर्नल प्रशस्ति पत्र रिपोर्ट' के स्वामित्व और पद्धतिशास्त्रीय संदेह पर व्यापक रूप से आधारित पत्रिकाओं की रैंकिंग करता था। यदि जे सी आर की रैंकिंग उचित है तो इसमें पोलिश की पुनरावृत्ति शैक्षणिक योग्यता के मूल्यांकन को विकृत करती है। जे सी आर की सूची के बाहर की पत्रिकाओं को अपारदर्शी तरीके से चुना गया है, अनेक गुणवत्ता केन्द्रों की उपेक्षा कर दी गयी या उन्हें हटा दिया गया, कानून और चिकित्सा के माध्यम से रैंकिंग प्रदान करने के प्रयास विशेष रूप से जीवविज्ञान, समाजशास्त्र, शास्त्रीय अध्ययनों के क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से असंभव हो गये। अन्य दूसरे प्रकार के प्रकाशनों को निम्न स्तर का माना जाता है और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस में प्रकाशित मोनोग्राफ उतना ही उपयोगी है जितना किसी निरर्थक प्रेस में छपी एक पुस्तक, अगर वह अंग्रेजी में है तो। विशेष रूप से मानविकी और समाज विज्ञानों के लिए ऐसी नीति के प्रभाव विनाशकारी हैं और उपेक्षित हैं।

अनेक सुधार, शैक्षणिक उत्पादन के मूल्यांकन के लौहतंत्र (नौकरशाही) सहित गुणवत्ता के बजाय नियंत्रण की आवश्यकता से प्रेरित हैं। उदाहरण के लिए, सभी संकायों को व्यापक पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जिसका मूल्यांकन राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार शिक्षण प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य यह नहीं है कि 'संकाय सदस्य क्या करते हैं' की रिपोर्ट की जाये अपितु यह सुनिश्चित करे कि वे जो भी करें अर्थपूर्ण करें।

शैक्षणिक समुदाय में गुणवत्ता की उदारवादी वार्ता ने व्यावहारिक अनु–संधान की प्रशंसा की उन क्षेत्रों (दर्शनशास्त्र और समाजशास्त्र सहित) को हतोत्साहित किया, जो तत्काल लाभ नहीं दिलाते। परंतु गुणवत्ता की यह अवधारणा भी पूर्णतः अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए, पोलैंड में गैर–सार्वजनिक विश्वविद्यालय–1989 के बाद स्थापित किए गये और गैर–लाभकारी संस्थान के रूप में संचालित कक्षाओं के लिए राज्य अनुदान को प्राप्त नहीं कर सके। यद्यपि सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तुलना में उनकी शिक्षण और अनु–संधान की गुणवत्ता बहुत अधिक उच्च स्तर की होती है और उनकी कक्षाएं भी बहुत प्रभावी होती है। इन सभी से पता लगता है कि सुधारों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार नहीं होता, बल्कि शैक्षणिक समुदायों को शक्तिहीन करना होता है।

पोलिश शैक्षणिक समुदाय की स्थिति बहुत चिंताजनक है परंतु यह विशिष्ट नहीं है–विश्वव्यापी विद्यालय समान चुनौतियों का और संकटों का सामना कर रहे हैं। जब तक शैक्षणिक समुदाय सामान्य रूप से और समाज वैज्ञानिक विशिष्ट रूप से उच्च शिक्षा के संगठन के लिए एक वैकल्पिक मूर्त व सृजनात्मक प्रस्ताव तैयार नहीं करते, जिसमें सुधारकों के मुद्दों को संबोधित करते हुए और वर्तमान परिवर्तनों के विनाशकारी परिणामों की उपेक्षा करते हुए सम्मिलित न किया जाये, स्थिति केवल बुरी होती जायेगी। वस्तुतः कार्यवाही करने का समय पहले ही बीत चुका है। ■

1 Mierzejewski M., Mikołajewska K., Rozenbaum J., "One or Many Sociologies? A Polish Dialogue," *Global Dialogue* 2:4, May 2012.

2 Michalak D., "Studia doktoranckie w Polsce – łatwo zacząć, trudniej skończyć," March 2013: http://noweotwarcie.wordpress.com/2013/03/11/studia-doktoranckie-w-polsce-latwo-zaczac-trudniej-skonczyc/

3 Editorial: "The disposable academic," *The Economist*, 2010, retrieved from http://www.economist.com/node/17723223

> उच्च शिक्षा में सुधार के संदर्भ में एक खुला पत्र

सार्वजनिक समाजशास्त्र प्रयोगशाला (पब्लिक सोशियोलॉजी लैब), वारसॉ विश्वविद्यालय तथा क्राकोव (पोलैण्ड) के यागीलोनियन विश्वविद्यालय के आलोचनात्मक अनुभाग द्वारा पौलिश समाजशास्त्र परिषद के समक्ष प्रस्तुत

सितम्बर 2003 में पोलिश समाजशास्त्र परिषद की 15 वीं कांग्रेस स्टेचिन में आयोजित हुई। छात्र चर्चाओं की एक श्रृंखला के बाद, सार्वजनिक समाजशास्त्र लैब ने उच्च शिक्षा में परिवर्तनों के संदर्भ में एक खुला पत्र जारी किया। इस पत्र को कांग्रेस में पढ़कर सुनाया गया और व्याख्याताओं की तरफ से इस पत्र पर बड़ी मात्रा में प्रतिक्रियाएँ हुयीं। जनवरी 2014 में वारसॉ में 'समकालीन पोलैंड में समाजशास्त्र और समाजशास्त्री' विषय पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें एकमात्र छात्र प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया था। यहाँ हम एक पत्र प्रस्तुत कर रह हैं जो कि छात्रों की समस्याओं के निदान तथा विश्वविद्यालय के संकट के संभावित समाधानों को प्रस्तुत करता है। इस पत्र को क्रिस्टोफ गुबान्स्की ने तैयार किया।

उच्च शिक्षा सुधारों की दुविधाओं पर क्राकोव में युवा समाजशास्त्रियों की कांग्रेस में चर्चा करते हुए पौलिश विद्यार्थी।

देवियो, सज्जनों और प्रिय शिक्षाविदों! हमारे पास शिक्षा जगत से सम्बद्ध मुद्दों पर चिंतन करने वाले छात्रों का एक समूह है। हम समाजशास्त्र के सभी छात्रों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का तो दावा नहीं करते, हालांकि वारसॉ विश्वविद्यालय तथा क्राकोव में यागीलोनियन विश्वविद्यालय के छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में हम शैक्षणिक जगत में समकालीन परिवर्तनों के विषय में हमारी जीवंत चर्चाओं का प्रचार करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि छात्र उदासीन नहीं हैं, जैसा कि सामान्यतः आरोप लगाया जाता हैं। हमने इन मुद्दों पर बैठकों व सेमीनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जिसके माध्यम

>>

से व्यापक प्रचार[1] को आकर्षित किया, जो यह दर्शाता है कि छात्र अपनी आवाज को खुद बुलंद करना चाहते हैं बजाय इसके कि दूसरे लोग उनके लिए अपनी आवाज उठाएें।

हमने यह अनुभव किया है कि उच्च शिक्षा में सुधार के विषय में सार्वजनिक बहस किस प्रकार वैज्ञानिकों की आवाज की उपेक्षा करती है। विज्ञान और उच्च शिक्षा मंत्रालय, जो मध्यस्थ के रूप में काम करता है, वैज्ञानिकों के मत देने के अधिकार की उपेक्षा करता है, उनके साथ आधुनिकीकरण के प्रगतिशील परिवर्तनों की बजाय रूढ़िवादी विपक्ष की तरह व्यवहार करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि विशेषा–धिकारों को सुरक्षा देने के लिए सुधारों का प्रतिरोध किया जाता है जो कि एक व्याधिकीय व्यवस्था को उत्पन्न करता है, जो यह बताता है कि किस प्रकार समकालीन शैक्षणिक समुदाय को प्रस्तुत किया जाता है। उसी समय सुधार के प्रणेता/प्रायोजक यह दावा करते हुए इसे वैधता प्रदान करते हैं कि यह छात्रों के हितों में वृद्धि करता है, उन्हें एक कठोर शिक्षा प्रणाली से मुक्त करता है परंतु छात्रों के हित मात्र एक काल्पनिक वस्तु बने हुए हैं और उनकी आवाज को सार्थक पहचान कभी नहीं मिल पाती। छात्र संगठन प्रतिदिन की उदासीनता भरी व्यक्तिगत सभाओं से ऊपर उठने में छात्रों की व्यापक मदद करते हैं और अक्सर उन पर वस्तुनिष्ठ चिंतन या अपने दावों को स्पष्ट न कर पाने की कमी होने का आरोप लगाया जाता है।

सुधार की चर्चा (संभवतः) असंगत विपक्ष पर बल देती है–'बाजार बनाम शिक्षा जगत', जो कि वैज्ञानिकों के विरोध के दो स्वरूपों को उत्पन्न करती है। पहली रणनीति में, वैज्ञानिक इस तर्क के साथ अपनी स्थिति का बचाव करते हैं कि वे नवीन सार्वजनिक प्रबंधन और नव्य उदारवादी विचारधाराओं से निर्देशित बाजार व्यवस्था का समर्थन करते हैं, जो कि मंत्रालय द्वारा स्थिति की स्वीकृत परिभाषा है। दूसरी रणनीति, रूढ़िवादी स्थिति का बचाव करती है जिसका अर्थ एक आदर्शवादी समुदाय व उससे सम्बद्ध अभिजनवाद व संस्थागत स्वायत्तता का समर्थन करने से है। परंतु यहाँ स्वायत्तता का क्या अर्थ है? यहाँ स्वायत्तता का अर्थ बाजार व राज्य की शक्तियों की स्वायत्तता से है, परंतु ऐसी स्वायत्तता अव्यवहारिक है। ऐसा रूढ़िवादी बचाव मंत्रालयिक चर्चा के लिए फायदेमंद है जो कि वैज्ञानिकों को सामंती प्रतिक्रियावादी की संज्ञा देता है।

'शैक्षणिक धोखाधड़ी' के ऐसे कपटी आरोपों और प्रत्यारोपों के स्थान पर हम आधुनिक विश्वविद्यालय की विशेषताओं और आवश्यकताओं के विषय में पारस्परिक सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने की पेशकश करते हैं। हमारा प्रस्ताव है कि शिक्षक छात्रों को अपनी प्रथम जनता (पब्लिक) माने और समाजशास्त्रीय ज्ञान को अकादमिक क्षेत्र से व्यापक जनता को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित करें या उसका सीधा प्रसारण करें। एक प्रदाता–ग्राहक सेवा के प्रस्तावित सरकारी तर्क के विपक्ष में विद्वान अभी भी सत्ता पर नियंत्रण करते हैं और पेशेवर समाजीकरण की प्रक्रिया को तय करते हैं। हमें अपने व्याख्यानों में अपनी सोच व शिक्षण में समाजशास्त्रीय ज्ञान के प्रयोग की विविधता को सम्मिलित करना चाहिए और न कि केवल परम्परागत तरीके से ही पढ़ाते रहना चाहिए। पोलैण्ड व यूरोप में उच्च शिक्षा के बारे में विचार विमर्श में समान सहभागिता हेतु एक सामान्य संघर्ष के माध्यम से ज्ञान के सामूहिक उत्पादन के विकास का उदाहरण लिया जा सकता है।

हम मानते हैं कि स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों में जो सुधारों का प्रमुख लाभार्थी होने का दावा करते है–'सामंती विश्वविद्यालय के प्रतिक्रियावादी आक्षेपों' के रूप में प्रतिरोध की अवसरवादी व्याख्या को चुनौती देने की क्षमता है। छात्रों की सहभागिता में वृद्धि के हमारे प्रयासों के बावजूद अब तक उन्हें अपनी क्षमता का अनुभव नहीं हुआ था। एक समस्या यह भी है कि छात्रों को सुधारों का पर्याप्त ज्ञान नहीं है (जिसे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं) परंतु उनके पास अपने व्याख्याताओं/शिक्षकों के नेतृत्व और समर्थन का अभाव भी है जिनके साथ वे अपने प्रतिदिन की गतिविधियाँ और सामान्य समस्याएं बाँटते हैं। बाह्य विशेषज्ञों को सार्वजनिक चर्चा के क्षेत्र को सौंपने का अर्थ है कि अनुसंधानकर्त्ता और छात्र दोनों का नुकसान या क्षति होना है। जब शिक्षाविद् विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्थितियों पर भी अपने प्रभाव को खो देते हैं तब छात्र उनकी क्षमता को सामाजिक परिवर्तन के सम्भावित उपकरण के रूप में नहीं स्वीकारते और वे उदासीनता का शिकार हो जाते हैं।

शैक्षणिक परिवेश की वर्तमान स्थिति के बजाय, जो कि मंत्रालय की प्रभावी स्थिति पर बल देती है, हम व्याख्याताओं/शिक्षकों, स्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों के गठबंधन की बात करते हैं। हम मानते हैं कि पोलिश समाजशास्त्र परिषद समाजशास्त्र के भविष्य के लिए सहभागिता व उत्तरदायित्व का विस्तार करने में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। यह पत्र चर्चा करने का एक आमंत्रण है, सहयोग करने व ठोस कार्यवाही करने की एक प्रस्तावना है। इसलिए हम अपने शिक्षकों से अपील करते हैं कि वे हमारे सामान्य हितों की संयुक्त कोशिश में हमारी संस्था को पहचान दें। ■

[1] उदाहरण के लिए, 'भविष्य का समाजशास्त्र–परवाह करने वाले छात्रों के बीच चर्चा' विषय पर युवा समाजशास्त्रियों की तृतीय कांग्रेस (क्राकोव, जून 2012), उच्च शिक्षा में परिवर्तन का सामना कर रहे छात्र समुदाय की दुविधाएं : प्रतिरोध या अनुकूलन' विषय पर युवा समाजशास्त्रियों की चतुर्थ कांग्रेस (क्राकोव, जून 2013), 'शिक्षण प्रणाली में छात्र संस्थाएं' विषय पर समर क्रिटिकल मैराथन (राब्का, जून 2013)।

> वैश्विक संवाद का टर्किश दल

हमने अपनी अनुवाद की यात्रा जी.डी 2.4 से प्रारम्भ की। शुरुआत में हमें इस साहसिक कार्य को करने के लिए लोगों को जोड़नें तथा संगठित करने में काफी मुश्किलें हुईं। लेकिन अब संपादकीय दल कमोबेश स्थापित हो गया है। हम टर्की के विभिन्न शहरों मे रहते हैं तथा कार्य करते हैं। यथेष्ठ भौगौलिक दूरियों के बावजूद जो कि हमें अलग करती है हम अपने श्रम को डिजिटल मीडिया के द्वारा सक्रिय रखते हैं। यह वैश्विक संवाद के संपादकीय दल का संक्षिप्त इतिहास है। नीचे दिये गये विवरण से आप हमें भली प्रकार से जानेंगे। ■

डॉ. आयतुल कासापोग्लु वर्तमान में अंकारा विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर (आचार्य) हैं तथा उनकी खास रुचि आपदा के समाजशास्त्र, स्वास्थ्य तथा बिमारियों के समाजशास्त्र, समाजविज्ञान की पद्धतियाँ, तथा सामजिक समस्याओं के अध्ययन में है।

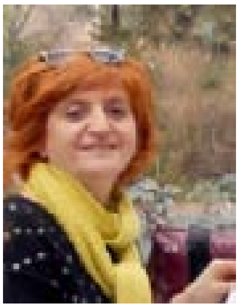

डॉ. निलय काबुक काया वर्तमान में अंकारा विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर (आचार्य) हैं तथा उनकी खास रुचि लैंगिक मुद्दों तथा विकास के समाजशास्त्र में है।

डॉ. गुनर इरटोंग नें बिलकेन्ट विश्वविद्यालय से 2003 में कला संकाय में स्नातक किया तथा अंकारा विश्वविद्यालय से 2005 में एम.ए. दोनो ही अर्थशास्त्र से। 2011 में आपने समाजशास्त्र में अपने शोधग्रन्थ *स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास और रोगी–चिकित्सक रिश्ते* पर पीएच.डी की उपाधी अंकारा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डॉ. इरटोंग ने 2007 से 2012 तक टर्किश स्वास्थ्य मंत्रालय में काम किया। वर्तमान में आप टर्किश साइंटिफिक एण्ड टेक्नोलोजिकल रिसर्च काउन्सिल के सोशल स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च एण्ड डवलपमेंन्ट युनिट में कार्यरत हैं। आपकी खास शोध अभिरुचियों में शामिल हैं स्वास्थ्य प्रणाली पर विश्वास, स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा, तथा आपदा के समाजशास्त्र, स्वास्थ्य तथा बिमारियों के समाजशास्त्र, समाजविज्ञान की पद्धतियाँ, तथा हाल ही में बच्चों पर खतरे।

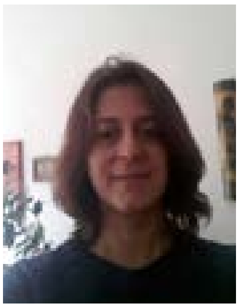

डॉ. जुहाल योन्का ओडाबस नें अंकारा विश्वविद्यालय से 2000 में स्नातक किया तथा इसके बाद मिडिल ईस्ट टेक्निकल विश्वविद्यालय से एम.ए.। 2009 में आपने समाजशास्त्र में अपने शोधग्रन्थ *आपदा प्रबन्धन तथा लिंग–भेद* पर अंकारा विश्वविद्यालय से पीएच.डी की उपाधी प्राप्त की। वह वर्तमान में अतातुर्क विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर (उप–आचार्य) हैं तथा उनकी खास रुचि स्वास्थ्य तथा बिमारियों के समाजशास्त्र, आपदा के समाजशास्त्र, तथा लैंगिक मुद्धों के समाजशास्त्र में है।

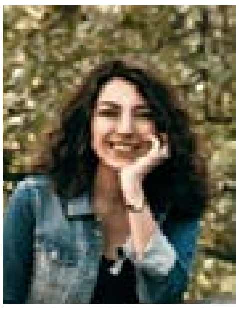

गिजेम गुनर नें हैक्टैपे विश्वविद्यालय, अंकारा से 2013 में स्नातक किया। अभी वह समाजशास्त्र से एम.ए. करने की योजना बना रही है। उसकी रुचियां हिंसा के प्रश्नों पर तथा इसके वर्ग तथा नृजातियता के साथ अंत:प्रतिच्छेदन पर रहीं हैं। वह वैश्विक संवाद के संपादकीय दल के साथ जनवरी 2013 से जुड़ी हुई है तथा वर्तमान में एक निजी संस्थान में आन्तरिक अंकेक्षक के पद पर कार्यरत है।

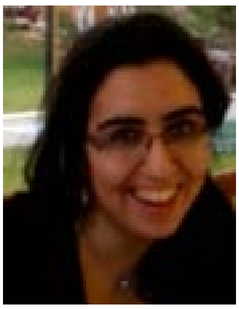

जैनप बैकल नें इस्ताम्बुल के बिल्गी विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान विभाग से स्नातक किया। उसने समाजशास्त्र से अपनी एम.ए. की उपाधि मिडिल ईस्ट टेक्निकल विश्वविद्यालय से ली है। उसके शोधग्रन्थ, *टर्की में अमेरिकन पहचान की निर्मितिः येसिल्कोय प्रकरण* को 2013 में टर्किश सोशल साईन्स एसोशिऐशन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। वह अभी अपनी पीएच.डी. मिडिल ईस्ट टेक्निकल विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में कर रही है। उसका कार्यक्षेत्र नृजातियता, पहचान, सांस्कृतिक अध्ययन तथा कला का समाजशास्त्र है। उसकी रुचियां थिएटर आलोचना और नाट्य में भी है और वह इस्ताम्बुल विश्वविद्यालय के थिएटर आलोचना और नाट्य विभाग से लगातार कोर्स कर रही है। वह वैश्विक संवाद के संपादकीय दल के साथ अक्टूबर 2012 से जुड़ी हुई है।